R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 03
01 से 15 नवम्बर 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

मिशन 2023 का घमासान

बागियों में उलझी भाजपा-कांग्रेस

बागी ही तय करेंगे हार और जीत का गणित

दलबदलुओं के सहारे तीसरा मोर्चा हरा-भरा

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

मुद्दा

9 | मुफ्त की रेवड़ियां नई सरकार पर...

मप्र सहित देशभर में यह परंपरा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि चार साल सरकार में रहने के बाद भी चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे कर देती हैं। इसे ही राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज...

राजपथ

10-11 | मिशन-2023 महिलाएं...

मप्र के इतिहास में पहली बार भाजपा और कांग्रेस ने महिला मतदाताओं पर जमकर सौगातों का प्यार बरसाया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार चाहे जिस भी पार्टी की बने लेकिन प्रदेश की सवा करोड़ से ज्यादा...

मेट्रो

18 | हाईटेक होगी मेट्रो

भोपाल और इंदौर मेट्रो कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होगी, जिसमें अनअटेंडेंट आब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डिरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ट्रेन के संचालन...

कुपोषण

20 | 19 प्रतिशत बच्चे अल्प पोषित

मप्र में कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन वह उतना प्रभावी नहीं हो रहा है, जितना सरकार को उम्मीद है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की रिपोर्ट में मप्र में करीब 78 हजार बच्चों में कुपोषण मिला है। ये वो बच्चे हैं, जो रोजाना...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनावी समर में प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में 3832 अभ्यर्थियों द्वारा 4359 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इनमें से 460 प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के हैं, जबकि 3372 वे हैं, जो केवल खेल बिगाड़ेंगे। इनमें वे नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने भाजपा-कांग्रेस से बगावत कर तीसरे मोर्चे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की है। ये दलबदलू दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे। इस बार भाजपा-कांग्रेस में इस कदर बगावत हुई है कि उनसे...

राजनीति

30-31 | ब्रांड मोदी को रोकने का...

एक दौर में तमाम महापुरुष और नेता जाति उन्मूलन की बात करते थे, आज देश की समूची राजनीति ही जातियों को गिनने की धुरी पर आकर टिक गई है। बिहार की जातिवार गणना के आंकड़े सामने आने के बाद जो हलचल मची है वह देश के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक...

महाराष्ट्र

35 | मराठा आरक्षण के पीछे की...

देश में आम चुनाव से पहले जातिगत जनगणना जितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भी उतना ही अहम है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आग सुलग गई है। 30 अक्टूबर को अचानक मराठा...

बिहार

38 | घोटालों को दबाने का...

बिहार में जाति जनगणना के बाद तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों में जानबूझकर कुछ जातियों को कमतर दिखाने का आरोप तो लग ही रहा है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का पांसा अपने शासनकाल में...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

चुनाव में पैसे के छिड़काव से वोट पैदा होता है?...

किसी शायर ने लिखा है...

न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे,
पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे।

चुनावी माहौल में शायर का यह शेर कुछ हद तक मतदाताओं पर सटीक बैठता है। क्योंकि चुनाव कोई भी हो, राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा दमखम लगा देती हैं। अंतिम समय में तो साम, दाम, दंड, भेद सबका सहारा लिया जाता है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि चुनाव में पैसे के छिड़काव से वोट पैदा होता है। शायद यही वजह है कि रोजाना करोड़ों रुपए नगद और सोने-चांदी के जेवर या अन्य सामान जब्त किए जा रहे हैं। अपने देश में पैसा और शराब बांटकर चुनाव जीतना अखिल भारतीय बीमारी है जो बढ़ती जा रही है। इस बार 2012 के चुनाव की तुलना में तीन गुना से ज्यादा रुपया और शराब चुनाव आयोग ने जब्त की है। जिस समय चुनाव विशेषज्ञ टीवी चैनलों पर बैठकर जाति, मुद्दे, विचारधारा, नेताओं के व्यक्तित्व वगैरह के आधार पर अनुमान लगा रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त साजिशन लालची और भ्रष्ट बनाया जाता वोटरों का बड़ा तबका किसी और हवा में बहकर फैसला कर रहा होता है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यह चलन लोकगीतों में झलकने लगा है। इसे बढ़ावा देने के कॉम्पिटीशन के चलते राजनीतिक दलों के लिए भी अधिक चुप रह पाना मुश्किल हो गया है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा है कि उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अलग से एक स्पष्ट प्रावधान कर वोटरों को घूस देने की स्थिति में चुनाव रद्द करने का अधिकार दिया जाए। इससे पहले भी आयोग दो बार यह मांग उठा चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया। चुनाव में वोटर को लालच देने का रिवाज पुराना है, लेकिन उदारीकरण के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ी है। इस दौर में आर्थिक अपराध ही मुख्य अपराध हो गए हैं, गैर कानूनी तरीकों से पैसा बनाने वाले नौदौलतिए वीआईपी के कवच के पीछे खुद को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के टिकट खरीदकर बड़ी तादाद में चुनाव में उतर रहे हैं। हर पार्टी में पैठ गए इस नौदौलतिया तबके को वोटर का दिमाग फेरने के लिए पैसा फेंकने के सिवा और कुछ नहीं आता। राजनीतिक पार्टियों के लिए ऐसे गूंगे प्रत्याशी बहुत काम के साबित होते हैं क्योंकि एक बार चुनाव जीत जाने के बाद वे हमेशा हां में हां मिलाते हैं, कोई समस्या नहीं खड़ी करते, उनके समर्थन का मैनेजमेंट आसान होता है। वोटर एक ही चुनाव क्षेत्र में ऐसे सभी प्रत्याशियों से बेहिचक पैसे लेता है, ऐसा करने के पीछे उसका जो तर्क है वह हमारे लोकतंत्र की पोल बहुत मार्मिक ढंग से खोलता है। ऐसे वोटरों का सादा-सा तर्क होता है, ये एमपी, एमएलए बनकर करोड़ों बटोरेंगे। हमको तो यही हजार दो हजार और दस दिन तक पीने-खाने को मिलता है। चुनाव ही एक ऐसा मौका है जब नेता बनने चले अमीरों की थैली खुलती है, हम क्यों चूकें। चुनाव नजदीक आते ही काले धन का इस्तेमाल भी तेज हो जाता है, अलग-अलग जगहों में करोड़ों रुपए कैश पहुंचाया जाता है, जिसे चुनाव में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पुलिस भी तैयार रहती है और संदिग्ध दिखने वाले लोगों और वाहनों की चेकिंग होती है, इसके अलावा पुलिस के पास मुखबिर भी होते हैं। जिनकी मदद से वो इस कैश को पकड़ लेते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 3, पृष्ठ-48, 1 से 15 नवंबर, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

मजदूर मजबूर क्यों?

मनरेगा योजना से लाखों मजदूरों को लाभ मिलता है। इस योजना के तहत कई राज्यों में भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसका खामियाजा गरीब मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। सरकार को इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करनी होगी, जिससे मजदूरों को अपना हक मिल सके।

● **राजू शिवहरे,** ग्वालियर (म.प्र.)

कैसे रुकेगा अवैध खनन?

प्रदेश में नर्मदा, चंबल, सोन सहित जितनी नदियां हैं उनमें अवैध रेत का खनन जोरों पर है। सोन नदी में रेत उत्खनन व परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद रेत की निकासी पर रोक नहीं लग पा रही है। इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

● **सृष्टि मिश्रा,** इंदौर (म.प्र.)

मप्र में अपराध होगा शून्य

मप्र में शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री दिन-रात प्रयास कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों से समाज को दूर रखने के लिए प्रदेश में कई कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम अपराध शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

● **सूरज यादव,** भोपाल (म.प्र.)

विधानसभा चुनाव में मोदी ही चेहरा

5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा हैं। ऐसे में इन चुनावों में लड़ाई मोदी बनाम कमलनाथ, मोदी बनाम बघेल, मोदी बनाम गहलोत, मोदी बनाम केसीआर ही होने वाला है। इन विधानसभा चुनावों का परिणाम मिला-जुला हो सकता है। फिलहाल मप्र में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मतदाताओं में भारी आक्रोश है और सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी रुझान इस बार सभी क्षेत्रों में विधायकों के खिलाफ है। कांग्रेस के प्रति लोगों में यह सहानुभूति भी है कि उसकी सरकार भाजपा ने गिरा दी थी। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की स्थिति बेहतर कही जा सकती है।

● **अनिल सेन,** जबलपुर (म.प्र.)

कांग्रेस को मजबूत होना होगा

कांग्रेस की स्थिति देशभर में कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस को अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए मजबूत विपक्ष के तौर पर फिर से उभरकर सामने आना होगा। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई से होते हुए कोरोना से लेकर चीन और किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में यदि कांग्रेस उभरकर सामने आती है तभी वह एक मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में खड़ी रह सकती है।

● **राहुल सिंह,** नई दिल्ली (म.प्र.)

व्यर्थ न जाए खाना

अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकते हैं। उतना ही खरीदें जितना हमारे लिए पर्याप्त है। बेवजह खाद्य पदार्थों को जमा करना बंद कर दें। भोजन के महत्व को समझें। यह इंसान के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। अगली बार जब भी अपनी थाली में खाना बाकी छोड़ें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं इसी खाने की वजह से कोई भूखा सोने को मजबूर है।

● **मधु सिंह,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में...

देश में बढ़ते प्याज के दाम को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने एक वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा है। जेडीयू ने वीडियो में कैप्शन देते हुए लिखा कि दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में...जितना रो रहा है मोदी जी की महंगाई में। इस वीडियो में कहा गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले दिनों शतक बनाने से चूक गए लेकिन मोदी जी के राज में प्याज सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गया है। कीमतों के मामले में प्याज लगातार धुंआधार पारी खेल रहा है। लगातार जनता की आंखों से आंसू निकाल रहा है। महंगाई अब राष्ट्रीय विपत्ति बन चुकी है। क्या अमीर क्या गरीब सबको यह महंगाई डायन खाए जा रही है। इसमें आगे कहा गया है कि रसोई महंगी, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, यात्रा महंगी। अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वह है मोदी जी का भाषण। बिहार के कई जिले के बाजारों में प्याज की कीमत 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। थोक मंडी में भी प्याज की कीमत पिछले एक माह में बढ़ी है। थोक मंडी में सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्याज की कीमत 2050-2100 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो वर्तमान समय में 5100-5200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।

चार साल में सिर्फ तीन दौरे

कांग्रेस उप्र के अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में बयान दिया कि राहुल गांधी फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राहुल भी वास्तव में तैयार हैं? प्रश्न बेजा नहीं, बल्कि परिस्थितियां पूछ रही हैं। दरअसल, 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा की स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल ने अमेठी से पर्याप्त दूरी बना ली है। वह तब से सिर्फ तीन बार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में गए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली अमेठी संसदीय सीट 2004 में अपने बेटे राहुल गांधी के लिए रिक्त की थी। वह यह चुनाव और फिर 2009 और 2014 का भी चुनाव जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनौती दी और 2019 में हरा भी दिया। इस चुनौती को लेकर पहले से सतर्क राहुल केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, इसलिए वहां से जीतकर संसद पहुंच गए, लेकिन फिर शायद उनका अपनी पारिवारिक-पारंपरिक सीट से मोहभंग हो गया। इसका संकेत राहुल के रुख से मिलता है। राहुल 2019 में चुनाव हारने के थोड़े समय बाद ही 10 जुलाई, 2019 को अमेठी गए, लेकिन चुनावी समीक्षा के लिए। फिर लंबे समय यानी लगभग ढाई वर्ष बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र की याद तब आई, जब उप्र के विधानसभा चुनाव सिर पर थे।

मिशन 66 में कामयाब होंगे दिग्विजय

मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का मिशन 66 पर पूरा फोकस रहेगा। कांग्रेस ने हारी हुई सीटों पर कब्जा जमाने विशेष रणीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 66 सीटों पर फिर सक्रिय होंगे। दिग्विजय सिंह बड़ी जनसभा नहीं पूरे चुनाव में संगठन पर फोकस करेंगे। पिछले तीन से चार बार से लगातार हार रही सीटों की दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी मिली है। 66 सीटों पर 6 महीने पहले दौरा कर रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी थी। चुनाव के 15 दिन पहले एक बार फिर लगातार हारी हुई सीटों पर दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे। आने वाले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खातेगांव और बागली सीट पर बैठक करेंगे। खातेगांव और बागली सीट लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीती है। दोनों विधानसभा में मंडलम सेक्टर और बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह एकजुटता का संदेश देते नजर आएंगे। 2018 में दिग्विजय सिंह ने अलग-अलग गुटों के समर्थकों को एक साथ लाने के लिए पंगत में संगत कार्यक्रम चलाया था।

सहमति का सवाल है

भारत एक विशाल और बहुलता भरा देश है। इस देश पर इसके हर नागरिक का समान अधिकार है। इसलिए इस देश का नाम क्या हो, उसकी पहचान कैसी हो, आदि जैसे सवालों पर हर व्यक्ति की राय समान महत्व रखती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की एक समिति ने सुझाव दिया है कि पाठ्यपुस्तकों में अपने देश का नाम हर जगह इंडिया के स्थान पर भारत लिखा जाए। अगर इस सुझाव का एक खास संदर्भ नहीं होता, तो इस पर विवाद या असहमति की कोई गुंजाइश नहीं होती। आखिर भारतीय संविधान में इस देश का नाम भारत और इंडिया दोनों लिखा है। इन दोनों में से किसी नाम का उपयोग संवैधानिक, कानूनी और उचित है। लेकिन ध्यान अगर इन नामों के उपयोग के संदर्भ पर दें, तो एनसीईआरटी कमेटी की ये पहल विवादास्पद मालूम पड़ने लगती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर लिखी गई किताबों में इस बात का उल्लेख है कि संविधान सभा में देश के नाम पर तीखी और गरमागर्म बहस हुई थी।

सबसे बिगाड़ की नीति!

देर-सवेर भारतवासियों को नरेंद्र मोदी सरकार के कनाडा के 41 राजनयिकों को देश से निकालने के फैसले पर अडिग रहने के परिणामों पर अवश्य ही विचार करना होगा। कनाडाई राजनयिकों के लौटने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की तीखी प्रतिक्रिया पश्चिमी खेमे से भारत के बढ़ते दुराव का संकेत देती है। मुद्दा यह है कि क्या इस वक्त पर इस खेमे से ऐसा टकराव भारत के दीर्घकालिक हित में है? कुछ समय पहले तक भारत सरकार के रणनीतिकार कहते थे कि एक समय देश निगुर्टता- यानी किसी भी महाशक्ति की तरफ झुकाव ना रखने की नीति (नॉन-एलाइंग्ड) पर चलता था, जबकि मोदी सरकार सबके साथ रिश्ता रखने (ऑल-एलाइंग्ड) की राह पर चल रही है। मगर कुछ महीनों के भीतर चीजें इस तरह बिगड़ी हैं कि अब भारत सबसे टकराव मोल लेता नजर आ रहा है। बेशक चीन-पाकिस्तान से रिश्तों में कड़वाहट की लंबी पृष्ठभूमि है।

क्लेश बांटने वाले ने खोली शांति की दुकान

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक मेडिटेशन सेंटर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन लोगों को इस मेडिटेशन सेंटर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे हों या फिर अन्य हर किसी की जुबान पर यह सेंटर चढ़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सेंटर को जिसने खोला है, उनके बारे में ख्यात है कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में केवल क्लेश ही क्लेश बांटा है। यहां बता दें कि इस मेडिटेशन सेंटर को एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने खुलवाया है। उनके रिटायर होने के बाद कईयों की खुशियां लौटेंगी। ऐसे में साहब दूसरों को अब तक सताते रहे और अब शांति बांटने के काम में जुटेंगे। बता दें कि साहब अपने अड़ियल रुख के कारण हमेशा चर्चा में रहे हैं। वर्तमान में साहब प्रशासन की सबसे ऊंची कुर्सी पर आसीन हैं। साहब जबसे इस कुर्सी पर बैठे हैं, तबसे उनका रुख और कठोर हो गया है, जिसका खामियाजा प्रशासनिक गलियारे में अधिकांश अफसरों को भुगतना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में अधिकांश अफसर साहब द्वारा दिए गए क्लेश से प्रताड़ित हैं। यही नहीं साहब ने तो मंत्रियों तक को क्लेश देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब अपनी नौकरी के आखिरी क्षणों में साहब को शांति बांटने का भूत न जाने कहां से सवार हुआ है कि उन्होंने अपने निवास के पास ही मेडिटेशन सेंटर खोल रखा है। इसमें 50-60 लोगों की एंट्री होती है। शायद ये लोग साहब की शांति में शरीक होते हैं कि अब तो साहब शांति से रह सकें।

प्रेमी के लिए घर में कलह

इन दिनों एक राज्य पुलिस सेवा की महिला अधिकारी और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की प्रेम कहानी प्रशासनिक वीथिका में चटखारे लेकर सुनी और सुनाई जा रही है। आलम यह है कि मैडम का घर बड़े साहब भले ही आबाद कर रहे हों, लेकिन इस कारण उनके घर में दिन पर दिन कलह बढ़ती जा रही है। घर की चार दीवारी में होने वाली कलह अब बाहर सुनाई देने लगी है, जिससे कहा जा रहा है कि कभी भी मैडम का घर टूट सकता है। लेकिन इन बड़े साहब के प्रेम में डूबीं मैडम को इसकी तनिक भी फिकर नहीं है। इसके पीछे मैडम को करीब से जानने वाले कहते हैं कि मैडम को इसका अनुभव है। सूत्रों का कहना है कि मैडम ने अब तक तीन शादी की हैं। पहली शादी उन्होंने अपनी पहली नौकरी के दौरान की थी। फिर नौकरी बदली और मैडम ने पति भी बदल लिया। उसके बाद मैडम की दूसरी शादी भी अधिक दिन तक नहीं टिक पाई। दूसरी शादी टूटने के बाद मैडम ने तीसरी शादी की है और वर्तमान में उसे निभा रही हैं। लेकिन बड़े साहब और मैडम के बीच बढ़ी नजदीकी के कारण अब तीसरी शादी में भी अनबन की खबरें आने लगी हैं। अब सबको इंतजार है कि मैडम का अगला कदम क्या हो सकता है।

होटल में कट रही साहब की रात

2014 बैच के एक आईएएस अधिकारी एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इसकी वजह यह है कि साहब यदा-कदा सरकारी बंगला छोड़कर एक होटल में रहने लगते हैं। हर कोई हैरान है कि साहब को इतना बड़ा बंगला मिला है फिर भी वे होटल में रात क्यों गुजार रहे हैं। यहां बता दें कि साहब महाकौशल क्षेत्र के खनिज संपदा से भरे एक जिले के कलेक्टर हैं। साहब जबसे जिले में कलेक्टर बनकर आए हैं, तबसे वे कई मामलों को लेकर चर्चा में बने रहे हैं। लेकिन इस बार वे अपने प्रेम प्रसंग के कारण चर्चा में हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक दो शादी कर चुके साहब का दिल एक महिला अधिकारी पर इस कदर आ गया है कि वे अपनी दूसरी शादी से भी निजात चाहते हैं। गौरतलब है कि साहब ने पहली शादी एक आईएएस अधिकारी से ही की थी। लेकिन वह शादी अधिक दिन नहीं चली। फिर साहब ने दूसरी शादी भी एक आईएएस अधिकारी से ही की है, लेकिन अब साहब का दिल एक तीसरी महिला अधिकारी से लग गया है। साहब का जिस महिला अधिकारी से दिल लगा है, वह एडिशनल कलेक्टर हैं। आलम यह है कि मैडम भी साहब पर पूरी तरह फिदा हैं और वे आए दिन साहब से मिलने के लिए साहब की पदस्थापना वाले जिले में पहुंच जाती हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब ने कलेक्टर बंगला छोड़कर होटल में रहने का प्लान मैडम के लिए ही बनाया है, ताकि दोनों सुकून से रातें गुजार सकें।

मंत्रीजी को लगा दी चपत

चुनावी माहौल में इस समय हर तरफ नेताओं की हार-जीत के गणित की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश सरकार के एक मंत्री अपनों की दगाबाजी के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये मंत्रीजी मालवा-निमाड़ क्षेत्र से आते हैं। बताया जाता है कि प्रदेश में पहली बार मंत्री बनने के बाद नेताजी ने कमाई करने का बीड़ा उठाया और पाई-पाई जमा करते रहे। करीब तीन साल के दौरान साहब ने करोड़ों रुपए कमाए और उसे अपने एक खास सरकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रखवाया था। लेकिन एक दिन वह सरकारी अधिकारी साहब की सारी जमा-पूंजी लेकर चंपत हो गया। महाकाल की नगरी का रहने वाला उक्त सरकारी अधिकारी आरएसएस की पृष्ठभूमि का था। इसलिए मंत्रीजी ने उस पर भरपूर विश्वास भी किया था। लेकिन दूसरों को दबा, धमका और काम कराने के एवज में मंत्रीजी ने जितनी कमाई की थी, वह सभी उनका सबसे करीबी और विश्वासपात्र व्यक्ति लेकर गायब हो गया है। सूत्रों का कहना है कि साहब किसी तरीके से अपनी कमाई हुई रकम को सीधा करने के लिए लगे हुए हैं। पर अफसर भी जान गया कि साहब की नब्ज कहां पर दबी है।

नजर लागी बंगले पर...

ये फिल्मी गाना तो आपने सुना ही होगा कि, नजर लागी राजा तोहरे बंगले पर। प्रदेश की राजधानी में इन दिनों अफसरों के बीच बंगलों को कब्जाने की दौड़ चल रही है। आलम यह है कि राजधानी में पदस्थ रहे कई आईएएस और आईपीएस कलेक्टर और एसपी बनकर दूसरे जिलों में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना बंगला छोड़ा नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि उन्हें इस बात का डर है कि कुछ महीनों बाद प्रदेश में जब नई सरकार बनेगी तो कहीं उन्हें फिर से राजधानी में न बुला लिया जाए। ऐसे में फिर बंगला खोजने की जहमत क्यों उठाई जाए। उधर, अफसरों द्वारा बंगला खाली न किए जाने का असर यह हो रहा है कि राजधानी में पदस्थ होने वाले कई अफसरों को बंगले के लिए हाथ-पैर मारने पड़ रहे हैं। ऐसे ही एक आईपीएस को काफी मेहनत के बाद बंगला अलॉट हुआ तो वे खुशी से फूले नहीं समाए। लेकिन साहब का बंगला आईआरएस अधिकारी ने अलॉट करा लिया। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी को वह बंगला पाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री से फोन करवाना पड़ा, क्योंकि वह भी पुलिस अफसर को अलॉट हुआ था।

सिंहस्थ की तैयारियां शुरू

मप्र में इस चुनावी समर के बाद नई सरकार किसी भी राजनीतिक दल की बने, उसकी प्राथमिकता वर्ष 2028 में धर्मनगरी उज्जैन में लगने वाले महाकुंभ सिंहस्थ को सुख-शांति से निर्विघ्न कराने की होगी। सबसे बड़ी चुनौती मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी का उद्धार करने की होगी। इस बात का समर्थन सिंहस्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे दिवाकर नातू भी करते हैं। उनका कहना है कि क्षिप्रा नदी उज्जैनवालों के लिए जीवनदायिनी है। करोड़ों श्रद्धालु इसके जल में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। इस नदी का जल 12 माह स्वच्छ-शुद्ध रहे, इसकी व्यवस्था होना ही चाहिए। मालूम हो कि देश का सबसे बड़ा स्नान पर्व सिंहस्थ हर 12 वर्ष बाद उज्जैन में अमृत तुल्य मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, जिसमें दुनियाभर के साधु-संत और श्रद्धालु क्षिप्रा में स्नान करने आते हैं। पिछली बार महाकुंभ वर्ष 2016 में लगा था, जिसमें आठ करोड़ लोग सम्मिलित हुए थे। इनकी व्यवस्थाओं पर सरकार ने 4500 करोड़ रुपए खर्च किए थे।

इस बार वर्ष 2028 में 9 अप्रैल से 8 मई तक महाकुंभ लगना है। स्थानीय प्रशासन ने 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया है। इन सभी को क्षिप्रा नदी के स्वच्छ-शुद्ध जल में स्नान कराना शासन-प्रशासन के लिए अब भी चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि पिछली सरकारें क्षिप्रा नदी के हरित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने और नदी के जल को आचमन लायक शुद्ध बनाने में प्राय: विफल ही रही है। पिछले दो आम चुनावों में राजनीतिक दलों ने क्षिप्रा को चुनाव का मुद्दा भी बनाया। सरकार बनने पर योजनाएं बनवाई। कुछ धरातल पर उतारी और कुछ कागजों पर ही उलझाए रखी। क्षिप्रा में कान्ह का प्रदूषित पानी मिलने से रोकने को 598 करोड़ रुपए की कान्ह डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना इसका ताजा उदाहरण है, जो सैद्धांतिक और प्रशासकीय स्वीकृति के 10 महीने बाद भी धरातल पर न उतर पाई। वो योजना, जिसे सिंहस्थ -2052 के वक्त इंदौर एवं सांवरे शहर की आबादी और सीवेज उद्वहन को ध्यान में रख बनाया गया। तय किया गया था कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सीवेज युक्त गंदा पानी क्षिप्रा नदी (स्नान क्षेत्र त्रिवेणी घाट से कालियादेह महल तक) में मिलने से रोकने के लिए त्रिवेणी घाट के समीप पांच मीटर ऊंचा स्टापडेम बनाया जाएगा।

यहां से कालियादेह महल के आगे तक 16.5 किलोमीटर लंबा एवं 4.5 बाय 4.5 मीटर चौड़ा आरसीसी बॉक्स बनाकर जमीन पर बिछाया जाएगा। कालियादेह महल के आगे अंतिम 100 मीटर लंबाई में ओपन चैनल का निर्माण किया जाएगा। पर ये परियोजना कानूनी विवाद में ऐसी फंसी कि आगे बढ़ ही न पाई। क्षिप्रा में पीलिया खाल और भैरवगढ़ नाले का गंदा पानी सीधे मिलने से रोकने के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाने, 1420-1420 मीटर लंबी दो सीवर इराजिंग मेंस पाइपलाइन बिछाने का काम भी धरातल पर शुरू न हो पाया। जबकि केंद्र सरकार छह महीने पहले ही इस कार्य को कराने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अंतर्गत सैद्धांतिक और प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर चुकी थी।

पिछले सिंहस्थ में क्षिप्रा नदी में गंदा पानी देख साधु-संत भड़क गए थे। कईयों ने नदी में उतरकर विरोध-प्रदर्शन करने, सिंहस्थ का बहिष्कार करने की चेतावनी तक दी थी। तब ताबड़तोड़ सरकार ने क्षिप्रा में नर्मदा का स्वच्छ पानी क्षिप्रा में छुड़वाकर सिंहस्थ का स्नान कराया था। उस दरमियान परमार्थ निकेतन के संचालक स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित कई साधु-संत और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षिप्रा नदी का किनारा आकर्षक बनाने की बात कही थी। हालांकि रिवर फ्रंट योजना अब तक न बनी। पिछले वर्ष भी क्षिप्रा शुद्धि के लिए साधु-संतों ने राम घाट पर धरना दिया था। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक के निर्माण के बाद दुनियाभर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। शासन-प्रशासन ने आने वाले समय में संख्या और अधिक बढ़ने की उम्मीद जताई है। ऐसे में सिंहस्थ भूमि पर हुआ अतिक्रमण हटाना, शहर की वायु गुणवत्ता और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी हो गया है। सिंहस्थ भूमि पर 300 से अधिक अतिक्रमण हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 50 से कम बेहतर माना गया है पर उज्जैन शहर का एक्यूआई औसत 88.6 है। बीते 20 दिनों से एक्यूआई 100 पार है। ट्रैफिक सुधार के लिए हरिफाटक ब्रिज की चारों भुजाओं का दोहरीकरण, फ्रीगंज रेलवे ओवर ब्रिज के समानांतर एक और ब्रिज का निर्माण, देवास गेट बस स्टैंड एवं नानाखेड़ा बस स्टैंड से श्री महाकाल महालोक तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने सहित कुछ मार्गों को चौड़ा किया जाने की आवश्यकता भी प्रतीत होती है।

● **विकास दुबे**

अरबों रुपए खर्च, फिर भी क्षिप्रा मैली

मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी एक बार फिर विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनने जा रही है। वजह, कई सरकारी घोषणाओं एवं अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी क्षिप्रा का जल स्वच्छ न होना और किनारों के संरक्षण, संवर्धन की बातें कागजों तक सिमटकर रह जाना है। कांग्रेस बीते विधानसभा चुनाव में अपने वचन पत्र में इसे शामिल कर चुकी है और इस बार भी तैयारी है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्षिप्रा शुद्धीकरण का संकल्प ले चुके हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में क्षिप्रा का जल डी ग्रेड का है। वजह, इसके प्रतिबंधित क्षेत्र में बढ़ता अतिक्रमण और इंदौर के सीवेज युक्त नालों का प्रदूषित पानी कान्ह नदी के रूप में उज्जैन आकर मिलना भी है। पिछले दो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, महापौर चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र और भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में क्षिप्रा नदी को लेकर कई वादे किए थे। इन वादों के परिणामस्वरूप क्षिप्रा को सदानीरा और स्वच्छ बनाने के लिए भाजपा सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। पहले वर्ष 2014 में 432 करोड़ रुपए खर्च कर क्षिप्रा को नर्मदा नदी से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया। प्राकृतिक प्रवाह से पानी छोड़ने से उद्देश्य की पूर्ति न होने पर साल 2019 में 139 करोड़ रुपए खर्च कर इंदौर के गांव मुंडला दोस्तदार स्थित पंपिंग स्टेशन से उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र तक 66.17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछवा दी।

मुफ्त की रेवड़ियां नई सरकार पर पड़ेंगी भारी...!

मप्र सहित देशभर में यह परंपरा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि चार साल सरकार में रहने के बाद भी चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे कर देती हैं। इसे ही राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। आज यह रेवड़ी कल्चर चुनावी परंपरा बन गई है। यही वजह है कि मप्र में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की घोषणाओं की भरमार कर दी है। खासकर भाजपा सरकार की घोषणाएं चर्चा में हैं। चुनावी साल में हुईं घोषणाएं सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही हैं।

गौरतलब है कि मप्र सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए है और खर्च इससे 54 हजार करोड़ ज्यादा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 हजार करोड़ की नई घोषणाएं कर चुके हैं। अकेले लाड़ली बहना योजना पर ही सालाना 19 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि इन सबके लिए पैसा कहां से आएगा? चुनाव के बाद जब प्रदेश में नई सरकार बनेगी तो उस पर फ्रीबीज का भार पड़ेगा। नई सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ऐसे में सरकार चलाना भारी पड़ सकता है।

पिछले तीन-चार महीने में सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषणाओं की ऐसी झड़ी लगाई कि **हितग्राहियों** की तो बांछें खिल गईं, लेकिन सरकार को खाली पड़े खजाने के बीच इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए लोन पर लोन लेना पड़ा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक छह महीने में बाजार, नाबार्ड और अन्य स्रोतों से 29 हजार 860 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अकेले सितंबर माह में सरकार ने बाजार से 9 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया। सरकार ने आखिरी बार 3 अक्टूबर को 3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया। खास बात यह कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के 12 महीने में करीब 43 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर वित्त वर्ष के आखिरी महीनों (जनवरी से मार्च तक) सरकार ज्यादा लोन लेती है, लेकिन इस बार चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में ही सरकार को बड़ा लोन लेना पड़ा। मौजूदा बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए है, जबकि खर्च इससे करीब 54 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार की ओर से पिछले महीनों में की गई घोषणाओं पर बड़ी राशि खर्च होने के कारण सरकार का हर महीने का खर्च 10 प्रतिशत बढ़ गया है। सरकार का प्रतिमाह 20 हजार करोड़ का खर्च था, जो जून के बाद से बढ़कर 22 हजार करोड़ रुपए प्रतिमाह के पार पहुंच गया है।

चुनाव के बाद भाजपा या कांग्रेस जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, उसे भारी वित्तीय चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि वैसे ही सरकार का हर महीने 2 हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च बढ़ गया है। दूसरा, भाजपा और कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में लोक लुभावन घोषणाएं करने की तैयारी में हैं। इनमें कई घोषणाएं ऐसी होंगी, जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार को बड़ी राशि की जरूरत होगी। सरकार पर साल दर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति में मप्र पर 2.95 लाख करोड़ का कर्ज था। वर्तमान में यह बढ़कर 3 लाख 40 हजार करोड़ के पार पहुंच गया है। बजट अनुमान के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक यह आंकड़ा 3.85 लाख करोड़ होने का अनुमान है। मप्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।

● **सुनील सिंह**

चार योजनाओं का भार

प्रदेश सरकार पर सबसे अधिक भार चार योजनाओं का पड़ रहा है। ये वे योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं, किसानों और छात्रों के लिए शुरू कर रखी हैं। लाड़ली बहना योजना मप्र के इतिहास की सबसे महंगी योजना है। जून से इस योजना में 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जा रहे थे। अक्टूबर से यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई। अक्टूबर में 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 1597 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। योजना पर सालाना 19 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो अगस्त में प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने की घोषणा की गई है। इससे सरकारी खजाने पर 1750 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ आएगा। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप में सरकार ने कक्षा 12वीं के 78,641 छात्र-छात्राओं के खाते में 25-25 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इससे सरकार पर 196 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ आया। सरकार ने ई-स्कूटी के लिए 120 लाख रुपए और पेट्रोल स्कूटी के लिए 90 हजार रुपए निर्धारित किए हैं। इस पर करीब 79 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनके अलावा कर्मचारियों के लिए घोषित योजनाओं का भार सरकार के खजाने पर बढ़ा है। 21,110 पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने से सरकार पर सालाना 181 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। 23 हजार रोजगार सहायकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार करने से हर साल 274 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। कर्मचारियों का डीए 38 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने से खजाने पर सालाना 265 करोड़ रुपए का भार पड़ा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने से 271 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। एक लाख सरकारी पदों पर नई भर्ती से सालाना 3 हजार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है। 67,910 अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने से सालाना 565 करोड़ का बोझ पड़ा है। अतिथि विद्वानों का मानदेय 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने से हर साल 108 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है।

मप्र के विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं और युवाओं के हाथ में सत्ता की चाबी है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में इन दोनों वर्गों के मतदाताओं की संख्या अधिक है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस ने दोनों वर्गों को साधने की भरपूर कोशिश की है। पार्टियों का सबसे अधिक फोकस महिलाओं पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने महिलाओं को साधने की भरपूर कोशिश की है। ऐसे प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, बहनों के दोनों हाथों में लड्डू होगा।

मिशन-2023 महिलाएं फायदे में

मप्र के इतिहास में पहली बार भाजपा और कांग्रेस ने महिला मतदाताओं पर जमकर सौगातों का प्यार बरसाया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार चाहे जिस भी पार्टी की बने लेकिन प्रदेश की सवा करोड़ से ज्यादा महिलाएं (बहनें) तो ऐसी हैं, जिन्हें रुपए मिलेंगे। भाजपा की शिवराज सरकार अभी 1.31 करोड़ महिलाओं का लाड़ली बहना में रजिस्ट्रेशन कर चुकी है और प्रत्येक को 1250 रुपए के मान से राशि दे रही है। वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के तहत 1.37 करोड़ महिलाओं (इनमें कई वे बहनें भी शामिल हैं, जो लाड़ली का लाभ ले रहीं) के फॉर्म भरने का दावा किया है, जिन्हें सरकार बनने पर 1500 रुपए महीना देने का वादा है। यानी मप्र की कुल 2.63 करोड़ महिला मतदाता में से लगभग सवा करोड़ तो ऐसी बहनें हैं, जिनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। सरकार किसी की भी बने, इन्हें रुपए मिलते ही रहेंगे।

चुनावी साल होने से अभी प्रदेशभर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि मतदाताओं की हर इच्छा पूरी हो रही है। बस मांगने की देर है बल्कि कई मामलों में तो बिना मांगे सबकुछ मिल रहा है। सरकार योजनाएं लागू कर रही है तो विपक्ष नए वादों के साथ मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इनमें से एक सरकार की लाड़ली बहना योजना और दूसरी है कांग्रेस की नारी सम्मान योजना। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा में यही योजनाएं हैं क्योंकि इनमें सीधे नकद लाभ मिल रहा है।

कांग्रेस की नारी सम्मान योजना से चुनाव में क्या इफेक्ट होंगे, ये भांपते ही भाजपा सरकार ने लाड़ली बहना योजना लांच करके कांग्रेस के वादे का तोड़ निकाल लिया। भाजपा को फायदा ये है कि कांग्रेस तो अभी सिर्फ वादा कर रही है, लेकिन सरकार ने अब तक तीन किस्तें डाल दीं और इस महीने से 1250 रुपए बैंक में जमा होंगे। आगे चलकर ये 250 की क्रमबद्ध वृद्धि के साथ 3 हजार रुपए महीने तक पहुंचेगी। इससे महिला वोटर भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 देने की घोषणा भाजपा से पहले की थी, लेकिन इसमें जल्दबाजी कर दी और भाजपा ने इसका तोड़ निकालकर लाड़ली बहना योजना लांच कर दी। कांग्रेस

महिलाओं पर जीत-हार का दारोमदार

पांच राज्यों की विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों के सियासी गणित में जोड़-घटाव स्वाभाविक है। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों पर भरोसा करें तो इन चुनावों में सबसे अहम भूमिका युवा मतदाताओं की होने जा रही है। माना जा रहा है कि जिन्होंने युवाओं को साध लिया, जीत उसके हाथ लगने की संभावना ज्यादा है। इसकी वजह है, इन राज्यों में नए वोटर बने कुल मतदाताओं की संख्या। पांचों राज्यों में पहली बार करीब साठ लाख वोटर मतदान करने वाले हैं। जाहिर है कि उनमें पहली बार वोट डालने का उत्साह है और वे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग भी पूरे उत्साह से करेंगे। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें जनसंख्या के लिहाज सबसे बड़ा राज्य मप्र है। यहां सबसे ज्यादा 22 लाख 36 हजार नए वोटर बने हैं। राज्य में 230 विधानसभा सीटें हैं। इस लिहाज से देखें तो औसतन हर सीट पर करीब 9722 नए वोटर होंगे। लेकिन प्रति सीट नए वोटर के लिहाज से राजस्थान की स्थिति मप्र से बेहतर है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में पहली बार करीब 22 लाख चार हजार वोटर वोट डालने जा रहे हैं। राज्य की 200 विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो हर सीट पर करीब 11020 नए वोटर होंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ में सात लाख 23 हजार नए वोटर बने हैं। जिनका प्रति सीट औसत आठ हजार 33 हो रहा है। इसी तरह मिजोरम में 50 हजार 611 नए वोटर पहली बार वोट डालेंगे। यानी प्रति विधानसभा इनकी औसत संख्या करीब साढ़े बारह सौ है।

तो कहती रह गई और सरकार ने रुपए देना भी शुरू कर दिए, इससे नुकसान ये हो सकता है कि कांग्रेस की भविष्यगामी योजना की बजाय मौजूदा लाभ देखते हुए वोटर पक्ष में नहीं आएं। वहीं सरकार बनते ही सीधे 1500 खाते में डालने के वादे का फायदा ये हो सकता है कि कांग्रेस के परंपरागत वोटर भाजपा नहीं तोड़ सकेगी। कांग्रेस मीडिया विभाग प्रदेश अध्यक्ष केके मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस सभी पात्र बहनों को बिना भेदभाव लाभ देगी। भाजपा सरकार जाने वाली है, जल्दबाजी में कुछ भी वादे कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपालसिंह सिसौदिया का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ छलावा किया। भाजपा सरकार द्वारा लाई गई संबल, लैपटॉप, तीर्थ दर्शन जैसी कई योजनाएं बंद क्यों कर दी थीं।

हाल ही में जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, मप्र में महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,33,945 अर्थात् 48.57 प्रतिशत है जबकि पूर्व के आंकड़ों को देखें तो लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने में इनमें से 75 प्रतिशत महिलाएं अपने मत का प्रयोग करती हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 2003 में 74.58 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि 2008 में 79.21 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला। 2013 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 83.17 प्रतिशत हो गया जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटिंग प्रतिशत गिरा और 74.03 प्रतिशत हो गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी किंतु चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन 10 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 सीटें भाजपा के खाते में आई थीं, वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इस बार की मतदाता सूची के अनुसार प्रदेश की 29 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के मुकाबले अधिक है जिनमें बैहर, निवास, बिछिया, अलीराजपुर, कुक्षी, पानसेमल, परसवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सैलाना, पेटलावाद, जोबट, झाबुआ, मानवर, बदनावर, बरघाट, सरदारपुर, डिंडोरी, रतलाम शहर, वारसोनी, कटंगी, थांदला, छिंदवाड़ा, पुष्पराजगढ़, शाहपुरा, उज्जैन उत्तर, जावरा, इंदौर-4 और सेंधवा शामिल हैं।

यही कारण है कि भाजपा-कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिए थोक में दर्जनभर से अधिक योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। सबसे अधिक रार लाड़ली बहना योजना को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस लाड़ली बहना योजना बंद करने का षड्यंत्र कर रही है जिसमें अभी 1,250 रुपए प्रतिमाह बहनों के खाते में आ रहे हैं जो भविष्य में बढ़कर पहले 1,500 और बाद में 3,000 रुपए करने का दावा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वादा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नारी सम्मान योजना के तहत 1,500 रुपए प्रतिमाह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ ही 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जाएगा। जाहिर है, यह सारी कवायद 48.57 प्रतिशत महिला वोटरों को लुभाने के लिए है क्योंकि मतदाताओं के इतने बड़े वर्ग की अनदेखी कोई भी नहीं करना चाहता। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में महिलाएं किस कदर निर्णायक भूमिका में हैं और कई सीटों पर हार-जीत का फैसला ही महिलाओं के हाथ में होगा।

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व भाजपा-कांग्रेस ने कई सर्वे करवाए थे। इनमें से भाजपा के आंतरिक सर्वे में यह तथ्य सामने आए थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ग्रामीण महिलाओं में खासी लोकप्रियता है और इसी के चलते भाजपा ने विधानसभा चुनाव में सारा फोकस महिला वोट प्रतिशत बढ़ाने पर कर दिया। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि जहां हार-जीत का अंतर पांच से दस हजार वोटों के बीच होता है वहां महिलाओं का इतना वोट प्रतिशत बढ़ने से सीटें पार्टी जीत लेगी। अब यह वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा तो इसके लिए बीते एक वर्ष से लेकर अब तक शिवराज सरकार की महिलाओं को लेकर योजनाओं अथवा घोषणाओं का विश्लेषण करने से स्थिति साफ हो जाएगी। शिवराज सरकार की महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कन्यादान योजना, लाड़ली लक्ष्मी, जननी योजना, महिला मजदूरों को प्रसव पर आर्थिक सहायता, छात्राओं को मुफ्त साइकिल और स्कूल ड्रेस, छात्रवृत्ति, बुजुर्ग महिलाओं को तीर्थ दर्शन कराने की योजना, महिलाओं को गैस चूल्हा बांटने वाली उज्जवला योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना, आवास योजना आदि ने महिलाओं में भाजपा की लोकप्रियता को बढ़ाया है। हालांकि यह लोकप्रियता वोटों में कितना तब्दील होगी यह 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा।

● **कुमार विनोद**

महिलाओं को 13 प्रतिशत भी प्रतिनिधित्व नहीं

मप्र में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने न केवल वादे किए हैं, बल्कि योजनाओं के साथ ही सौगातों की बौछार की है। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो पार्टियों ने महिलाओं को बराबरी का हक देने की बजाय उनके हिस्से का भी हक नहीं दिया है। गौरतलब है कि चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी टिकट देने की बात हो रही है लेकिन प्रदेश में किसी भी पार्टी ने 15 फीसदी टिकट भी नहीं दिया है। जबकि मप्र की 16वीं विधानसभा गठन के लिए हो रहे विधानसभा चुनावों में बहुमत की भूमिका 2.72 करोड़ महिलाएं भी निभाएंगी। मौजूदा समय में मप्र सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी तय कर चुकी है। मप्र में कुल मतदाताओं की संख्या 5.60 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को एक स्वर में भाजपा और कांग्रेस के साथ सभी पार्टियों ने समर्थन दिया, लेकिन मप्र विधानसभा चुनाव में किसी ने 33 फीसदी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। भाजपा द्वारा घोषित 230 उम्मीदवारों में से 28 महिलाओं को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने 230 में से 29 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह भाजपा ने मात्र 12.28 और कांग्रेस ने 12.66 फीसदी महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व दिया है। इससे साफ होता है कि, दोनों ही राजनीतिक दलों को महिला प्रत्याशी के जीतने पर पुरुषों की अपेक्षा कम भरोसा है।

आईपीएस को पसंद नहीं केंद्र में प्रतिनियुक्ति

केंद्र सरकार में बतौर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस अफसरों का तय कोटा भर नहीं पा रहा था कि अब स्पेशल डीजी और आईजी पद के लिए निर्धारित वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अगस्त में जारी आईपीएस प्रतिनियुक्ति स्टेटस के अनुसार, केंद्र में डीजी के लिए 15, एसडीजी के 10, एडीजी के 26, आईजी के 138, डीआईजी के 255 और एसपी के 225 पद स्वीकृत थे। अब 10 अक्टूबर की स्टेटस रिपोर्ट में डीजी के 15, एसडीजी के 12, एडीजी के 26, आईजी के 146, डीआईजी के 255 और एसपी के 225 पद स्वीकृत दिखाए गए हैं। मौजूदा समय में केंद्र की आईपीएस प्रतिनियुक्ति के लिए डीजी के तीन, एसडीजी का 1, एडीजी के 2, आईजी के 28, डीआईजी के 87 और एसपी के 93 पद खाली पड़े हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की 11 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, डीजी के 15 स्वीकृत पदों में से 2 खाली थे, लेकिन एसडीजी के सभी 10 पद भरे हुए थे। एडीजी के 26 पदों में से केवल दो स्थान खाली थे। आईजी के 138 पदों में से 20, डीआईजी के 255 पदों में से 86 और एसपी रैंक के 225 पदों में से 95 पद खाली बताए गए थे। सीबीआई में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 73 पदों में से 42 पद खाली पड़े थे, जबकि आईबी में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 83 पदों में से 34 पद खाली थे। एनआईए में भी एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 36 पदों में से 7 पद खाली थे। एनपीए में एसपी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 14 पदों में से 8 पद खाली थे।

बीएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 26 पदों में से 9 पद खाली पड़े हैं। सीआईएसएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 20 पदों में से 12 पद खाली पड़े हैं। आईबी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 63 पदों में से 41 पद खाली पड़े हैं। आईटीबीपी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 11 पदों में से 7 पद खाली पड़े हैं। एसएसबी में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 24 पदों में से 10 पद खाली पड़े हैं। सीआरपीएफ में डीआईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 38 पदों में से कोई भी पद रिक्त नहीं दिखाया गया है। सीबीआई में आईजी स्तर पर आईपीएस के लिए पहले 16 पद स्वीकृत थे। अब वह संख्या 18 कर दी गई है। मौजूदा समय में आईजी के छह पद रिक्त हैं। आईबी में आईजी स्तर पर आईपीएस के लिए स्वीकृत 37 पदों में से 6 पद खाली पड़े हैं। तीन मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों, आयोगों और जांच एवं खुफिया एजेंसियों में डीआईजी के लिए स्वीकृत 255 पदों में से 77 पद खाली थे। इससे पहले खाली पदों की यह संख्या 120 से 186 के बीच थी।

लंबे समय से विशेषकर आईपीएस डीआईजी, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आने का मन नहीं बना पा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन अधिकारियों के लिए पैनल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। इसके पूरा होने में काफी समय लगता है। सरकार के इस कदम का मकसद, केंद्र में डीआईजी-रैंक के अधिकारियों की भारी कमी को दूर करना था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास यह प्रस्ताव कई बार भेजा गया था। गत वर्ष 10 फरवरी को इसे कमेटी की मंजूरी मिल गई थी। केंद्र सरकार का मानना था कि डीआईजी-रैंक के अधिकारियों के लिए पैनल सिस्टम को खत्म करने से अब प्रतिनियुक्ति पर अधिक आईपीएस केंद्र में आ सकेंगे। मनोनयन प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक साल लग जाता था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि जो भी आईपीएस एसपी या डीआईजी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं आएंगे, उन्हें बाकी सेवा के दौरान केंद्रीय नियुक्ति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे पहले केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा नियमों में संशोधन भी किया था। उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार, आईएएस व आईपीएस अधिकारी को राज्य की अनुमति या बिना अनुमति के भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है।

तीन मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों, आयोगों और जांच एवं खुफिया एजेंसियों में डीआईजी के लिए 255 पद स्वीकृत थे। इनमें से डीआईजी के 77 पद अभी खाली पड़े थे। आईजी के लिए 138 पद स्वीकृत थे, जिनमें से 19 पद खाली पड़े थे। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर डीजी रैंक के लिए 15 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से दो पद खाली थे। एक पद बीएसएफ डीजी का और दूसरा एनपीए निदेशक का पद शामिल था। एसडीजी आईपीएस के लिए 10 पद मंजूर किए गए हैं, उनमें भी दो पद रिक्त थे। एडीजी के 26 पद हैं। इनमें भी तीन पद खाली पड़े थे। एसपी के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 225 है, इन पदों में से 113 पद रिक्त थे। आईबी में डीआईजी के लिए स्वीकृत 63 पदों में से 38 पद खाली थे, जबकि आईपीएस एसपी के लिए मंजूर 83 पदों में से 40 पद रिक्त पड़े थे।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

साल 2020 में आईपीएस प्रतिनियुक्ति का कोटा

30 जुलाई 2020 की स्थिति के मुताबिक, केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति डीआईजी के लिए 254 पद स्वीकृत थे। इनमें से 164 पद थे। आईजी के लिए स्वीकृत 135 पदों में से 20 पद खाली पड़े थे। डीजी रैंक के लिए 13 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 2 पद खाली थे। एसडीजी के 10 में से 3 पद रिक्त थे। एडीजी के 27 पदों में से 4 पद खाली रहे। उस दौरान एसपी के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 199 थी, मगर इनमें से 97 पद रिक्त रहे। हैरानी की बात रही कि उस वर्ष बीएसएफ में आईपीएस डीआईजी के 26 पदों में से 22 पद खाली थे। सीआरपीएफ में ये पद 38 थे, जिनमें से केवल एक ही पद भरा हुआ था। सीबीआई में 35 में से 20 पद खाली थे, जबकि सीआईएसएफ में 20 में से 16 पद रिक्त थे। आईबी में आईपीएस डीआईजी के 63 में से 28 पद और आईपीएस एसपी के 83 में से 49 पद खाली रह गए थे। 9 जून 2021 की स्थिति के अनुसार, केंद्र में बतौर प्रतिनियुक्ति डीआईजी के लिए 251 पद स्वीकृत थे। इनमें से 186 पद खाली थे। आईजी के लिए स्वीकृत 140 पदों में से 26 पद खाली पड़े थे। डीजी रैंक के लिए 13 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 4 पद खाली थे। एसपी के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 203 थी, मगर इनमें से 96 पद रिक्त रहे। उस दौरान सीआरपीएफ व बीएसएफ में आईपीएस डीआईजी के अधिकांश पद खाली रहने के कारण उन्हें सीएपीएफ कैडर अधिकारियों की ओर डायवर्ट कर दिया गया था।

तीसरी ताकत कितनी ताकतवर

विंध्य के रास्ते छाने को आतुर आप

विंध्य क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें हैं जिनमें से वर्तमान में 24 सीटें भाजपा के खाते में हैं और यह क्षेत्र कमल दल का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है किंतु 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में आप की रानी अग्रवाल सिंगरौली की महापौर बनीं, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में सपा-बसपा की तीसरी ताकत बनने के स्वप्न पर झाड़ू फेर दी। यह प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर था जब कोई महापौर भाजपा-कांग्रेस से इतर किसी अन्य राजनीतिक दल का चुना गया। इसके अलावा आप ने निकाय चुनाव में प्रदेशभर के निकायों में 6-7 प्रतिशत वोट प्राप्त किए। प्रदेश में 40 से अधिक आप पार्षद प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया और 86 से ज्यादा प्रत्याशियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। नगरीय निकाय के इतर आप ने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आप समर्थित उम्मीदवारों में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से अधिक जिला पंचायत सदस्य, 20 से अधिक जनपद सदस्य, 100 से अधिक सरपंच तथा 200 से अधिक पंच निर्वाचित हुए। ऐसे में आप के नेता और कार्यकर्ता पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव में उतरने को आतुर हैं। आप की प्रदेश में संभावनाएं इसलिए भी नजर आ रही हैं क्योंकि पार्टी को भाजपा और कांग्रेस के ऐसे मजबूत चेहरों का साथ मिला जिन्हें दोनों दलों ने टिकट से वंचित कर दिया। पिछले छह महीनों में आप ने कांग्रेस और भाजपा के कई क्षुब्ध नेताओं को पार्टी की सदस्यता दी है और उन्हें विधानसभा चुनाव में भी उतारा जा रहा है।

मप्र की 185 किमी लंबी सीमा उप्र से लगती है जिसमें ग्वालियर-चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, बुंदेलखंड संभाग के सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर तथा विंध्य संभाग के पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले आते हैं। चूंकि इन सभी जिलों की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि उप्र की संस्कृति से मेल खाती है, अत: यहां राजनीतिक रूप से भी उप्र के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को खाद-पानी मिलता रहा है।

इन 14 जिलों की 67 विधानसभा सीटों में से कई पर सपा-बसपा ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मप्र में जेडीयू, एनसीपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल आदि ने भी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया किंतु कोई भी दल अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। किंतु 2013 के विधानसभा चुनाव में सपा-बसपा से इतर आम आदमी पार्टी आप की एंट्री से एक बार फिर क्षेत्रीय दलों और उनके प्रभाव तथा तीसरी ताकत बनने की संभावनाओं पर बहस छिड़ गई है।

हालांकि एक समय बसपा प्रदेश में तीसरी ताकत बनती नजर भी आ रही थी किंतु मायावती पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रदेशवासियों ने हाथी की सवारी करने से इंकार कर दिया जबकि सपा के साथ गुंडागर्दी और यादवराज का दाग चिपका रहा। अब जबकि आप ने राज्य में भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और 230 विधानसभा सीटों में से 66 पर प्रत्याशियों का चयन किया जा चुका है। पिछले पांच चुनावों में तीसरी ताकत बनने को आतुर सपा-बसपा के प्रदर्शन पर भी ध्यान देना होगा।

अविभाजित मप्र में 1998 में 330 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे जिनमें से सपा ने 94 सीटों पर अधिकृत प्रत्याशी उतारे किंतु विधानसभा की ओर मात्र 4 प्रत्याशियों की साइकिल ही मुड़ पाई। 84 सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, शेष 6 प्रत्याशी तीसरे-चौथे स्थान पर रहे। 2000 में मप्र से टूटकर बने छत्तीसगढ़ के चलते प्रदेश में 230 विधानसभाएं बचीं और 2003 के विधानसभा चुनाव में 161 विधानसभा सीटों पर साइकिल चली, किंतु चुनाव परिणाम में मात्र 7 प्रत्याशी ही इसकी सवारी कर पाए। शेष सभी चुनावी रण में खेत रहे।

2008 के विधानसभा चुनाव को संभवत: कोई भी समाजवादी याद नहीं करना चाहेगा क्योंकि सपा के 187 अधिकृत प्रत्याशियों में से 183 की जमानत जब्त हो गई थी और निवाड़ी विधानसभा से मीरा यादव ही चुनाव जीत सकी थीं, वह भी तब जब उनके साथ उनके पति पूर्व विधायक और बाहुबली दीप नारायण सिंह यादव मजबूती से खड़े रहे थे। निवाड़ी टीकमगढ़ जिले में आता था जिसकी सीमा उप्र के ललितपुर जिले से लगती है। 1 अक्टूबर, 2018 को निवाड़ी स्वतंत्र जिला बना दिया गया।

2013 का विधानसभा चुनाव भी सपा के लिए दुस्वप्न रहा, जबकि उसके 164 अधिकृत प्रत्याशियों में से 161 की जमानत जब्त हुई और पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहीं 2018 में सपा का मात्र 1 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचा। वोट प्रतिशत के आधार पर देखें तो मप्र निर्वाचन आयोग के अनुसार, सपा को 1998 में 4.83 प्रतिशत, 2003 में 5.26 प्रतिशत, 2008 में 2.46 प्रतिशत, 2013 में 1.70 प्रतिशत और 2018 में 1.30 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार बसपा ने 1998 के विधानसभा चुनाव में 330 सीटों पर 221 प्रत्याशी उतारे जिनमें से 11 जीतने में सफल रहे। इस चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत 6.15 प्रतिशत रहा। 2003 विधानसभा चुनाव में बसपा को 7.26 प्रतिशत वोट मिले और उसके 2 प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे। 2008 में बसपा ने 228 विधानसभा सीटों पर अधिकृत प्रत्याशी उतारे जिनमें से 7 प्रत्याशी जीतने में सफल रहे और पार्टी को 8.97 प्रतिशत वोट मिले। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 230 में से 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल की। 202 सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई।

हालांकि इस चुनाव में 5.1 प्रतिशत वोट शेयर पाकर बसपा मप्र में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। प्रदेश की 65 सीटों पर बसपा का वोटबैंक 10 प्रतिशत तक रहा है। हालांकि सपा-बसपा के साथ प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या उनके विधायकों की प्रतिबद्धता रही है क्योंकि अधिकांश ने जीत के बाद या तो भाजपा की सदस्यता ले ली अथवा हाथ का साथ निभाने चल पड़े। जो बचे वे अपनी राजनीतिक जमीन नहीं बचा पाए क्योंकि उनके पास न तो नेतृत्व था और न ही जमीनी कार्यकर्ता। ऐसे में प्रदेश में तीसरी ताकत के लिए हमेशा मैदान साफ ही रहा है।

● **अरविंद नारद**

सिंचाई के पानी की कमी से जूझता मप्र

आज उठाए कदमों पर निर्भर है कल का भविष्य

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में जारी आंकड़ों से पता चला है कि 2050 तक शहरों में पानी की मांग 80 फीसदी तक बढ़ जाएगी। वहीं यदि मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो दुनियाभर में शहरों में रहने वाले करीब 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं अनुमान है कि अगले 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक जा सकता है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जहां पानी को लेकर होने वाली खींचातानी कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले लेगी। गौरतलब है कि भूजल के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2018 में अटल भूजल योजना का प्रस्ताव रखा था। जिसे विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना लक्ष्य गिरते भूजल का गंभीर संकट झेल रहे सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मप्र, राजस्थान और उप्र में संयुक्त भागीदारी से भूजल का उचित और बेहतर प्रबंधन करना है। भारत में गिरते भूजल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जलदूत नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है।

मप्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसलिए दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों, भाजपा और कांग्रेस ने मप्र में सिंचाई के पानी की कमी को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। राज्य के कई क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान पीने के पानी की कमी के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। हर घर में नल से पानी पहुंचाने के अभियान और कई सिंचाई परियोजनाओं के चलते राज्य में जल संकट अभी भी जारी है। प्रदेश के करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलने लगा है। इसके साथ ही कई लंबित परियोजनाएं अगले दो वर्षों में और 20 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकती है। वर्तमान में छिंदवाड़ा नर्मदा में बन रहा सिंचाई परिसर, नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक परियोजना, दमोह-सागर की पंचम नगर सिंचाई परियोजना, रीवा-सतना की बहोटी परियोजना, बदनावर नर्मदा सूक्ष्म सिंचाई, चंबल क्षेत्र की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना, बीना नदी पर प्रस्तावित हनोता सिंचाई परियोजना, राजगढ़ की कुंडलिया सिंचाई परियोजना और मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागू होने पर राज्य के सिंचित क्षेत्र में बड़ी वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा था कि मप्र में वर्ष 2003 में सरकारी स्रोतों से सिंचित कुल क्षेत्रफल सात लाख हेक्टेयर था जो अब 43 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। इसके साथ ही सरकार ने अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 63 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर सिंचाई पानी के संकट को लेकर कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई बार हमला बोल चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने कई मौकों पर चौहान को घोषणा नायक कहा है और आरोप लगाया है कि वह जमीनी स्तर पर मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। बुंदेलखंड के कांग्रेस नेता वीरेंद्र दवे लोगों के साथ बातचीत करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी सहित अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए साइकिल यात्रा शुरू करेंगे। दवे का कहना है कि दमोह जिले की पंचम नगर सिंचाई परियोजना किसानों को पानी उपलब्ध कराकर और बिजली पैदा कर कृषि में क्रांति ला सकती है। इस परियोजना के तहत बिना बिजली के खेतों तक पानी पहुंचेगा। दवे ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की एक वाणिज्यिक सीमेंट कंपनी सहयोग नहीं कर रही है और परियोजना के पूरा होने में बाधा उत्पन्न कर रही है।

दुनियाभर में बढ़ता तापमान अपने साथ अनगिनत समस्याएं भी साथ ला रहा है, जिनकी जद से भारत भी बाहर नहीं है। ऐसी ही एक समस्या देश में गहराता जल संकट है जो जलवायु में आते बदलावों के साथ और गंभीर रूप ले रहा है। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और गर्म जलवायु के चलते भारत आने वाले दशकों में अपने भूजल का कहीं ज्यादा तेजी से दोहन कर सकता है। अनुमान है कि इसके चलते 2040 से 2080 के बीच भूजल में आती गिरावट की दर तीन गुणा बढ़ सकती है। इस रिसर्च के नतीजे एक सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुए हैं।

गौरतलब है कि भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पहले ही कहीं ज्यादा तेजी से अपने भूजल का दोहन कर रहा है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत में हर साल 230 क्यूबिक किलोमीटर भूजल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि भूजल के वैश्विक उपयोग का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। देश में इसकी सबसे ज्यादा खपत कृषि के लिए की जा रही है। देश में गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए भारत बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है। लेकिन जैसे-जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, खेत तेजी से सूख रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी में नमी को सोखने की क्षमता भी घट रही है, जिसकी वजह से भारत में भूजल स्रोतों को रिचार्ज होने के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है। नतीजन साल दर साल देश में भूजल का स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। अनुमान है कि बढ़ते तापमान के साथ जल उपलब्धता में आने वाली इस गिरावट के चलते एक तिहाई लोगों की जीविका पर खतरा मंडराने लगेगा। इसके न केवल भारत में बल्कि वैश्विक परिणाम भी सामने आएंगे। साथ ही इससे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा।

बता दें कि दुनिया भर में भूमिगत जल, साफ पानी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्रोत है। आंकड़ों की मानें तो वैश्विक स्तर पर करीब 200 करोड़ लोग, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और सिंचाई के लिए भूजल पर ही निर्भर हैं। रिसर्च के अनुसार दुनिया की 20 फीसदी आबादी इन भूजल स्रोतों द्वारा सिंचित फसलों का उपभोग कर रही है। हालांकि बढ़ती आबादी और उनकी जरूरतों के साथ इन भूजल स्रोतों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक दुनिया के 79 फीसदी तक भूजल स्रोत खत्म हो जाएंगे।

● **राजेश बोरकर**

चुनावी रंग में रंगी बिजली

महंगाई और कटौती का पर्याय बनी बिजली मप्र में चुनावी माहौल में कमाल दिखा रही है। यानी प्रदेश में न तो बिजली की कमी पड़ रही है और न ही कंपनियों को घाटा लग रहा है। इससे किसानों के साथ ही सभी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। खेती-किसानी के इस दौर में किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर बिजली मिल रही है। जबकि पिछले 4 साल किसान बिजली के लिए परेशान होते रहे।

गौरतलब है कि मप्र के ग्रामीण इलाके ही विधानसभा चुनाव की तस्वीर को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस चुनाव में भी किसानों की समस्याएं मुख्य चुनावी मुद्दा हैं। किसानों ने बिजली, पानी की किल्लत और छुट्टा पशुओं से फसल को हो रहे नुकसान की समस्या को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही बिजली की समस्या छूमंतर हो गई है।

प्रदेश की बिजली कंपनियां फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजेस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) के नाम पर हर महीने बिजली का टैरिफ बढ़ा रही हैं। प्रदेश में एफपीपीएएस अप्रैल से लागू हुआ है। पहली बार बिजली कंपनियों ने 8.41 फीसदी सरचार्ज वसूला था। पिछले पांच महीने से हर महीने सरचार्ज वसूला जा रहा है। मप्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है। ऐसे में इस बार बिजली कंपनियों को कोई घाटा नहीं लगा। बिजली कंपनियों ने इस बार 1 पैसे का भी सरचार्ज नहीं लगाया है। केंद्र सरकार ने घाटे के आधार पर फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजेस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) वसूलने के अधिकार बिजली कंपनियों को दिए हैं। इसके चलते बिजली कंपनियों ने मई से सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया था। इस सरचार्ज की गणना प्रत्येक महीने की 24 तारीख को होती है। बिजली कंपनियों द्वारा मई से हर महीने सरचार्ज वसूला जा रहा है, लेकिन इस बार बिजली कंपनियों ने कोई सरचार्ज नहीं वसूला है। इसे चुनाव की महिमा ही कहेंगे कि चुनावी सीजन होने के चलते पिछले पांच महीने से फ्यूल कास्ट में घाटा उठा रही बिजली कंपनियों को नवंबर में कोई घाटा नहीं हुआ है।

रबी के सीजन में बिजली की खपत सर्वाधिक रहती है। अक्टूबर की शुरुआत में प्रदेश की बिजली खपत 9000 मेगावाट के करीब बमुश्किल पहुंच रही थी। वहीं महीना खत्म होने में करीब 6500 मेगावाट बिजली खपत की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वर्तमान में मप्र की बिजली खपत 15000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। इसमें भी बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड दिन के समय में बनी हुई है। रबी सीजन में गेहूं, आलू, प्याज, लहसुन, मटर एवं अन्य सब्जियों में पानी देने के लिए मोटर पंप का सहारा लिया जाता है और यह बिजली से संचालित होते हैं, जिसके कारण अक्टूबर से जनवरी तक रबी सीजन में बिजली की सर्वाधिक मांग बनी रहती है। पिछले वर्ष भी 16000 मेगावाट के करीब सर्वाधिक बिजली खपत दर्ज की गई थी।

इस बार अक्टूबर खत्म हो रहा है और बिजली की खपत 15000 मेगावाट को पार कर रही है। इंदौर बिजली कंपनी में अक्टूबर के शुरुआती दिनों में बिजली की खपत 4000 मेगावाट के करीब चल रही थी, जो अब 2150 मेगावाट बढ़कर 6150 मेगावाट के करीब चल रही है। जानकारों की मानें तो इस बार बिजली की खपत नए रिकॉर्ड दर्ज करेगी। तकरीबन 17000 मेगावाट प्रदेश में बिजली खपत का आंकड़ा आगामी एक से डेढ़ महीने में दर्ज होने की पूरी संभावना है। रबी सीजन में बिजली की मांग 15 अक्टूबर के बाद शुरू होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही बिजली की डिमांड सिंचाई के लिए शुरू हो गई थी, जिसका आंकलन अधिकारी नहीं कर पाए थे और सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देने में मशक्कत करनी पड़ी थी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

"मप्र देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन इन सबके बावजूद यहां बिजली सबसे महंगी है। स्थिति यह है कि अब तो हर महीने बिजली की दरें, बढ़ रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनावी मौसम में बिजली पर भी उसका रंग चढ़ गया है। न बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और न ही बिजली की कटौती हो रही है।"

अगले साल बढ़ेगा टैरिफ

अगले महीने प्रदेश में नई सरकार बन जाएगी। ऐसे में बिजली कंपनियों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। तय है कि अगले महीने बिजली उत्पादन महंगा हो जाएगा और हो सकता है कि बिजली कंपनियां इस महीने का सरचार्ज भी अगले महीने वसूल कर लें। चुनावी साल होने के कारण इस साल बिजली के टैरिफ में मामूली इजाफा हुआ था। बिजली कंपनियों ने 1537 करोड़ का घाटा बताते हुए बिजली की दरों में 3.20 फीसदी का इजाफा करने की मांग की थी। इसका प्रस्ताव विद्युत विनियामक आयोग को भेजा था, लेकिन आयोग ने सिर्फ 1.65 फीसदी टैरिफ बढ़ाया था। बिजली का यह टैरिफ इस साल मार्च में बढ़ गया था। अब बिजली कंपनियां अगले साल जनवरी-फरवरी में बिजली का टैरिफ बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आयोग को देंगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के चलते इस बार सरकार ने प्रदेश के करीब 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल स्थगित कर दिए हैं। इससे बिजली कंपनियां एक बार फिर बड़े घाटे में आ गई हैं। इस घाटे की भरपाई के लिए अगले साल बिजली कंपनियां बिजली के टैरिफ में 9 से 10 फीसदी तक का इजाफा करने की मांग आयोग कर सकती है। इससे तय है कि अगले साल बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिल चुकाने होंगे। इससे पहले चुनाव के बाद बिजली के टैरिफ में साल में दो बार इजाफा किया गया है।

मार्च 2020 में सत्ता खोने के बाद दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को फिर से सत्ता दिलाने के लिए कमर कस ली थी। कमलनाथ ने फ्रंट पर रहकर, तो दिग्विजय सिंह ने बैकग्राउंड से मैदानी जमावट की है। अब 2023 में सत्ता का संग्राम शुरु हो गया है, तो प्रदेश में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा पाएगी?

नाथ-दिग्गी की जुगलबंदी

गौरतलब है कि कांग्रेस ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यानी कांग्रेस ताल ठोंककर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इससे पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना भारी-भरकम घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में वचन पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के इस वचन पत्र में युवा से बुजुर्ग, बच्चों से लेकर महिला और कास्ट से लेकर क्लास, आस्था और विश्वास तक, हर उस मतदाता वर्ग को टारगेट किया गया है जिसकी भूमिका मप्र के चुनाव में सत्ता का निर्धारण करने वाली मानी जा रही है।

लेकिन टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में जिस तरह विरोध, विद्रोह, बगावत और भितरघात की गूंज उठ रही है, उससे पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेशभर में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस अपने मिशन में सफल होगी। इसकी एक वजह यह है कि विगत दिनों जब पार्टी का वचन पत्र जारी हुआ, तो उस समय मंच पर ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बहस भी हुई थी। हालांकि राजनीति के जानकार बताते हैं कि कभी तल्खी, कभी तरफदारी ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच अजब-गजब सियासी केमिस्ट्री का नमूना है। सूत्रों का कहना है कि मिशन 2023 में कांग्रेस की पूरी रणनीति इन दोनों नेताओं ने मिलकर बनाई है। हर रणनीति में इन दोनों की बराबर की सहमति है। इसी रणनीति के तहत 2020 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने मप्र में सरकार बनाने के लिए हर मोर्चे पर चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी के कद्दावर नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं भाजपा का मुकाबला करने के लिए आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को मैदानी मोर्चे पर सक्रिय कर दिया है। जबकि संगठन संभालने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दे दी है।

दोनों को समझ पाना मुश्किल

गौरतलब है कि पांच साल पहले मप्र में 2018 विधानसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बचा था, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कैमरे पर एक बात कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो चुनावों में प्रचार करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनके भाषणों का असर कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले वोटों पर पड़ता है। दिग्विजय के इस बयान ने सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए चारे का काम किया। भाजपा ने दिग्विजय का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि सबसे पुरानी पार्टी ने वोट डाले जाने से पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए। दिग्विजय ने पूरे चुनाव अभियान में खुद को लो-प्रोफाइल रखा था। नतीजों में कांग्रेस को बहुमत से 2 सीटें कम मिली थीं और 15 साल के बाद मप्र की सत्ता में कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही थी। विगत दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 मई 2018 को उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले ज्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मई 2018 तक कमलनाथ मप्र में करीब चार दशक बिता चुके थे। इन 40 सालों में ज्यादातर समय वह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2018 का चुनाव जीतकर वह मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 15 महीने ही चल पाया।

विगत दिनों मप्र में जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता के समर्थकों से कह रहे थे- जाकर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। चुनावी मौसम में सामने आया ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और सूबे की सियासत में सियासी बवाल हो गया। हंगामा खड़ा हुआ तो कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने इसे लेकर सफाई भी दी। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी नोंकझोंक भी खबरों में रही, खूब सुर्खियां बनीं। मप्र चुनाव के लिए वचन पत्र जारी करने के कार्यक्रम में दोनों नेताओं की तल्खी भी नजर आई। कमलनाथ ने ये भी कहा कि गाली खाने के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। वहीं, दिग्विजय ने कहा कि विष पीने को भी तैयार हूं। हालांकि, दिग्विजय ने कमलनाथ से ये सवाल जरूर पूछ लिया कि फॉर्म-ए और बी पर किसके दस्तखत होते हैं। ये सब हुए चार दिन बीत चुके हैं लेकिन इसे लेकर चर्चा थम नहीं रही। चर्चा के केंद्र में सवाल एक है, कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय के बीच सब ठीक है? दोनों ही नेता कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि उनके बीच सियासी से अधिक पारिवारिक रिश्ते हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ से तनाव की खबरों पर कई बार ये कह चुके हैं कि हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आएगी। अब कहा ये भी जाता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। समय-समय पर ये दिखा भी है। लेकिन दिग्विजय के दावे को आसानी से खारिज कर देना भी मुश्किल है।

दरअसल, कमलनाथ और दिग्विजय की

केमिस्ट्री भी बहुत अजब-गजब रही है। दोनों नेताओं के रिश्तों में तल्खी रही है तो तरफदारी भी। दिग्विजय सिंह ने जहां साल 1971 में राघौगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़कर सियासत में कदम रखा और 1977 में राघौगढ़ से पहली बार विधानसभा पहुंचे। वहीं, कमलनाथ के सियासी सफर का आगाज साल 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से हुआ। कमलनाथ जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह दूसरी बार विधानसभा पहुंचने की जुगत में थे। कमलनाथ दिल्ली तो दिग्विजय मप्र की सियासत में पैर जमाते चले गए। साल 1993 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई। तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव नतीजों के बाद ये मंथन चल रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे दी जाए। पार्टी पर नरसिम्हा राव की ही पकड़ मजबूत थी। तब मप्र का मुख्यमंत्री बनने की रेस में तीन नाम थे- माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ल और दिग्विजय सिंह। सिंधिया ने श्यामाचरण का समर्थन कर दिया जिसके बाद दो ही दावेदार बचे। कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव ने शुक्ल के नाम पर मुहर भी लगा दी थी। लेकिन तभी कमलनाथ ने उनको विधायकों की राय जानने और उसके अनुरूप फैसला लेने की सलाह दे दी। नरसिम्हाराव को कमलनाथ की ये सलाह पसंद आई। उन्होंने इस कार्य के लिए कमलनाथ को ही जिम्मेदारी सौंप दी। कमलनाथ की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के लिए विधायकों की राय ली गई। अधिकतर विधायकों ने दिग्विजय के नाम का समर्थन कर दिया। कमलनाथ ने ही इसकी जानकारी नरसिम्हाराव को दी और नेतृत्व की मुहर के बाद दिग्विजय सिंह 1993 में पहली बार मप्र के मुख्यमंत्री बने और 2003 तक इस पद पर रहे। इसके लिए कमलनाथ को श्रेय दिया गया। साल 2018 के चुनाव में कमलनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में दिग्विजय का अहम योगदान रहा।

कहा तो ये भी गया कि दिग्विजय ने 1993 का सियासी कर्ज चुकाया है। दरअसल, 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश

अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ मुख्यमंत्री के दावेदार थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रेस में थे। दिल्ली में कई दौर की मैराथन बैठक हुई लेकिन मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में दिग्विजय ने नेतृत्व के सामने कमलनाथ का समर्थन कर दिया। दिग्विजय ने राहुल गांधी की मौजूदगी में ये कहा कि सिंधिया के पास अभी बहुत समय है। कमलनाथ के नाम पर नेतृत्व की मुहर लग गई। कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद भी मप्र कांग्रेस अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह के रिश्तों में तनाव की खबरें आईं। दिग्विजय ने इन खबरों को खारिज किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कमलनाथ और दिग्विजय के बीच ऐसी ही नोंकझोंक नजर आई थी। कमलनाथ ने मंच से नाराजगी जताते हुए कहा था कि दिग्विजय ने अपना चेहरा खूब दिखाया। दरअसल, कमलनाथ का इशारा दिग्विजय की सक्रियता की ओर था।

पिछले दिनों जब ये बहस छिड़ी थी कि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के लिए कमलनाथ चेहरा होंगे या कोई और? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजय सिंह राहुल ने कहा था कि चुनाव बाद विधायक और आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तब भी दिग्विजय ने खुलकर कमलनाथ का समर्थन करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए वही पार्टी का चेहरा हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक्टिव भी हैं, तहसील स्तर पर दौरे भी किए। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिग्विजय, कमलनाथ के नेतृत्व में अपने बेटे जयवर्धन सिंह को सियासत में सेट करने की संभावनाएं देख रहे हैं। वजह 1993 का कर्ज हो या बेटे को सेट कराने की कोशिश, दिग्विजय खुलकर कमलनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। ताजा कुर्ताफाड़ बयानों का असर अब कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। मप्र में कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में वापसी। इसके लिए अब कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुनाव के लिए पूरी तरह फ्री हैंड दे दिया है। यानी अब दिग्विजय और कमलनाथ का पूरा फोकस चुनावी रण पर रहेगा। अब कमलनाथ-दिग्विजय अपनी टीम के साथ चुनावी मैदान संभालेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ में संगठन की जिम्मेदारी रहेगी। ताकि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपना अधिक से अधिक समय जनता के बीच दे सकें।

● **कुमार राजेन्द्र**

राजनीतिक हिंदू बनाम व्यक्तिगत

जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता धार्मिक हैं, लेकिन दिग्विजय खुद को कमलनाथ के विपरीत सार्वजनिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष दिखाते हैं। कमलनाथ खुद को सार्वजनिक रूप से हनुमान भक्त कहते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कमलनाथ ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भड़के हुए माहौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धार्मिक शख्सियतों की सेना का मुकाबला करने के लिए साधुओं के समूह को काम पर रखा था। साधु अलग-अलग गांवों में जाते थे और जब गांव वाले देखते थे तो नाथ को आशीर्वाद देते थे। वहीं, दिग्विजय सिंह अपने व्यक्तिगत मामलों में कहीं ज्यादा धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। वह नियमित रूप से पंढरपुर और तिरुपति जैसे स्थानों का दौरा करते रहे हैं और सालभर कई उपवास रखते हैं। हालांकि वह आरएसएस, भाजपा और इसके द्वारा चलाए जा रहे हिंदुत्व के खुले तौर पर आलोचक भी हैं। सार्वजनिक मंच और मीडिया से बात करके दिग्विजय अक्सर भाजपा के हिंदुत्व की आलोचना करते हैं। भगवा आतंकवाद, पुलवामा हमले और बाटला हाउस मुठभेड़ के बारे में दिग्विजय सिंह के आरोपों और आक्षेपों ने कई बार कांग्रेस को अजीब स्थिति में डाल दिया था।

हाईटेक होगी मेट्रो

5 साल में डेढ़ गुनी हुई लागत

मेट्रो ट्रेन परियोजना के एमडी मनीष सिंह के मुताबिक इंदौर में इसका किराया नॉमिनल रखने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा ट्रेन में स्टेशन सिग्नलिंग और कंट्रोल सेंटर विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीकी से तैयार किए जा रहे हैं। इंदौर में ही 10 हजार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। मेट्रो रेल परियोजना पर फरवरी 2019 में काम शुरू हुआ था। जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन कोविड के कारण काम के पिछड़ने के कारण निर्माण लागत में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में जो रूट एलाइनमेंट किया गया था उसमें मेट्रो की लागत 7500 करोड़ रुपए तय की गई थी लेकिन बीते 5 वर्षों में 50 फीसदी लागत की बढ़ोतरी होगी। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 25 ट्रेनें लाई जा रही हैं। एक ट्रेन में तीन कोच होंगे। इस हिसाब से 1 दिन में 7 लाख लोग सफर कर सकेंगे। 2026 के बाद इंदौर जब पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन के मूवमेंट के लायक होगा, तब एक कोच में स्टैंडिंग और सिटिंग मिलकर 300 सवारी आ सकेंगी। एक ट्रेन में एक बार में तीनों कोच में 900 यात्रियों के सफर करने की व्यवस्था होगी। इंदौर की मेट्रो ट्रेन फिलहाल ड्राइवर चलाएंगे लेकिन ट्रेन की तकनीक पूरी ड्राइवरलेस है, जो भविष्य में बिना ड्राइवर के भी चलाई जा सकेगी।

भोपाल और इंदौर मेट्रो कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होगी, जिसमें अनअटेंडेंट आब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डिरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा ट्रेन के संचालन के लिए इनबिल्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सुरक्षा प्रणालियों के कारण जहां ट्रेन में सफर आरामदायक होगा। वहीं यात्रियों को पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। मप्र मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो ट्रेन के कोच और स्टेशन के साथ अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें कैप्चर होने वाले वीडियो से संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा मिलान कर वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम के जरिए उसकी पहचान की जाएगी, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम की मदद ली जाएगी। इसकी मदद से अपराधियों का डाटा तैयार किया जाएगा। जिसमें अपराधियों और गुमशुदा बच्चों के फोटो अपलोड किए जाएंगे। अपराधी जैसे ही कैमरे के संपर्क में आएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम को मेट्रो के सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। लंबे समय तक वीडियो फुटेज संरक्षित रखे जा सकेंगे। खास बात यह होगी कि इस सिस्टम के तहत चश्मा पहने हुए व्यक्ति की पहचान करना भी आसान होगा।

मेट्रो प्रोजेक्ट में अनअटेंडेंट आब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा। इस सिस्टम की सहायता से मेट्रो और प्लेटफार्म पर हर वस्तु पर मेट्रो के संचालन के दौरान सुरक्षाकर्मी बारीक नजर रखेंगे। ऐसे में ऐसा कोई भी सामान जिसका कोई दावेदार नहीं होगा। उसे तुरंत ही प्लेटफार्म से हटाया जाएगा। डिरेलमेंट डिटेक्शन सिस्टम के जरिए ट्रैक पर किसी तरह की बाधा के होने पर या मेट्रो ट्रेन के डिरेलमेंट होने पर तुरंत जानकारी मिलेगी। ऐसे में ट्रेन को समय पर रोका जा सकेगा। इससे दोनों ओर से चल रही मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता होगी। मेट्रो के संचालन का सिस्टम पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी से लैस होगा। इनबिल्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के कारण इसे हैक करना लगभग नामुमकिन होगा। साथ ही इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर ट्रेन का संचालन सही रास्ते पर है।

भोपाल और इंदौर में मेट्रो स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था लागू होने के बाद स्टेशनों पर टोकन और मेट्रो कार्ड से एंट्री-एग्जिट हो पाएगी। स्टेशनों पर ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए एंट्री और एग्जिट बनाने और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इस पर केंद्र सरकार करीब 230 करोड़ रुपए खर्च करेगा। काम को पूरा करने की डेडलाइन 48 महीने रखी गई है। मेट्रो के अफसरों ने बताया कि 230 करोड़ रुपए से डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनों के इंस्टालेशन और कमिशनिंग से लेकर उसकी टेस्टिंग के तमाम काम किए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सबसे पहले करोंद से एम्स के बीच पहले रूट पर काम किया जा रहा है।

भोपाल में करोंद से एम्स रूट पर 16 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें करोंद चौराहा, कृषि उपज मंडी, डीआईजी बंगला, सिंधी कॉलोनी, नादरा बस स्टैंड, भोपाल रेलवे स्टेशन, भारत टॉकीज, पुल बोगदा, ऐशबाग स्टेडियम के पास काम किया जाएगा। स्टेशन परिसर में टोकन लेने के लिए टिकट वेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही स्टेशन परिसर में टोकन लेने के लिए काउंटर भी खोले जाएंगे। यहां पर मेट्रो कार्ड बनवाने की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। यहीं से कार्ड रिचार्ज भी करवा पाएंगे। अभी तक सुभाष नगर अंडरब्रिज के पास, मैदा मिल केंद्रीय विद्यालय, एमपी नगर, सरगम सिनेमा, हबीबगंज कॉम्प्लेक्स, अलकापुरी और एम्स के पास स्टेशन बनाने का काम करीब-करीब पूरा हो गया है। स्टेशन का काम पूरा होने के बाद यहां मशीनों का इंस्टालेशन किया जाएगा।

मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट पर टोकन और कार्ड टच करने के बाद एंट्री मिलेगी। नए सिस्टम के लागू होने के बाद व्यक्ति को मेट्रो में सफर के लिए स्टेशन में बने काउंटर से टिकट की जगह टोकन मिलेगा। इसका उपयोग करने से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी। मेट्रो से उतरने के बाद आपको स्टेशन से बाहर निकलते समय इस टोकन को एग्जिट पर डालना होगा। इसके बाद ही आप बाहर आ पाएंगे। इसी तरह मेट्रो कार्ड का भी उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि इसे आप अपने पास रिचार्ज कराकर रख पाएंगे। मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करने की सुविधा दिल्ली में मोबाइल पर भी शुरू हो गई है। इसके शुरू होने के बाद व्यक्ति को बार-बार स्टेशन पर जाकर रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जितने का रिचार्ज कराएंगे। उतनी राशि कार्ड सफर के लिए तय किराए से कट जाएगी। ओटिस इंडिया, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स और मूविंग वॉकवेज बनाने वाली, दुनिया की प्रमुख कंपनी ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी, भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बेंगलुरु स्थित अपने कारखाने से 255 एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स लेकर इंस्टाल करेगी। गौरतलब है कि यह मप्र में पहली मेट्रो लाइन्स हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

आपदाओं की गाज

आपदा आने पर मुश्किल में पड़ जाते हैं किसान

रिपोर्ट की प्रस्तावना में एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंगयु ने लिखा है कि कृषि आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि वो प्रकृति और जलवायु पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बार-बार आने वाली आपदाएं खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रणालियों की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनके मुताबिक रिपोर्ट में एफएओ की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, इन जोखिमों को संबोधित करने और कृषि प्रथाओं और नीतियों में आपदा जोखिम प्रबंधन को शामिल करने के तरीके सुझाए गए हैं। छोटे किसान जो अपनी फसलों के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं, वो आपदा आने पर मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखा जाए तो कृषि खाद्य प्रणालियों की सबसे कमजोर कड़ी हैं। जो इन आपदाओं का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। ऐसे में किसानों को सिखाना की वो अपने खेतों को आपदाओं से कैसे बचा सकते हैं। उनकी फसलों को बचाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह उन्हें कहीं ज्यादा सशक्त बनाएगा। इन नए तरीकों का उपयोग, पुराने तरीकों की तुलना में 2.2 गुना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है।

मप्र में हर साल बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश के कारण फसलें चौपट हो रही हैं। इससे किसानों का हर साल हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन आपदाओं की गाज केवल मप्र ही नहीं बल्कि दुनियाभर के किसानों पर गिर रही है। पिछले तीन दशकों में किसानों को आपदाओं के चलते करीब 316.4 लाख करोड़ रुपए (380,000 करोड़ डॉलर) का नुकसान उठाना पड़ा है। मतलब कि इन आपदाओं के कारण किसानों को हर साल फसलों और मवेशियों के रूप में औसतन 10.24 लाख करोड़ रुपए (12,300 करोड़ डॉलर) की चपत लग रही है। जो कृषि के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब पांच फीसदी है। यह जानकारी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट, द इम्पैक्ट ऑफ डिसास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में सामने आई है, जिसे 13 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रमुख कृषि उत्पादों का होता नुकसान भी बढ़ रहा है। पिछले 30 वर्षों के दौरान अनाज को हर वर्ष औसतन 6.9 करोड़ टन का नुकसान हो रहा है, जो 2021 में फ्रांस में अनाज की कुल पैदावार के बराबर है। इसी तरह फल, सब्जियों और गन्ने की फसलों में सालाना करीब चार करोड़ टन का नुकसान दर्ज किया गया, जो 2021 में जापान और वियतनाम में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन के बराबर है। इन आपदाओं से हर वर्ष औसतन 1.6 करोड़ टन मांस, अंडे और डेयरी उत्पाद बर्बाद हो रहे हैं जो मैक्सिको और भारत में 2021 में हुए इनके कुल उत्पादन से मेल खाता है।

यदि देशों और क्षेत्रों के आधार पर देखें तो इस नुकसान में काफी अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार इन आपदाओं से कृषि को सबसे ज्यादा एशिया में नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की बारी आती है। हालांकि जहां एशिया में यह नुकसान कृषि मूल्य का केवल चार फीसदी था, वहीं अफ्रीका में, वो करीब आठ फीसदी दर्ज किया गया। इसी तरह यदि उप-क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो यह अंतर और भी बड़ा था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तीन दशकों में आपदाओं ने तुलनात्मक रूप से निम्न और निम्न से मध्यम आय वाले देशों में कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो उनके कृषि के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 15 फीसदी तक है। हालांकि यदि कुल घाटे की बात करें तो समृद्ध और मध्यम आय वाले देशों को अधिक नुकसान हुआ। वहीं कम आय वाले देशों, उनमें भी विशेष रूप से छोटे विकासशील द्वीपीय देशों (एसआईडीएस) को भी इससे अच्छा-खासा नुकसान पहुंचा है, जो उनकी कृषि के कुल सकल घरेलू उत्पाद का करीब सात फीसदी है।

गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में आपदाओं को किसी समाज या समुदाय के कामकाज में गंभीर व्यवधान के रूप में परिभाषित किया है। इनमें प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आक्रामक कीटों के हमले और कोविड-19 महामारी तक शामिल हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार 70 के दशक में इन आपदाओं की संख्या जो हर साल 100 दर्ज की गई थी, वो पिछले 20 वर्षों में 300 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर प्रति वर्ष 400 पर पहुंच गई है। देखा जाए तो इन आपदाओं की केवल संख्या ही नहीं आवृत्ति, तीव्रता और जटिलता भी बढ़ रही है। वहीं अनुमान है कि भविष्य में हालात और बदतर हो सकते हैं, क्योंकि जलवायु संबंधी आपदाएं समाज और पर्यावरण में पहले से मौजूद समस्याओं को और बदतर बना देती हैं। यह अपनी तरह की पहली बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें एफएओ ने फसलों और पशुधन से जुड़े कृषि उत्पादन पर आपदाओं के प्रभाव का आंकलन किया है। हालांकि रिपोर्ट ने यह भी माना है कि यदि हमारे पास मछली पालन, जलीय कृषि और वानिकी में हुए नुकसान के पर्याप्त डेटा होते तो नुकसान के यह आंकड़े कहीं ज्यादा होते। रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि, जब खतरे प्रकट होते हैं, तो वे कई प्रणालियों और क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इन समस्याओं के पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, जनसंख्या वृद्धि, महामारी से जुड़ी आपात स्थिति, भूमि का गलत तरीके से होता उपयोग, युद्ध और पर्यावरण को होता नुकसान जैसे कारक होते हैं।

किसी आपदा में कितना नुकसान होता है यह इस बात से तय होता है कि खतरा कितना बड़ा और कितनी तेजी से फैलता है। साथ ही स्थिति कितनी कमजोर थी और उनके रास्ते में कितने लोग या संपत्ति आती है उस पर भी निर्भर करता है। कभी-कभी, यह चरम आपदाएं ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। उदाहरण के लिए जब पाकिस्तान के सिंध में मानसून के दौरान भारी बारिश के बाद बाढ़ आई थी, तो उसने लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे कृषि और खाद्य सुरक्षा पर भारी असर पड़ा था। ऐसे में आपदाएं कृषि से जुड़े सभी क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रही हैं, रिपोर्ट इस बारे में आंकड़ों और जानकारी को तेजी से बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। देखा जाए तो यह आंकड़े ऐसे तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो आंकड़ों पर आधारित प्रभावी निर्णय लेने में मददगार साबित हो सकता है।

● **प्रवीण सक्सेना**

19 प्रतिशत बच्चे अल्प पोषित

मप्र में कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन वह उतना प्रभावी नहीं हो रहा है, जितना सरकार को उम्मीद है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की रिपोर्ट में मप्र में करीब 78 हजार बच्चों में कुपोषण मिला है। ये वो बच्चे हैं, जो रोजाना आंगनबाड़ी पहुंचते हैं। रिपोर्ट जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 की है जो दो जून को जारी हुई है। पिछली तिमाही (अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022) की रिपोर्ट की तुलना में भोपाल समेत सात संभागों में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक मप्र में 19 प्रतिशत बच्चे अल्प पोषित (मध्यम कुपोषित) और 6.5 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर तीव्र कुपोषित हैं। लेकिन धरातल पर की जाने वाली माप जोख कोई और ही कहानी बयान करती है। राज्य में कितने बच्चे कुपोषित हैं, इसी में असमंजस की स्थिति है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मप्र में 19 प्रतिशत बच्चे अल्प पोषित (लंबाई के अनुसार कम वजन) हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार केवल 3.93 प्रतिशत बच्चे ही कुपोषित हैं।

मप्र सरकार द्वारा जून 2022 में की गई वृद्धि निगरानी में 60.46 लाख बच्चों में से महज 2.008 लाख बच्चे (3.32 प्रतिशत) ही मध्यम कुपोषित पाए गए और केवल 36580 बच्चे (0.60 प्रतिशत) ही अति गंभीर तीव्र कुपोषित हैं। इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि लगभग 12 लाख मध्यम कुपोषित बच्चों में से 10 लाख बच्चों की वास्तविक पोषण स्थिति को जांचा ही नहीं जा सका है। अति गंभीर कुपोषण एक आपदा है। लगभग 3.60 लाख बच्चे इस श्रेणी में हैं, लेकिन 90 प्रतिशत अति गंभीर कुपोषित बच्चे नजर से ओझल हैं। राज्य की रिपोर्ट को अगर स्वीकार कर लिया जाए, तो मप्र अब एक कुपोषण मुक्त प्रदेश माना जाएगा, क्योंकि 5 प्रतिशत से कम होने पर कुपोषण को नगण्य ही माना जाता है।

गौरतलब है कि मप्र सरकार कुपोषण के खिलाफ लगातार काम कर रही है। जुलाई-अगस्त 2015 में बहुत जोश-खरोश के साथ आंगनबाडी केंद्रों में दूध देने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि प्रोटीन के लिए अंडे नहीं देने थे, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद दूध लुप्त हो गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से पोषण आहार के लिए स्वयं सहायता समूहों को मार्च से जुलाई-22 के बीच गेहूं-चावल नहीं मिला, क्योंकि व्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा था। अप्रैल-मई 2022 में कहा गया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पारदर्शी डिब्बों में लड्डू, नमकीन, मठरी, भुना चना, गुड़ आदि रखा जाएगा। यह पहल इतनी अधिक पारदर्शी रही, दिखाई ही नहीं दी। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और उठाया गया है। पहले मप्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, पानी, शौचालय, वजन मशीन की जानकारी वेबसाईट पर सबके लिए उपलब्ध होती थी। पहले यह भी देखा जा सकता था कि किस आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे मध्यम या अतिगंभीर तीव्र कुपोषित हैं। अब प्रदेश में केवल तीन लोग यह जानकारी देख पाते हैं, क्योंकि मप्र के लोगों ने कुपोषण से संबंधित पहलुओं पर निगाह रखना शुरू कर दिया था और प्रश्न पूछने लगे थे।

मप्र के 97 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को 7 कारखानों से टेक होम राशन भेजा जाता है। इसे मप्र में विकेंद्रीकरण कहा गया है। ऐसे विकेंद्रीकरण का परिणाम सिंगरौली में नजर आया। वहां नवानगर थाना क्षेत्र में एक दुकान से 12 बोरी पोषण आहार (लगभग 480 पैकेट) बरामद हुआ। मप्र में शासन व्यवस्था की दृढ़ मान्यता है कि व्यवस्था को मशीनी और तकनीकी बना देने से कुपोषण में कमी आ जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण आहार भले न पहुंच पाया हो, लेकिन केंद्रों की निगरानी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन खरीदकर दिए गए हैं। इस वक्त भी मप्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 35.7 प्रतिशत बच्चे ठिगनेपन के शिकार हैं। झाबुआ (49.3 प्रतिशत), कटनी (49.5 प्रतिशत), सतना (49.4 प्रतिशत), बड़वानी 45.8 प्रतिशत, छतरपुर (45.1 प्रतिशत और श्योपुर (45.8 प्रतिशत) में ये मानक और चिंताजनक हैं। कोई भी बच्चा ठिगनेपन का शिकार तभी होता है, जब उसका परिवार और समुदाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुपोषण से ग्रस्त रहते हुए खाद्य असुरक्षा में रहता है। यह कुपोषण एक पीढ़ी में कम होता भी नहीं है, लेकिन मप्र सरकार ने 24-25 मई 2022 को साफ-साफ कह दिया था कि बस, डेढ़ साल में मप्र से कुपोषण खत्म हो जाएगा।

जिस तरह के कुपोषण की स्थिति मप्र में रही है, उसका बहुत सीधा जुड़ाव राज्य में शिशु और बाल मृत्यु दर के साथ भी स्थापित होता है। राज्य की बाल मृत्यु दर और प्रदेश में होने वाले सभी जीवित जन्मों की संख्या के आंकलन से यह समझ आता है कि मप्र में इक्कीसवीं सदी के पहले 22 सालों में लगभग 3.96 करोड़ जीवित जन्म हुए हैं, और अगर औसतन और बाल मृत्यु दर लगभग 70 प्रति हजार जीवित जन्म रही है। इस मान से 27.72 लाख बच्चों की मृत्यु पांच साल से कम उम्र में हुई है, जिनमें से लगभग 10 प्रतिशत में अतिगंभीर तीव्र कुपोषण मृत्यु का एक प्रत्यक्ष कारण रहा है, लेकिन इसके मूल कारणों का विश्लेषण करके बच्चों के गरिमामय जीवन के मूल अधिकार को सुनिश्चित करने के बजाय, कुपोषण को प्रचार के एक अवसर के रूप में तब्दील कर दिया गया।

● **लोकेंद्र शर्मा**

मालवा के ट्राइबल जिलों में ज्यादा कुपोषण

धार में 2 हजार 968 गंभीर कुपोषित बच्चे मिले हैं। मध्यम कैटेगरी की भी संख्या 7,365 है। इसी तरह बड़वानी में भी 1313 गंभीर हैं, जबकि 3,878 कम कुपोषित हैं। श्योपुर जिला जो कभी कुपोषण के मामले में सुर्खियों में था, वहां गंभीर श्रेणी में 191 बच्चे और मध्यम में 408 बच्चे ही मिले। यह महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सुखद हो सकता है। आदिवासी जिले डिंडोरी में भी यह संख्या गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 154 मिली है। सबसे कम आगर में 47 और हरदा में 64 बच्चे गंभीर स्थिति में मिले हैं। संभागवार स्थिति देखें तो इंदौर संभाग (आलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन व इंदौर) में सर्वाधिक 6 हजार 491 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं, जबकि कम कुपोषण के शिकार 16 हजार 230 हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 की तिमाही रिपोर्ट में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 20 हजार 728 थी, जो ताजा तिमाही रिपोर्ट में 21 हजार 631 हो गई। भोपाल समेत सात संभागों ग्वालियर, इंदौर, चंबल, रीवा, सागर और उज्जैन में गंभीर कुपोषित बच्चे ताजा तिमाही रिपोर्ट में पिछली बार से ज्यादा मिले हैं।

मासूमों के सौदागार

कर्फ्यू वाली माता मंदिर से कन्या भोज के नाम पर बच्चियों को अगवा करने वाली अर्चना सैनी ने एक बच्ची का सौदा कर लिया था। उसके मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि मप्र के बाहर के एक खरीदार से सौदा लगभग तय था। मामला कीमत को लेकर अटका था। खरीदार 10 हजार रुपए में बच्ची चाह रही थी। इस पर अर्चना ने कहा कि इतने में तो कुत्ता भी नहीं मिलता। ये इंसान की बच्ची है। इसके तो हम लाखों ले सकते हैं। बाद में अर्चना ने बच्ची को ले जाने के लिए कार का इंतजाम करने को कहा। पुलिस को चारों आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन मिले हैं। इनमें कुछ कीपैड फोन भी हैं। इन सभी की कॉल डिटेल और खरीदने वाले की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि अर्चना का लिव इन पार्टनर वीजा का काम करता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं बच्चों को दूसरे देशों में तो नहीं बेचा जाता था। इधर, गिरोह की सरगना अर्चना सैनी (38), उसके लिव इन पार्टनर निशांत रामास्वामी (32), अर्चना के बेटे सूरज सैनी (19) और उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान बानो (19) को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। गिरोह में अर्चना की नाबालिग बेटी भी शामिल है। उसे बालिका गृह भेजा गया है।

गिरोह के पास से 40 बैग मिले हैं। इनमें 70 जोड़ी कपड़े ऐसे थे, जिनसे टैग तक नहीं हटे थे। चार विदेशी नस्ल के महंगे डॉग्स के अलावा पर्शियन बिल्ली इनके पास थी। दिखावे के लिए सेकंड हैंड मर्सडीज कार पांच लाख रुपए में दिल्ली से खरीदी थी। आरोपी चार महीने पहले भोपाल आए थे। वे करीब 3 महीने तक जेके रोड स्थित मिनाल में किराए पर रहे। इसके बाद कोलार स्थित इंग्लिश विला में किराए पर मकान लिया। अर्चना के घर पर मिली ढाई साल की अकीरो और तीन महीने की एंजल में से एक को उसने दिल्ली की एक महिला डॉक्टर से लिया था। पुलिस ने डॉक्टर की पहचान कर ली है। आरोपियों ने बताया कि डॉक्टर नोएडा और फरीदाबाद के कुछ अस्पतालों में जाती है। वह लिव इन या अन्य रिश्तों में रहने वाली लड़कियों के गर्भवती होने पर डिलीवरी कराने के बाद बच्चा लेकर उन्हें बेचने के धंधे में लिप्त है। अर्चना और उसका परिवार उसकी मदद करता है।

अगवा की गई बच्चियों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती थी। वे खौफ में रहें और किसी से बात न कर सकें, इसलिए उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मानव तस्करी का पूरा रैकेट दो अलग-अलग गैंग के तौर पर बंटा था। भोपाल में पकड़ी गई गैंग के सदस्य केवल बच्चों को उठाने का काम करती है। दिल्ली की गैंग की जिम्मेदारी सौदा करने की थी। पुलिस मप्र में भी इनका नेटवर्क खंगाल रही है।

प्रदेश से हर रोज 32 बच्चे लापता हो रहे हैं। साल 2022 में 11,717 बच्चे गायब हुए, जिनमें 8,844 लड़कियां थीं, जबकि 2873 लड़के थे। हालांकि यह अच्छी बात है कि लापता लड़कियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में लड़कियों के गायब होने की दर में 6 फीसदी गिरावट आई है। लेकिन लड़कों की संख्या बढ़ गई है। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी में कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) के अनुसार, बच्चों की गुमशुदगी के 75 फीसदी मामलों में पीड़िता लड़की थी। साल 2022 में प्रतिदिन 24 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। लापता लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में तीन गुना अधिक दर्ज की गई। लापता बच्चों में 75 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियां थीं। लड़कियों की संख्या काफी अधिक होने की प्रवृत्ति पिछले 5 वर्षों से लगातार बनी हुई है।

क्राई (उत्तर) की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा का कहना है कि घरेलू कामकाज में मांग, व्यावसायिक देह व्यापार के कारण वे गुम हो रही हैं। वहीं, घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा का शिकार होकर भी लड़कियां घर से भाग जाती हैं। सोहा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र में सस्ते कामगारों की जरूरत बढ़ी है। ऐसे में बाल मजदूरी की मांग के कारण बच्चे लापता हो रहे हैं। सोहा ने बताया कि घर से भागने वाली बच्चियां नासमझी में घर छोड़ देती हैं। कई बार वे बेहतर जीवन की तलाश में कम उम्र में घर छोड़ने का भारी जोखिम उठा लेती हैं। गायब होने वाली लड़कियां ज्यादातर कम आय वाले और हाशिए पर रहने वाले परिवारों से आती हैं। यह लड़कियां आसानी से तस्करी और अपहरण का निशाना बन जाती हैं। मप्र में पिछले वर्षों की तुलना में बाल तस्करी बढ़ी है। क्राईम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बाल तस्करी के मामलों की संख्या साल 2020 में 33 से बढ़कर साल 2021 में 52 हो गई। बाल तस्करी के मामलों में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

● **राकेश ग्रोवर**

साल दर साल ज्यादा गायब हो रहे बच्चे

वर्ष 2018 में मप्र से 10,038 बच्चे गायब हुए थे, इनमें 7564 लड़कियां, जबकि 2464 लड़के थे। साल 2019 में कुल 11,022 बच्चे गायब हुए, जिसमें 8572 लड़कियां और 2450 लड़के थे। वर्ष 2020 में 8751 बच्चे लापता हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 7230 जबकि 1521 लड़के थे। साल 2021 में 11,607 बच्चे गायब हुए, जिनमें 9407 लड़कियां और 22 लड़के थे। वर्ष 2022 में कुल 11,717 बच्चे गायब हुए, इसमें 8844 लड़कियां और 2873 लड़के शामिल हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। साल 2022 में इंदौर में 977 मामले दर्ज हुए। जबकि भोपाल में 661 बच्चे गायब होने के मामले दर्ज हुए हैं। शहरी बच्चे अधिक गायब हो रहे हैं। साल 2022 में इंदौर में 245 लड़के और 732 लड़कियां गायब हुईं। भोपाल में 436 लड़कियां और 225 लड़के गायब हुए। धार में 470 लड़कियां और 84 लड़के लापता हुए। जबलपुर में 427 लड़कियां और 170 लड़के गायब हो गए। बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर में 346 लड़कियां और 115 लड़के गुम हुए।

गायब हो रही हरियाली

मप्र में हरियाली बढ़ाने के लिए हर साल पौधारोपण होता है और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हरियाली गायब हो रही है। खासकर प्रदेश के महानगरों में तो स्थिति विकट होती जा रही है। इंदौर में आसपास तो हरियाली है, लेकिन शहर के भीतर सूखे की स्थिति है। यह तब है, जब पांच साल में निगम ने पौधारोपण पर 10 करोड़ खर्च किए हैं। हालांकि 75 फीसदी रकम सजावटी पौधों पर खर्च की गई, जिसके कारण 2020 में इंदौर का जो ग्रीन कवर 66 वर्ग किमी था वह 2021 में 54 रह गया था। निगम अब 74 वर्ग किमी होने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में यह 60 से भी कम है। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. ओपी जोशी व एसडीओ वन कैलाश जोशी के साथ शहर के ग्रीन कवर की पड़ताल की गई तो पता चला निगम 1126 गार्डन व अन्य ग्रीन फील्ड का एरिया जोड़कर ग्रीन कवर 74.50 वर्ग किमी बता रहा है, जबकि ग्रीन कवर पेड़ों की कैनोपी (छांह का दायरा) होती है। हरियाली में कमी की बड़ी वजह बड़े निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई और नए ग्रीन एरिया विकसित नहीं किया जाना है। शहर में हरियाली के लिए दो सिटी फॉरेस्ट, ट्रेंचिंग ग्राउंड, पितृ पर्वत, बिजासन टेकरी और 1126 गार्डन ही बचे हैं। रिंग रोड के आसपास का ग्रीन बेल्ट ही बचा है।

सुपर कॉरिडोर के सेंट्रल डिवाइडर में मेट्रो आने के कारण यहां का पूरा ग्रीन बेल्ट खत्म हो गया। ऐसे ही नई-नई योजनाओं के कारण लगातार ग्रीन कवर घटता जा रहा है। दूसरी तरफ निगम का दावा है कि ग्रीन कवर 74.50 वर्ग किमी हो गया है। इस पर पड़ताल करने पर खुलासा हुआ यह कागजी हेराफेरी है। पर्यावरणविद डॉ. ओपी जोशी, एसडीओ कैलाश जोशी का कहना है कि ग्रीन कवर नहीं बढ़ रहा है बल्कि निगम ग्रीन बेल्ट या गार्डन की जमीनों पर ही ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर पेड़ों का घनत्व बढ़ा रहा है। इसमें भी ज्यादातर सजावटी पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनसे ज्यादा लाभ मिलना मुश्किल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि निगम जो 74.50 वर्ग किमी का ग्रीन कवर बता रहा है उसमें 30 प्रतिशत हरियाली 1980 के दशक में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत लगाए गए पेड़ों से है। तब तेजी से बढ़ने वाले पेड़ जैसे सुबबुल, पेल्टोफोरम, गुलमोहर व अन्य को वन विभाग ने लगवाया था, ताकि जंगल का बोझ कम हो सके। पर इन पेड़ों की आयु भी सिर्फ 40 साल है, यही पेड़ आंधी-तूफान में गिर रहे हैं। निगम द्वारा ही 2020 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भेजी गई जानकारी निकाली गई तो खुलासा हुआ तब इंदौर का ग्रीन कवर 66 वर्ग किमी था। 2021 में उद्यान विभाग से तैयार की गई जानकारी के मुताबिक शहर का ग्रीन कवर 12 वर्ग किमी कम होकर 54 पर आ गया था। 2023 में निगम द्वारा तैयार की गई जानकारी में ग्रीन कवर 74.50 वर्ग किमी बताया गया है। इसकी पड़ताल की गई तो बड़ा खुलासा हुआ।

विशेषज्ञों के मुताबिक जहां 100 की क्षमता है वहां निगम 125 पेड़ ठूंस रहा है। इससे घनत्व भले अधिक आएगा, लेकिन हरियाली को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधे पनप नहीं पाएंगे। इससे ग्रीन कवर में कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा **मियावाकी पद्धति** से पौधारोपण किया जा रहा है। ऐसा ही एक गार्डन एयरपोर्ट के पास तैयार किया गया है। मेट्रो के लिए सुपर कॉरिडोर का 11 किमी लंबा ग्रीन बेल्ट हटाया गया, यहां बड़ी मुश्किल से पेड़ तैयार हुए थे। अब जरूरत है राजस्व रिकॉर्ड में नया एरिया नोटिफाई करने की। पहले मिलों की जमीनों पर सिटी फॉरेस्ट तैयार करने की योजना बनी थी लेकिन इस पर भी अमल नहीं हुआ। शहर में लगभग 6 लाख पेड़ बचे हैं, जिनमें से 25 प्रतिशत पेड़ वे हैं, जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। यही कारण है कि जरा सी तेज आंधी में शहर में सैकड़ों पेड़ या उनकी शाखाएं टूट रही हैं। पांच सालों में निगम ने 10 करोड़ रुपए पौधारोपण पर खर्च किए हैं। ज्यादातर खर्च डिवाइडरों पर सजावटी पेड़-पौधे लगाने में किया है। शहर सुंदर तो दिखने लगा है लेकिन आबोहवा को फायदा पहुंचाने वाले पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जनवरी में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन (पीबीडी) में निगम ने 14500 सजावटी, और 46500 स्के फीट घास लगाई। इसमें से 70 प्रतिशत पौधे बर्बाद हो चुके हैं। नेहरू पार्क को ऑफिस पार्क बना दिया गया है। होलकर काल में नौलखा में 9 लाख से ज्यादा पेड़ थे। विश्राम बाग व फलबाग में हजारों पेड़ रिडेवलपमेंट के नाम पर कट गए।

भोपाल में भी विकास या निर्माण के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। अरेरा कॉलोनी में जिस स्थान पर वीर दुर्गादास की प्रतिमा लगी थी। वहां चौराहे को संकरा किया जाना था। ऐसे में नगर निगम ने वीर दुर्गादास की प्रतिमा को विस्थापित किया जाना था। इसके लिए निगम के अधिकारियों ने प्रतिमा को सड़क किनारे स्थापित करने के लिए साइड वर्ज में खड़े पुराने पेड़ों को काट दिया। वहीं प्रतिमा के लिए कांक्रीट का बेस बनाया और इसके बगल में लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाकर हरियाली को नष्ट किया। वर्ष 2021 में राजधानी परियोजना द्वारा सेंट्रल व साइड वर्ज पर 692 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया था, जिनकी संख्या अब बढ़कर करीब 1500 से अधिक हो गई है। इनमें 1100 क्वार्टर, अरेरा कालोनी ई-1 से लेकर ई-8 तक, शाहपुरा, चूनाभट्टी, गुलमोहर, 12 नंबर और लिंक रोड समेत अन्य स्थानों पर सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट खत्म होता जा रहा है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

राजधानी में हरियाली के दुश्मन बने रसूखदार

भोपाल की सड़कों के बीच और किनारे में बनाए गए ग्रीन बेल्ट पर कब्जे हो गए हैं, जिससे यहां हरियाली खत्म होती जा रही है। जबकि करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क के सेंट्रल व साइड वर्ज में पेड़-पौधे लगाकर हरियाली विकसित की गई है। लेकिन रसूखदार और जिम्मेदार मिलकर इस ग्रीन बेल्ट को खत्म करते जा रहे हैं। इसको लेकर राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) ने दो वर्ष पहले किए अतिक्रमणों को चिन्हित किया था, साथ ही इसको लेकर एनजीटी में याचिका भी दायर की गई है। इस मामले में पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे ने एनजीटी में याचिका दायर की है।

बुंदेलखंड किसकी तकदीर चमकाएगा

मप्र के गरीब और सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड में पिछले दो दशकों के चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा की ओर साफ झुकाव दिखा है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि यहां पिछली प्रवृत्ति जारी रहती है या भाजपा के मतदाता आधार में कांग्रेस सेंध लगा सकेगी। पन्ना जिले में हीरे की खदान होने के बावजूद यह क्षेत्र दशकों से सूखा, आर्थिक असमानता, गरीबी और जातिगत संघर्षों से जूझ रहा है। मप्र और उप्र तक फैले बुंदेलखंड की राजनीति मप्र के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक जटिल है। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। चूंकि यह क्षेत्र उप्र की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए यहां समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है, जो निकटवर्ती उत्तरी राज्य में प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उप्र स्थित संगठन अपना आधार बढ़ाने और केंद्रीय राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए मप्र में सत्ता के दो मुख्य दावेदारों भाजपा और कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं।

विधानसभा की 26 सीटों वाले इस इलाके में 2018 के चुनावों में, बसपा और सपा ने बुंदेलखंड में एक-एक सीट हासिल की थी। इन 26 सीटों में से छह अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र मप्र के छह जिलों में फैला हुआ है। 2018 में भाजपा ने 16 और कांग्रेस ने आठ सीटें जीती थीं। हालांकि, सपा विधायक राजेश शुक्ला (बिजावर सीट) बाद में भगवा दल में शामिल हो गए। वर्ष 2018-2023 के दौरान सपा विधायकों के दलबदल और उपचुनाव के बाद, वर्तमान में भाजपा के विधायकों की संख्या 18 है, जबकि कांग्रेस के पास क्षेत्र से सात विधायक हैं। बसपा का एक विधायक है।

बुंदेलखंड का पिछड़ापन राष्ट्रीय फोकस में तब आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगभग डेढ़ दशक पहले इस क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज पर जोर दिया, तब उनकी पार्टी केंद्र में यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रही थी। जानकारों का कहना है कि बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है, औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसरों का अभाव है। इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पलायन दशकों से एक सामान्य घटना रही है। गांधी ने 2008 में इस क्षेत्र का दौरा किया और इसके विकास के लिए एक विशेष पैकेज पर जोर दिया। यूपीए सरकार ने बाद में बुंदेलखंड (मप्र और उप्र के क्षेत्रों को कवर करते हुए) के लिए 7,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की, लेकिन अंतर्निहित स्थानीय भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण चीजें अब तक नहीं बदली हैं। जहां तक चुनावी राजनीति का सवाल है, पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र ने भाजपा की ओर झुकाव दिखाया है। यह क्षेत्र अभी भी पुरानी समस्याओं से जूझ रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि वरिष्ठ भाजपा नेता और मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (जो दिसंबर 2003 में मुख्यमंत्री बनीं, लेकिन उनका कार्यकाल एक साल से भी कम समय तक चला) बुंदेलखंड से आती हैं। टीकमगढ़ जिले की मूल निवासी उमा भारती के नेतृत्व में दिसंबर 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी। कांग्रेस के 10 साल के लंबे शासन के बाद भाजपा सत्ता में आई थी। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री भारती का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम रहा। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस जाति सर्वेक्षण पर जोर देती है, मतदाताओं के बीच रुझान बढ़ता है और वे विपक्षी दल की ओर बढ़ते हैं, तो बुंदेलखंड में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह गेम चेंजर होगा। इसके अलावा, अपनी आर्थिक विषमता, घोर गरीबी और तीव्र जातिगत संघर्षों के साथ बुंदेलखंड, (मुख्यमंत्री) शिवराज सिंह चौहान की कल्याणकारी नीतियों और जमीन पर उनके प्रभाव के लिए एक आदर्श परीक्षण मामला है।

प्रदेश भाजपा सचिव रजनीश अग्रवाल ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 2018 से बेहतर प्रदर्शन करेगी और क्षेत्र में अपनी सीटों की संख्या में सुधार करेगी। अग्रवाल का कहना है कि कुछ राजनीतिक समीकरणों के कारण 2018 में बुंदेलखंड की 26 सीटों पर हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। पार्टी ने अब उन समीकरणों को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता तक पहुंचा है। बीना रिफाइनरी, सिंचाई योजनाएं और सड़कों का निर्माण जैसी परियोजनाएं विकास के संकेत हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

भाजपा का दबदबा

मप्र में बुंदेलखंड 6 जिलों सागर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर और निवाड़ी में फैला हुआ है। बुंदेलखंड की कुल 26 विधानसभा सीटों में से सागर जिले में आठ क्षेत्र- सागर, नरयावली, खुरई, देवरी, सुरखी, रहली-गढ़ाकोटा, बीना और बांदा हैं। इनमें से भाजपा के पास छह और कांग्रेस के पास दो सीटें हैं। छतरपुर जिले में छह सीटें महाराजपुर, चंदला, राजनगर, छतरपुर, बिजावर और मलहरा हैं। इनमें से कांग्रेस और भाजपा के पास तीन-तीन सीटें हैं। दमोह जिले में चार सीटें पथरिया, दमोह, जबेरा और हाटा हैं। वर्तमान में, भाजपा विधायक दो सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बसपा और कांग्रेस के पास एक-एक विधायक है। पन्ना जिले में तीन सीट हैं पवई, गुन्नौर और पन्ना। इनमें से दो पर फिलहाल भाजपा और एक पर कांग्रेस का कब्जा है। टीकमगढ़ जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र खरगापुर, टीकमगढ़ और जतारा हैं, जबकि नवगठित निवाड़ी जिले में दो सीटें पृथ्वीपुर और निवाड़ी हैं। इन दोनों जिलों के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भाजपा विधायक कर रहे हैं। पिछले दो दशकों में विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा ने 2003 में 20 सीटें जीतीं, उसके बाद 14 (2008), 20 (2013) और 18 सीटें (2018 चुनावों में 16, जबकि दो सीटें बाद में उपचुनाव में जुड़ी)। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भी अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है। उसने 2003 में केवल दो सीटें जीतीं जबकि इसकी संख्या आठ (2008), छह (2013) और सात (2018 के चुनावों में आठ और उसके बाद उपचुनावों में एक निर्वाचन क्षेत्र की हार) हो गई।

मिशन 2023 का घमासान

बागियों में उलझी भाजपा-कांग्रेस

मप्र में चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनावी समर में प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में 3832 अभ्यर्थियों द्वारा 4359 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इनमें से 460 प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के हैं, जबकि 3372 वे हैं, जो केवल खेल बिगाड़ेंगे। इनमें वे नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने भाजपा-कांग्रेस से बगावत कर तीसरे मोर्चे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की है। ये दलबदलू दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे। इस बार भाजपा-कांग्रेस में इस कदर बगावत हुई है कि उनसे निकले नेताओं से तीसरा मोर्चा भी हरा-भरा हो गया है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में विधानसभा का चुनावी रण सज गया है। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। इस चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के 230-230 प्रत्याशियों ने तो बसपा ने 178, सपा ने करीब 60, आम आदमी पार्टी ने 66 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने करीब 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वास्तविक भारत पार्टी, जनहित पार्टी, विंध्य विकास पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसे दलों ने भी अपने उम्मीदवार कुछ सीटों पर उतारे हैं। सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस में ही होना है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के लिए वे नेता परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिन्होंने बागी होकर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन कर दिया है। अब दोनों पार्टियों की हार-जीत का गणित इन बागियों में उलझ गया है। ये बागी जीतें या न जीतें, अपनी पूर्व पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ेंगे।

भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दांवा कर रही हैं। लेकिन जिस तरह दोनों पार्टियों में अधिकांश प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, उससे पार्टियों के रणनीतिकारों के साथ ही आमजन भी असमंजस में हैं। चुनाव में किसकी जीत होगी अब तो यह 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता तय करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को देखते हुए भाजपा इस चुनाव में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसलिए पार्टी ने मिशन 2023 को फतह करने के लिए तपे तपाए नेताओं को टिकट दिया है। यानी इस बार के चुनाव में भाजपा का एकमात्र फोकस जीत पर है। इसलिए पार्टी ने सारे कायदे और फॉर्मूले दरकिनार कर टिकटों का वितरण किया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा कहते हैं कि भाजपा ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उसमें युवा, अनुभव और ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है जो अच्छे कार्यकर्ता के साथ-साथ सामाजिक कल्याण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस बार पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया है जो इतिहास बनाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। दोनों पार्टियों के दावों के बीच उनकी परेशानी झलक रही है कि बागी उनका खेल न बिगाड़ दें। बागियों का दम पहले ही दिख चुका है। टिकट बंटवारे के बाद दावेदारों के बगावती तेवर के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। पार्टी दो किस्तों में 7 टिकट वापस लेकर नए प्रत्याशियों को दे चुकी है। बगावत का बवंडर भाजपा में भी उठा, लेकिन ज्यादा नुकसान किए बिना थम गया। अभी की स्थिति में 97 सीटें ऐसी हैं, जहां भाजपा को चुनौती कम मिल रही है। ऐसी स्थिति वाली कांग्रेस की 90 सीटें हैं। 43 सीटों पर अभी से कांटे का मुकाबला लग रहा है। जैसे-जैसे जनसंपर्क, दौरे और सभाएं होंगी; यह आंकड़ा ऊपर-नीचे होगा ही।

गौरतलब है कि प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा इस बार किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। शायद इसीलिए पार्टी ने प्रत्याशियों की पांचवीं सूची में जहां विधायकों के टिकट तो काटे लेकिन नए चेहरों पर दांव लगाने के बजाय पुरानों को ही आजमाना बेहतर समझा। वहीं कांग्रेस-सपा से आए एक-एक और दो निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया गया है। जोबट से सुलोचना रावत को टिकट न देकर उनके बेटे का दिया है। बालाघाट में मंत्री गौरीशंकर बिसेन की जगह बेटी मौसम प्रत्याशी हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव हारने वाले 20 पूर्व विधायकों को फिर मौका दिया है। पांचवीं सूची में उम्र सीमा का बंधन नजर नहीं आया। विधायक नागेंद्र सिंह गुढ़ और नागेंद्र सिंह (नागौद) की उम्र 80 वर्ष से अधिक है और इन्हें टिकट दिया गया है।

पुराने मुद्दों पर नई रणनीति से चुनाव

मप्र में पांच साल बाद एक बार फिर चुनावी संग्राम चरम पर है। लेकिन इस बार के चुनाव में न कोई लहर है और न कोई मुद्दा। चुनावी माहौल देखकर कहा जा रहा है कि इस बार पुराने मुद्दों पर ही वार-प्रहार हो रहा है। हालांकि मुद्दे भले ही पुराने हैं, लेकिन रणनीति जरूर नई है। इस बार भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे को घेरने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया है। इस चुनाव में इंटरनेट मीडिया का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इसलिए चुनाव बिना लहर और मुद्दे के भी आक्रामक तरीके से लड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान होगा और इसके ठीक 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नई सरकार तय हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल अब पूर्ण निर्धारित रणनीति के तहत चुनाव मैदान में फिर उतरने को तैयार हैं। पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। मुद्दे वही हैं, जो हर चुनाव में होते रहे हैं। इस बार भाजपा ने किसी नेता का चेहरा तय नहीं किया है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है, वह यह कि राजनीतिक दल ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। जिसमें भाजपा तकनीकी रूप से ज्यादा दक्ष है। जबकि कांग्रेस भी चुनाव में हाईटेक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा के मुकाबले काफी पिछड़ी है। फिलहाल चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों की मीडिया टीमें चौकस हैं। चुनाव के लिए भाजपा ने नया मीडिया सेंटर तैयार किया है। जहां से कांग्रेस पर चुनावी हमले तेज हो गए हैं।

61 सीटों पर बगावत

नामांकन जमा होने के बाद यह बात भी साफ हो चुकी है कि 61 सीटों पर बगावत में भाजपा को 36 और कांग्रेस को 25 सीटों पर अपने नाराज नेताओं की मनुहार करनी होगी। इनमें तमाम नेता इतने प्रभावशाली हैं कि वे बेशक जीत न पाएं लेकिन हार का कारण बन सकते हैं। इसको लेकर दोनों दल सतर्क हो गए हैं। दिग्गजों को मान-मनौव्वल के लिए मैदान में उतारा गया है। भाजपा का दावा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की लगातार बैठकों के बाद नाराज लोगों को काफी हद तक मना लिया गया है लेकिन जिस तरह से नामांकन के अंतिम दिन नाराज लोगों ने नामांकन पत्र भरे, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि नाराजगी थामना इतना भी आसान नहीं है। कांग्रेस का तो इससे भी बुरा हाल है। बेशक भाजपा के मुकाबले कम सीटों पर नाराजगी दिख रही है लेकिन जहां नाराजगी है, वहां अराजक स्थिति भी पैदा होती रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नाम वापसी के बाद क्या स्थिति बनती है।

ग्वालियर-चंबल अंचल में सर्वाधिक बगावत देखी जा रही है। मुरैना की छह में से दो सीटों पर बागी हैं। यहां भाजपा के प्रत्याशी रघुराज कंसाना के खिलाफ पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा से मैदान में हैं। सुमावली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाह के सामने कुलदीप सिकरवार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। भिंड की पांच में से तीन सीटों पर बगावत है। लहार सीट से भाजपा के उम्मीदवार अंबरीश शर्मा के खिलाफ पूर्व विधायक रसाल सिंह चुनावी रण में हैं। अटेर से भाजपा के उम्मीदवार मंत्री अरविंद भदौरिया के खिलाफ पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया बसपा से और भिंड से

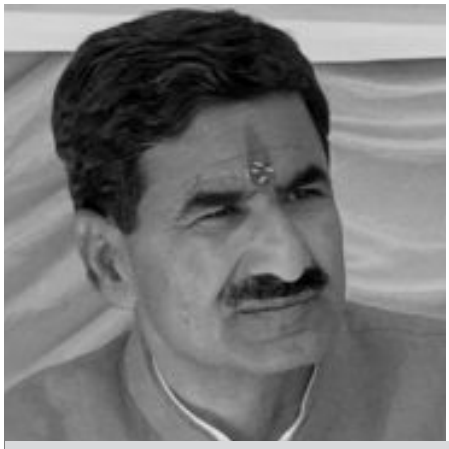

13 फीसदी महिलाओं को नहीं मिला प्रतिनिधित्व

मप्र में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने न केवल वादे किए हैं, बल्कि योजनाओं के साथ ही सौगातों की बौछार की है। लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो पार्टियों ने महिलाओं को बराबरी का हक देने की बजाय उनके हिस्से का भी हक नहीं दिया है। गौरतलब है कि चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी टिकट देने की बात हो रही है लेकिन प्रदेश में किसी भी पार्टी ने 15 फीसदी टिकट भी नहीं दिया है। जबकि मप्र की 16वीं विधानसभा गठन के लिए हो रहे विधानसभा चुनावों में बहुमत की भूमिका 2.72 करोड़ महिलाएं भी निभाएंगी। मौजूदा समय में मप्र सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी तय कर चुकी है। मप्र में कुल मतदाताओं की संख्या 5.60 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को एक स्वर में भाजपा और कांग्रेस के साथ सभी पार्टियों ने समर्थन दिया, लेकिन मप्र विधानसभा चुनाव में किसी ने 33 फीसदी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। भाजपा द्वारा घोषित 230 उम्मीदवारों में से 28 महिलाओं को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने 230 में से 29 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह भाजपा ने मात्र 12.28 और कांग्रेस ने 12.66 फीसदी महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व दिया है। इससे साफ होता है कि, दोनों ही राजनीतिक दलों को महिला प्रत्याशी के जीतने पर पुरुषों की अपेक्षा कम भरोसा है।

भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाह के खिलाफ विधायक संजीव सिंह कुशवाह बसपा से उम्मीदवार हैं।

शिवपुरी की पोहरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कैलाश कुशवाह के खिलाफ प्रद्युमन वर्मा बागी होकर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। टीकमगढ़-निवाड़ी की पांच सीटों में से चार पर बागी मैदान में हैं। टीकमगढ़ सीट से भाजपा के उम्मीदवार राकेश गिरी के खिलाफ पूर्व विधायक केके श्रीवास्तव निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। खरगापुर से कांग्रेस की चंदा सुरेंद्र सिंह गौर के खिलाफ अजय यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निवाड़ी में भाजपा के अनिल जैन के खिलाफ नंदराम कुशवाहा और कांग्रेस के अमित राय के खिलाफ रजनीश पटेरिया बागी होकर मैदान में हैं। जतारा में कांग्रेस की किरण अहिरवार के खिलाफ आरआर बंसल सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह छतरपुर की छह में पांच सीटों पर बगावत है। राजनगर सीट से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद पटैरिया के खिलाफ घासीराम पटेल बसपा से टिकट लेकर मैदान में उतर गए हैं। छतरपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी के खिलाफ डील मनी सिंह भी बसपा से टिकट लेकर आ गए। महाराजपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज दीक्षित के खिलाफ अजय दौलत तिवारी सपा से मैदान में हैं। बिजावर सीट से भाजपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला बबलू के खिलाफ रेखा यादव बसपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतर गईं हैं।

विंध्य-महाकौशल की 11 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने बागी ताल ठोंक रहे हैं। जबलपुर की उत्तर मध्य सीट से भाजपा में टिकट के दावेदार रहे कमलेश अग्रवाल ने बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल इस सीट से डॉ. अभिलाष पांडेय को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। कटनी जिले की मुड़वारा सीट से भाजपा से महापौर पद की प्रत्याशी रहीं ज्योति दीक्षित व उनके पति विनय दीक्षित ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। इसी सीट से पूर्व नगर निगम अध्यक्ष व वर्तमान में पार्षद संतोष शुक्ला ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। भाजपा नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने भी इसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन प्रपत्र जमा किया है। इसी तरह भाजपा से बागी होकर पूर्व राज्यमंत्री मोती कश्यप ने कटनी की बड़वारा सीट से निर्दलीय नामांकन किया। बहोरीबंद सीट पर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी से शंकर महतो ने नामांकन दाखिल किया। दो माह पहले ही वह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। शहडोल के जयसिंह नगर से भाजपा की महिला मोर्चा की पदाधिकारी और शहडोल जिला पंचायत उपाध्यक्ष फूलबती सिंह ने भाजपा से बगावत करके विंध्य जनता पार्टी से नामांकन भर दिया है।

भाजपा नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष (सोहागपुर) रमेश कोल ने भी पार्टी से बगावत कर बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। उमरिया की मानपुर सीट से कांग्रेस की बागी रोशनी सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। जबकि छिंदवाड़ा की चौरई से बंटी पटेल (नीरज ठाकुर) ने कांग्रेस से बगावत कर अपना नामांकन भरा है। बालाघाट के कटंगी से केसर बिसेन ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। सीधी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के तीन बार विधायक रहे केदारनाथ शुक्ला ने निर्दलीय नमांकन दाखिल किया। रीवा की मनगवां सीट से भाजपा के विधायक पंचूलाल प्रजापति ने निर्दलीय और दमोह की जबेरा सीट से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विनोद राय ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। हटा से कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे भगवानदास चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी से नामांकन दाखिल किया है।

मध्य भारत अंचल की 12 सीटों पर बगावत दिख रही है। इसमें भाजपा को सात और कांग्रेस को पांच सीटों पर बागियों का सामना करना पड़ रहा है। गुना से भाजपा की ममता मीणा आप प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं तो भाजपा छोड़कर आए गिरजाशंकर शर्मा को कांग्रेस ने नर्मदापुरम से मैदान में उतार दिया है। भाजपा की भगवती चौरे भी नर्मदापुरम से निर्दलीय मैदान में हैं। बैतूल के भैंसदेही में भाजपा के राहुल चौहान प्रहार जनतंत्र पार्टी से मैदान में हैं। बैतूल जिले की अन्य सीटों पर भी बगावत की स्थिति है। यहां भाजपा से बगावत कर मुकेश जैन, सुधीर यादव व अरविंद तोमर आम आदमी पार्टी के टिकट पर ताल ठोंक रहे हैं। भोपाल उत्तर में कांग्रेस के आमिर अकील, नासिर इस्लाम ने निर्दलीय तथा मोहम्मद सउद ने आम आदमी पार्टी से नामांकन किया है। हुजूर सीट से कांग्रेस के जितेंद्र डागा ने निर्दलीय तथा अशोकनगर की मुंगावली से मोहन ने बसपा से नामांकन दाखिल किया है।

मालवा-निमाड़ में दर्जनों बागियों ने निर्दलीय नामांकन भरे हैं। उज्जैन जिले में महिदपुर से भाजपा के प्रतापसिंह आर्य, बड़नगर में भाजपा के प्रकाश गौड़, शांतिलाल धबाई, श्याम विशनवाणी व कांग्रेस से राजेंद्रसिंह सोलंकी, नागदा-खाचरौद से भाजपा के लोकेंद्र मेहता, धार जिले की धार सीट से भाजपा के पूर्व

दलबदलुओं के सहारे तीसरा मोर्चा

मप्र में प्रत्याशियों के टिकट वितरण के बाद भाजपा और कांग्रेस में बगावत को देख तीसरे मोर्चे की बांछें खिल गई हैं। दोनों पार्टियों के कई नेताओं ने सपा, बसपा और आप का दामन थाम लिया है। इन दलबदलुओं को तीसरा मोर्चा ने हाथों हाथ लिया है और टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। प्रदेश की 12 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बेटिकट चेहरे जीत-हार का समीकरण प्रभावित करेंगे। अगर पिछली बार की तरह करीबी मुकाबला हुआ तो ये सीटें निर्णायक साबित हो सकती हैं। कांग्रेस व भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के बाद जो विद्रोह की स्थिति बनी है, वह दोनों ही दलों की नींद हराम किए हुए हैं। हालत यह है कि एक को शांत कराने के प्रयास किए जाते हैं, तो कई और विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के बड़े नेता अपने स्तर पर इस असंतोष को शांत कराने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इसके बाद भी दावेदार नामांकन फार्म लेने और भरने तक में पीछे नहीं रह रहे हैं। कई सीटों पर तो यह हालात हैं कि दावेदार मौजूदा पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं कई दावेदार दलबदल कर बसपा, सपा व आप जैसे दलों के टिकट पर ताल ठोंकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यह वे बागी नेता हैं, जिनका अपना प्रभाव है, जिसकी वजह से पार्टी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। प्रदेश में बसपा और सपा का उप्र से सटे जिलों में अच्छा प्रभाव है। उनके कोर वोटर बड़े चेहरों के फॉलोअर वोटरों के साथ मिलकर बड़ी ताकत बन जाते हैं। पिछली बार बसपा ने इसी बेल्ट में दो और सपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। बसपा को पिछली बार 6 प्रतिशत के लगभग और आम आदमी पार्टी को एक साल पहले हुए निकाय चुनाव में इतने ही प्रतिशत वोट मिले थे। इसलिए बागी नेताओं का आकर्षण इन पार्टियों की तरफ बढ़ा है। मुरैना के सुमावली सीट से टिकट कटने के बाद अजब सिंह कुशवाहा बागी होकर बसपा से मैदान में उतरने की तैयारी में थे। कांग्रेस ने 25 अक्टूबर को इस सीट से प्रत्याशी बदलते हुए उन्हें टिकट दे दिया। इससे नाराज कुलदीप सिकरवार बसपा में शामिल हो गए और उन्हें वहां से टिकट भी मिल गया। अटेर सीट पर भाजपा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने बसपा का दामन थाम लिया है। पार्टी ने उन्हें अटेर से टिकट दिया है। वे दो बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने यहां से अरविंद सिंह भदौरिया और कांग्रेस ने यहां से हेमंत कटारे को प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार भी यहां त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था।

जिलाध्यक्ष राजीव यादव, मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ से कांग्रेस के बागी श्यामलाल जोकचंद, आलीराजपुर जिले में जोबट से भाजपा नेता और मप्र वन विकास निगम के अध्यक्ष माधोसिंह डावर और आलीराजपुर सीट से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वकीलसिंह ठकराला, झाबुआ में कांग्रेस के जेवियर मेड़ा, भाजपा के धनसिंह बारिया निर्दलीय मैदान में हैं। पेटलावद में कांग्रेस के अकमल डामोर, थांदला से भाजपा के तानसिंह मेड़ा, खरगोन जिले के भगवानपुरा से भाजपा के पूर्व विधायक जमनासिंह सोलंकी, पूर्व विधायक विजय सिंह सोलंकी, महेश्वर से भाजपा के पूर्व राज्यमंत्री स्वर्गीय जगदीश रोकड़े के बेटे रितेश रोकड़े, भाजपा के हर्षवर्धन सिंह चौहान ने निर्दलीय रूप से नामांकन जमा किया है। इसी प्रकार रतलाम जिले में जावरा विधानसभा में कांग्रेस के हिम्मत श्रीमाल और डीपी धाकड़ ने निर्दलीय फार्म जमा किया है। रतलाम जिले के ही आलोट में भाजपा के रमेश मालवीय और कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू पहले ही निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। खंडवा सीट से कांग्रेस के यशवंत सिलावट और मांधाता सीट से भाजपा के संतोष राठौर ने निर्दलीय पर्चा भरा है। महू से कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और देपालपुर से भाजपा के राजेंद्र चौधरी पूर्व में ही निर्दलीय फार्म भर चुके हैं। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन में भाजपा के बागी अखिलेश शाह ने निर्दलीय फार्म भरा है। इसी तरह महू में कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने निर्दलीय फार्म भरा है।

चुनावी मैदान में मुद्दों का वार

इन चुनावों के खत्म होते ही आम चुनाव की भी बिसात बिछ जाएगी। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे को घेरने के लिए मुद्दों को तैयार कर लिया है। मप्र में वैसे तो ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाड़ली बहना नारी सम्मान, बेरोजगारी, अपराध, किसान और सनातन प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन जब स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे तो वे दर्जनों ऐसे मुद्दों को हवा देंगे

वीजेपी ने भाजपा के लिए बढ़ाई परेशान

मप्र विधानसभा चुनाव के लिए विंध्य जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। वीजेपी ने 25 सीटों पर नामों का ऐलान किया है। सतना जिले की मैहर विधानसभा से नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में

उतरेंगे। नारायण ने भाजपा से बागी होकर अपनी अलग वीजेपी बनाई है। त्रिपाठी 2018 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। विंध्य जनता पार्टी ने पहली सूची में 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। सतना से हरिओम गुप्ता, मैहर से नारायण त्रिपाठी, अमरपाटन से शशि सत्येंद्र शर्मा, रैगांव से आरती शर्मा, सेमरिया से हासिफ मोहम्मद अली, त्यौंथर से कमांडो अरुण गौतम, देवतालाब से कुंजबिहारी तिवारी, गुढ़ से शिवमोहन शर्मा, चुरहट से अरुण द्विवेदी, सीधी से वाल्मीकि तिवारी, सिंहावल से आशीष मिश्रा, चितरंगी से रामकृष्ण कोल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सिंगरौली से कुंदन पांडेय, ब्यौहारी से लेखन सिंह, जयसिंहनगर से फूलमती सिंह, जैतपुर से हीरालाल पनिका, अनूपपुर से प्यारेलाल पनिका, पुष्पराजगढ़ से अमृतलाल सोनवानी, बांधवगढ़ से धूप सिंह, मानपुर से राजकुमार बैगा, शहपुरा से मदन सिंह परस्ते, डिंडोरी से सितार मरकाम, भोपाल दक्षिण पश्चिम से मनीष पांडेय, महू से बैद्यनाथ मिश्रा और बड़ामलहरा से दिनेश यादव को टिकट दिया है।

जिनका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। ये मुद्दे हैं-महिला आरक्षण, जातिगत गणना। अभी हाल ही में मप्र का दौरा कर चुके राहुल गांधी महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण और जातिगत गणना हो हवा दे गए हैं। ऐसे में यह बात तो तय है कि मप्र विधानसभा चुनाव के मैदान में मुद्दों से राजनीतिक माहौल गरमाएगा।

दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इन विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण, जातिगत सर्वे सहित कई मुद्दे उठाए गए हैं। विधानसभा चुनावों में जिसका मुद्दा असर दिखाएगा, लोकसभा चुनाव में उसका प्रभाव रहेगा। मप्र में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो प्रादेशिक स्तर के हैं। हर मंच पर इन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है। जनता का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित करने का प्रयास राजनीतिक दल कर रहे हैं। इनमें, ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाड़ली बहना नारी सम्मान और सनातन शामिल हैं। आम चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा ओपिनियन पोल माना जाता है। 2018 में भाजपा को इन चुनावों में बुरी तरह हार मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने पूरी तरह स्वीप कर लिया था। जानकारों का मानना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा और इन चुनावों का परिणाम आम चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर लेती है, तो इसे आम चुनाव से पहले देश का मूड माना जा सकेगा।

कई मुद्दे होंगे प्रभावी

इस बार के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा और प्रमुख मुद्दा है। जहां कांग्रेस यह ऐलान कर चुकी है कि सरकार आने पर वो प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएगी।

वहीं भाजपा इसके जवाब में ओबीसी वर्ग से तीन मुख्यमंत्री दिए जाने, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने की बात को रखेगी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी लगातार अपने दौरों में ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल में भी ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न दिए जाने की बात पर कांग्रेस नेता भाजपा को घेर रहे हैं। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत बताई जाती है। ये विधानसभा ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरे देश में जातिगत सर्वे की मांग ने जोर पकड़ी है। मप्र में कांग्रेस जातिगत गणना का वादा कर चुकी है। भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाकर लोगों के बीच में है। चुनाव के नतीजे जातिगत सर्वे पर जनमत संग्रह माने जाएंगे। कांग्रेस मौजूदा भाजपा शासन में कथित भ्रष्टाचार को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। विपक्षी दल ने दावा किया है कि जब भाजपा सत्ता में थी तो कर्नाटक में 40 फीसदी कमीशन की सरकार थी, लेकिन मप्र में 50 फीसदी कमीशन की सरकार है। कांग्रेस ने भाजपा शासन के 18 साल के दौरान 250 से ज्यादा बड़े घोटाले भी गिनाए हैं। वित्तीय घोटालों की सूची में व्यापमं भर्ती और प्रवेश घोटाला सबसे ऊपर है। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक-दूसरे के कार्यकाल के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। जहां कांग्रेस भाजपा सरकार में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ सरकार में हुए भ्रष्टाचार की बात कर रही है। कांग्रेस 50 परसेंट कमीशन का आरोप सरकार पर लगा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर पोस्टरों के माध्यम से भ्रष्टाचार गिनाए जा रहे हैं।

जनता बेहाल...माननीय होते जा रहे मालामाल

प्रदेश हो या फिर देश, देखा यह जा रहा है कि जहां एक तरफ जनता की आर्थिक स्थिति खराब है, वहीं माननीय दिन पर दिन मालामाल होते जा रहे हैं। मप्र के मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव के नामांकन के साथ अपनी आय का ब्यौरा दिया है। इसके मुताबिक बीते पांच साल में मंत्रियों की इनकम 600 प्रतिशत तक बढ़ी है। जबकि आम आदमी की आमदनी में महज 52 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भाजपा की ओर से 32 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। पिछले पांच साल में इन मंत्रियों की संपत्ति में औसतन पौने पांच करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कुछ मंत्रियों की संपत्ति तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा बढ़ी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 84 करोड़ की हो गई है। वहीं, राजपरिवार से जुड़े बदनावर के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पास सबसे ज्यादा सोना-चांदी है। बमोरी प्रत्याशी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और उनकी पत्नी के नाम पर चार लाइसेंसी शस्त्र हैं। इस दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की संपत्ति कम हुई है। यहां यह भी बता दें कि पांच साल पहले 2018-19 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय औसतन 92 हजार रुपए थी। यह अब बढ़कर 1.40 लाख रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के पास 2.25 लाख रुपए नकद हैं। ये पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में तीन गुना ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने खुद की सुरक्षा के लिए रिवाल्वर भी ले रखी है। पांच साल में साधना सिंह ने 4 तोला सोना खरीदा है। मुख्यमंत्री शिवराज का बैंक बैलेंस 20 लाख से बढ़कर 96 लाख और साधना सिंह का 11 लाख से बढ़कर 71 लाख रुपए पहुंच गया है। शिवराज की कुल संपत्ति 3.21 करोड़ और साधना सिंह की 5.41 करोड़ रुपए है। पांच साल पहले इस दंपती पर 1.10 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो घटकर 68.72 लाख ही रह गया है। राजपरिवार से आने वाले बदनावर प्रत्याशी एवं मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और उनकी पत्नी के पास 3.50 किलो सोना और 70 किलो चांदी के जेवर-बर्तन हैं। चांदी के बर्तन ही 20 किलो वजन के हैं। वे चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं। 5 साल पहले दत्तीगांव दंपती के पास 7 किलो सोना था, जो अब आधा रह गया है। सुरखी से प्रत्याशी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास भी 20 किलो चांदी के जेवर और बर्तन हैं। इसमें 10 किलो के चांदी के बर्तन हैं। सोना 460 ग्राम ही है। अनूपपुर से प्रत्याशी बिसाहूलाल और उनके परिवार के पास एक किलो से अधिक सोना व 15 किलो चांदी के जेवर हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल के पास 1 किलो 165 ग्राम सोना तो 10 किलो चांदी के जेवर हैं। बृजेंद्र सिंह यादव के पास 300 ग्राम सोना तो 5 किलो चांदी के जेवर हैं।

ये आमने-सामने

विधानसभा क्षेत्र	कांग्रेस	भाजपा
श्योपुर	बाबू जंडेल	दुर्गालाल विजय
विजयपुर	रामनिवास रावत	बाबूलाल मेवरा
सबलगढ़	बैजनाथ कुशवाह	सरला रावत
जौरा	पंकज उपाध्याय	सूबेदार सिंह रजौधा
सुमावली	अजब सिंह कुशवाहा	अदल सिंह कंसाना
मुरैना	दिनेश गुर्जर	रघुराज कंसाना
दिमनी	रवींद्र सिंह तोमर	नरेंद्र सिंह तोमर
अंबाह	देवेंद्र सखवार	कमलेश जाटव
अटेर	हेमंत कटारे	डॉ अरविंद सिंह भदौरिया
भिंड	राकेश चतुर्वेदी	नरेंद्र सिंह कुशवाह
लहार	डॉ. गोविंद सिंह	डॉ. अंबरीश शर्मा
मेहगांव	राहुल भदौरिया	राकेश शुक्ला
गोहद	केशव देसाई	लालसिंह आर्य
ग्वालियर ग्रा.	साहब सिंह गुर्जर	भारत सिंह कुशवाह
ग्वालियर	सुनील शर्मा	प्रद्युम्न सिंह तोमर
ग्वालियर पू.	सतीश सिकरवार	माया सिंह
ग्वालियर द.	प्रवीण पाठक	नारायण सिंह कुशवाह
भितरवार	लखन सिंह यादव	मोहन सिंह राठौर
डबरा	सुरेश राजे	इमरती देवी
सेवढ़ा	घनश्याम सिंह	प्रदीप अग्रवाल
भांडेर	फूलसिंह बरैया	घनश्याम पिरोनिया
दतिया	राजेन्द्र भारती	नरोत्तम मिश्रा
करेरा	प्रागीलाल जाटव	रमेश खटीक
पोहरी	कैलाश कुशवाह	सुरेश धाकड़
शिवपुरी	केपी सिंह	देवेंद्र कुमार जैन
पिछोर	अरविंद सिंह लोधी	प्रीतम लोधी
कोलारस	बैजनाथ यादव	महेंद्र यादव
बमोरी	ऋषि अग्रवाल	महेंद्र सिंह सिसोदिया
गुना	पंकज कनेरिया	पन्नालाल शाक्य
चाचौड़ा	लक्ष्मण सिंह	प्रियंका मीणा
राघौगढ़	जयवर्धन सिंह	हीरेंद्र सिंह बंटी बना
अशोकनगर	हरिबाबू राय	जजपाल सिंह
चंदेरी	गोपाल सिंह चौहान	जगन्नाथ सिंह रघुवंशी
मुंगावली	राव यादवेंद्र यादव	बृजेंद्र सिंह यादव
बीना	निर्मला सप्रे	महेश राय
खुरई	रक्षा राजपूत	भूपेंद्र सिंह
सुरखी	नीरज शर्मा	गोविंद सिंह राजपूत
देवरी	हर्ष यादव	बृजबिहारी पटेरिया
रहली	इंजी. ज्योति पटेल	गोपाल भार्गव
नरयावली	सुरेन्द्र चौधरी	प्रदीप लारिया
सागर	निधि जैन	शैलेंद्र जैन
बण्डा	तंवर सिंह लोधी	वीरेंद्र सिंह लोधी
टीकमगढ़	यादवेंद्र सिंह	राकेश गिरि
जतारा	किरण अहिरवार	हरिशंकर खटीक
पृथ्वीपुर	नितेंद्र सिंह राठौर	डॉ. शिशुपाल यादव
निवाड़ी	अमित राय	अनिल जैन
खरगापुर	चंदा सिंह गौर	राहुल सिंह लोधी
महाराजपुर	नीरज दीक्षित	कामाख्या प्रसाद सिंह
चंदला	हरप्रसाद अनुरागी	दिलीप अहिरवार
राजनगर	विक्रम सिंह	अरविंद पटेरिया
छतरपुर	आलोक चतुर्वेदी	ललिता यादव
बीजावर	चरण सिंह यादव	राजेश शुक्ला
मलहरा	साध्वी राम सिया भारती	प्रद्युमन सिंह लोधी
पथरिया	राव ब्रजेंद्र सिंह	लखन पटेल
दमोह	अजय टंडन	जयंत मलैया
जबेरा	प्रताप सिंह लोधी	धर्मेंद्र सिंह लोधी
हटा	प्रदीप खटीक	उमा खटीक
पवई	मुकेश नायक	प्रहलाद लोधी

विधानसभा क्षेत्र	कांग्रेस	भाजपा
गुन्नौर	जीवन लाल सिद्धार्थ	राजेश वर्मा
पन्ना	भरत मिलन पांडेय	बृजेंद्र प्रताप सिंह
चित्रकूट	नीलांशु चतुर्वेदी	सुरेंद्र सिंह गहरवार
रायगांव	कल्पना वर्मा	प्रतिमा बागरी
सतना	सिद्धार्थ कुशवाह	गणेश सिंह
नागोद	डॉ. रश्मि सिंह पटेल	नागेंद्र सिंह
मैहर	धर्मेश घई	श्रीकांत चतुर्वेदी
अमरपाटन	राजेंद्र कुमार सिंह	रामखेलावन पटेल
रामपुर बघेलान	रामशंकर प्यासी	विक्रम सिंह
सिरमौर	रामगरीब कोल	दिव्यराज सिंह
सेमरिया	अभय मिश्रा	केपी त्रिपाठी
त्योंथर	रमाशंकर सिंह पटेल	सिद्धार्थ तिवारी
मऊगंज	सुखेंद्र सिंह बन्ना	प्रदीप पटेल
देवतालाब	पद्मेश गौतम	गिरीश गौतम
मनगवां	बबीता साकेत	नरेंद्र प्रजापति
रीवा	राजेंद्र शर्मा	राजेंद्र शुक्ला
गुढ़	कपिध्वज सिंह	नागेंद्र सिंह
चुरहट	अजय सिंह राहुल	शरदेन्दु तिवारी
सीधी	ज्ञान सिंह	रीति पाठक
सिंहावल	कमलेश्वर पटेल	विश्वामित्र पाठक
चितरंगी	माणिक सिंह	श्रीमती राधा सिंह
सिंगरौली	रेणु शाह	रामनिवास शाह
देवसर	बासमणि प्रसाद वर्मा	राजेंद्र मेश्राम
धौहनी	श्रीमती कमलेश सिंह	कुंवर सिंह टेकाम
ब्योहारी	रामलखन सिंह	शरद जुगलाल कोल
जयसिंहनगर	नरेंद्र मरावी	मनीषा सिंह
जैतपुर	उमा धुर्वे	जयसिंह मरावी
कोतमा	सुनील सराफ	दिलीप जायसवाल
अनूपपुर	रमेश सिंह	बिसाहूलाल सिंह
पुष्पराजगढ़	फुंदेलाल मार्को	हीरासिंह श्याम
बांधवगढ़	सुश्री सावित्री सिंह	शिवनारायण सिंह
मानपुर	तिलकराज सिंह	मीना सिंह
बड़वारा	विजय राघवेंद्र सिंह	धीरेंद्र बहादुर सिंह
विजयराघवगढ़	नीरज बघेल	संजय पाठक
मुड़वारा	मिथलेश जैन	संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
बहोरीबंद	सौरभ सिंह	प्रणय प्रभात पांडे
पाटन	नीलेश अवस्थी	अजय विश्नोई
बरगी	संजय यादव	नीरज सिंह ठाकुर
जबलपुर पूर्व	लखन घनघोरिया	अंचल सोनकर
जबलपुर उत्तर	विनय सक्सेना	अभिलाष पांडे
जबलपुर कैंट	अभिषेक चौकसे चिंटू	अशोक रोहाणी
जबलपुर पश्चिम	तरुण भनोत	राकेश सिंह
पनागर	राजेश पटेल	सुशील कुमार तिवारी
सिहोरा	एकता ठाकुर	संतोष बरकड़े
शाहपुरा	भूपेंद्र मरावी	ओमप्रकाश धुर्वे
डिंडोरी	ओंकार सिंह मरकाम	पंकज टेकाम
बिछिया	नारायण सिंह पट्टा	डॉ. विजय आनंद मरावी
निवास	चैनसिंह वरकड़े	फग्गनसिंह कुलस्ते
मंडला	डॉ.अशोक मर्सकोले	श्रीमती संपतिया उइके
बैहर	संजय उइके	भगत सिंह नेताम
लांजी	हीना कांवरे	राजकुमार करहि
परसवाड़ा	मधु भगत	रामकिशोर कावरे (नानो)
बालाघाट	अनुभा मुंजारे	मौसम बिसेन
वारासिवनी	विकी पटेल	प्रदीप जायसवाल
कटंगी	बोध सिंह भगत	गौरव पंधी
बरघाट	अर्जुन सिंह काकोडिया	कमल मर्सकोले
सिवनी	आनंद पंजवानी	दिनेश राय मुनमुन

विधानसभा क्षेत्र	कांग्रेस	भाजपा
केवलारी	रजनीश सिंह	राकेश पाल सिंह
लखनादौन	योगेंद्र सिंह बाबा	विजय उईके
गोटेगांव	एनपी प्रजापति	महेंद्र नागेश
नरसिंहपुर	लखन सिंह पटेल	प्रहलाद सिंह पटेल
तेंदुखेड़ा	संजय शर्मा	विश्वनाथ सिंह
गाडरवारा	श्रीमती सुनीता पटेल	उदय प्रताप सिंह
जुन्नारदेव	सुनील उइके	नाथन शाह
अमरवाड़ा	कमलेश शाह	मोनिका बट्टी
चौरई	सुजीत मेर सिंह	लखन वर्मा
सौंसर	विजय चौरे	नानाभाऊ मोहोड़
छिंदवाड़ा	कमलनाथ	विवेक बंटी साहू
परासिया	सोहन वाल्मीकि	ज्योति डेहरिया
पांढुर्णा	नीलेश उइके	प्रकाश सिंह उइके (जज)
मुलताई	सुखदेव पांसे	चंद्रशेखर देशमुख
आमला	मनोज मालवे	योगेश पंडाग्रे
बैतूल	निलय डागा	हेमंत विजय खंडेलवाल
घोड़ाडोंगरी	राहुल उइके	गंगा बाई उइके
भैंसदेही	धर्मू सिंह	महेंद्र सिंह चौहान
टिमरनी	अभिजीत शाह	संजय शाह
हरदा	रामकिशोर डोगने	कमल पटेल
सिवनी मालवा	अजय बलराम पटेल	प्रेमशंकर वर्मा
होशंगाबाद	गिरिजा शंकर शर्मा	सीतासरन शर्मा
सोहागपुर	पुष्पराज सिंह	विजय पाल सिंह
पिपरिया	वीरेंद्र बेलवंशी	ठाकुर दास नागवंशी
उदयपुरा	देवेंद्र पटेल घाडरवास	नरेंद्र शिवाजी पटेल
भोजपुर	राजकुमार पटेल	सुरेंद्र पटवा
सांची	डॉ. जीसी गौतम	प्रभुराम चौधरी
सिलवानी	देवेंद्र पटेल	रामपाल सिंह
विदिशा	शशांक भार्गव	मुकेश टंडन
बासौदा	निशंक जैन	हरीसिंह रघुवंशी
कुरवाई	श्रीमती रानी अहिरवार	हरीसिंह सप्रे
सिरोंज	गजेंद्र रघुवंशी	उमाकांत शर्मा
शमशाबाद	सिंधू विक्रम सिंह	सूर्यप्रकाश मीणा
बैरसिया	सुश्री जयश्री हरिकिरण	विष्णु खत्री
भोपाल उत्तर	आतिफ अकील	आलोक शर्मा
नरेला	मनोज शुक्ला	विश्वास सारंग
भोपाल द.प.	पीसी शर्मा	भगवानदास सबनानी
भोपाल मध्य	आरिफ मसूद	ध्रुवनारायण सिंह
गोविंदपुरा	रवीन्द्र साहू	कृष्णा गौर
हुजूर	नरेश ज्ञानचंदानी	रामेश्वर शर्मा
बुधनी	विक्रम मस्ताल	शिवराज सिंह चौहान
आष्टा	कमल चौहान	गोपाल सिंह
इछावर	शैलेंद्र पटेल	करण सिंह वर्मा
सीहोर	शशांक सक्सेना	सुदेश राय
नरसिंहगढ़	गिरीश भंडारी	मोहन शर्मा
ब्यावरा	पुरुषोत्तम डांगी	नारायण सिंह पवार
राजगढ़	बापू सिंह तंवर	अमर सिंह यादव
खिलचीपुर	प्रियव्रत सिंह	हजारीलाल डांगी
सारंगपुर	कला मालवीय	गोतम टेटवाल
सुसनेर	भेरू सिंह बापू	विक्रम सिंह राणा
आगर	विपिन वानखेड़े	माधव सिंह गहलोत
शाजापुर	हुकुम सिंह कराड़ा	अरुण भीमावद
शुजालपुर	रामवीर सिंह सिकरवार	इंदरसिंह परमार
कालापीपल	कुणाल चौधरी	घनश्याम चंद्रवंशी
सोनकच्छ	सज्जन सिंह वर्मा	राजेश सोनकर
देवास	प्रदीप चौधरी	गायत्री राजे पवार
हाटपिपल्या	राजवीर सिंह बघेल	मनोज नारायणसिंह चौधरी
खातेगांव	दीपक जोशी	आशीष गोविंद शर्मा

विधानसभा क्षेत्र	कांग्रेस	भाजपा
बागली	गोपाल भोंसले	मुरली भंवरा
मांधाता	उत्तम पाल सिंह	नारायण पटेल
हरसूद	सुखराम साल्वे	विजय शाह
खंडवा	कुंदन मालवीय	कंचन मुकेश तन्वे
पंधाना	रुपाली बारे	छाया मोरे
नेपानगर	श्रीमती गेंदू बाई चौहान	मंजू राजेंद्र दादू
बुरहानपुर	सुरेंद्र सिंह शेरा	अर्चना चिटनिस
भीकनगांव	झूमा सोलंकी	नंदा ब्राह्मणे
बड़वाह	नरेंद्र पटेल	सचिन बिड़ला
महेश्वर	विजय लक्ष्मी साधौ	राजकुमार मेव
कसरावद	सचिन यादव	आत्माराम पटेल
खरगोन	रवि जोशी	बालकृष्ण पाटीदार
भगवानपुरा	केदार डावर	चंद्रसिंह वास्कले
सेंधवा	मोंटू सोलंकी	अंतर सिंह आर्य
राजपुर	बाला बच्चन	अंतर सिंह पटेल
पानसेमल	चंद्रभागा किराड़े	श्याम बर्डे
बड़वानी	राजन मंडलोई	प्रेमसिंह पटेल
अलीराजपुर	मुकेश पटेल	नागरसिंह चौहान
जोबट	सेना पटेल	विशाल रावत
झाबुआ	डॉ. विक्रांत भूरिया	भानू भूरिया
थांदला	वीर सिंह भूरिया	कलसिंह भाबर
पेटलावद	वालसिंह मेडा	निर्मला भूरिया
सरदारपुर	प्रताप ग्रेवाल	वेलसिंह भूरिया
गंधवानी	उमंग सिंगार	सरदार सिंह मेडा
कुक्षी	सुरेंद्र सिंह बघेल हनी	जयदीप पटेल
मनावर	डॉ. हीरालाल अलावा	शिवराम कन्नोज
धरमपुरी	पांचीलाल मेडा	कालूसिंह ठाकुर
धार	श्रीमती प्रभा गौतम	नीना विक्रम वर्मा
बदनावर	भंवरसिंह शेखावत	राजवर्धनसिंह दत्तीगांव
देपालपुर	विशाल पटेल	मनोज पटेल
इंदौर-1	संजय शुक्ला	कैलाश विजयवर्गीय
इंदौर-2	चिंतामणि चिंटू चौकसे	रमेश मेंदोला
इंदौर-3	दीपक पिंटू जोशी	राकेश गोलू शुक्ला
इंदौर-4	राजा मंधवानी	मालिनी गौड़
इंदौर-5	सत्यनारायण पटेल	महेंद्र हार्डिया
महू	रामकिशोर शुक्ला	उषा ठाकुर
राउ	जीतू पटवारी	मधु वर्मा
सांवेर	रीना बौरासी सेतिया	तुलसीराम सिलावट
नागदा-खाचरोद	दिलीप सिंह गुर्जर	डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान
महिदपुर	दिनेश जैन बॉस	बहादुर सिंह चौहान
तराना	महेश परमार	ताराचंद गोयल
घट्टिया	रामलाल मालवीय	सतीश मालवीय
उज्जैन उत्तर	माया राजेश त्रिवेदी	अनिल कालूहेड़ा
उज्जैन दक्षिण	चेतन प्रेमनारायण यादव	डॉ. मोहन यादव
बडनगर	मुरली मोरवाल	जितेंद्र पंड्या
रतलाम ग्रामीण	लक्ष्मण डिंडोरे	मथुरालाल डावर
रतलाम शहर	पारस सकलेचा	चैतन्य कश्यप
सैलाना	हर्ष विजय गहलोत	संगीता विजय चारेल
जावरा	वीरेंद्र सोलंकी	डॉ. राजेंद्र पांडेय
आलोट	मनोज चावला	चिंतामणि मालवीय
मंदसौर	विपिन जैन	यशपाल सिंह सिसोदिया
मल्हारगढ़	परशुराम सिसोदिया	जगदीश देवड़ा
सुवासरा	राकेश पाटीदार	हरदीप सिंह डंग
गरोठ	सुभाष सोजतिया	चंदरसिंह सिसोदिया
मनासा	नरेंद्र नाहटा	अनिरुद्ध मारू
नीमच	उमराव सिंह गुर्जर	दिलीप सिंह परिहार
जावद	समंदर पटेल	ओमप्रकाश सखलेचा

एक दौर में तमाम महापुरुष और नेता जाति उन्मूलन की बात करते थे, आज देश की समूची राजनीति ही जातियों को गिनने की धुरी पर आकर टिक गई है। बिहार की जातिवार गणना के आंकड़े सामने आने के बाद जो हलचल मची है वह देश के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। खासकर पांच राज्यों के चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव में इसके अक्स दिखने की संभावना है।

ब्रांड मोदी को रोकने का जतन

ओबीसी जातियों के कितने प्रतिशत वोट किसको मिले

आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर के बाद तक कांग्रेस पिछड़ी जातियों की गिनती और मोटे तौर पर उनके आरक्षण के मामले में उदासीन बनी रही थी। इंदिरा गांधी के दौर तक कांग्रेस के वोट बैंक ब्राह्मण, हरिजन और मुसलमान माने जाते थे लेकिन नब्बे के दशक में स्थितियां बदलने लगीं। इस तरह कांग्रेस को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के दौरान ही ओबीसी संभावनाओं का एहसास होने लगा। मनमोहन सिंह सरकार में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने 2006 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया। फिर 2010 में पिछड़े वर्ग के नेताओं लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव के प्रभाव में संसद में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका भाजपा ने समर्थन किया था। 2011 में सरकार ने देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) कराई और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान की, हालांकि 2013 में उसके नतीजे जाहिर नहीं किए गए।

बिहार के व्यापक जाति सर्वेक्षण के प्रारंभिक आंकड़ों के जारी होने के साथ इंडिया गठबंधन के तहत लामबंद पार्टियां देशव्यापी जाति जनगणना की मांग जोरशोर से उठा रही हैं। उन्हें शायद उम्मीद है कि करीब 9 साल से केंद्र में सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अगले साल के लोकसभा चुनावों में चुनौती दी जा सकेगी। बिहार जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य बन गया है। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग की आबादी 63 फीसदी है जिसमें 27.12 फीसदी पिछड़ा वर्ग और 36.01 फीसदी अतिपिछड़ा वर्ग है। दलितों की संख्या 19.65 फीसदी, सामान्य वर्ग 15.52 फीसदी और आदिवासी 1.68 फीसदी हैं। इन आंकड़ों में खासकर पिछड़े वर्ग की आबादी मोटे तौर पर वही है, जो विभिन्न चुनाव सर्वेक्षणों में परिलक्षित होती रही है। बेशक, इसके राजनीतिक असर दिख सकते हैं, खासकर बिहार के मामले में यह बात सही हो सकती है। शायद इसीलिए बिहार के भाजपा नेता भी इसका हल्का-फुल्का विरोध करते हुए कहते हैं कि यह फैसला उनकी गठबंधन सरकार के दौरान ही किया गया था।

क्या इसका असर समूचे देश के स्तर पर देखा जा सकता है? विपक्ष और खासकर कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। वह 2011 में यूपीए सरकार के दौरान सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के नतीजे जाहिर करने की मांग कर रही है जिसे तकनीकी कारण बताकर अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जाहिर मकसद है कि अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मुहैया कराया जाए। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान ओबीसी की भागीदारी वाले मुद्दे को रेखांकित करते हुए बताया था कि केंद्र सरकार के कुल 90 सचिवों में सिर्फ तीन ही ओबीसी हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, देश को सचिव नहीं, सरकार चलाती है और उसके बाद गिनवाया था कि भाजपा के 88 सांसद ओबीसी हैं और उनकी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा के 1358 विधायक में 365 यानी 27 फीसदी ओबीसी के हैं। इन तमाम दलीलों के बावजूद जाति जनगणना पर भाजपा की दुविधा स्पष्ट झलकती है। 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के नतीजे अव्यावहारिक बताकर सार्वजनिक नहीं किए गए और 2021 में तय जनगणना भी कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाई। महामारी खत्म होने के दो साल बाद भी यह प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। दरअसल, जातिवार जनगणना की वजह से भाजपा को सवर्ण वोटरों के छिटकने का खतरा नजर आता है। यह बात अलग है कि 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनावों में उसे ओबीसी का अच्छा-खासा वोट मिला था। कई चुनाव बाद जनमत सर्वेक्षणों में यह जाहिर हुआ है। कुछ सर्वेक्षण 2019 में 44 फीसदी तो कुछ 58 फीसदी तक भाजपा को ओबीसी वोट मिलने का अनुमान लगाते हैं। कुछेक सर्वेक्षणों में भाजपा को करीब 10 फीसदी मुसलमान वोट मिलने का

भी अनुमान है। यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने बड़े पैमाने पर छोटी ओबीसी जातियों और दलित जातियों को अपने साथ जोड़ा है। यह इससे भी समझ में आता है कि 2019 में भाजपा को 37.75 फीसदी जो वोट मिले, उसके सवर्ण जातियों के मूल आधार के अलावा सभी समुदायों का वोट मिला हुआ है।

लेकिन इसके बावजूद भाजपा को जाति जनगणना पर सवर्ण वोटरों की नाराजगी का अंदेशा है। भाजपा शायद यह गणित भी लगा रही है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बाद वीपी सिंह सत्ता में नहीं लौटे थे और 1991 के चुनाव में भाजपा को बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी जबकि उप्र में 46 सीटें मिल गई थीं। यही नहीं, 1991 में मंडल की राजनीति से तेजी से उभरे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टियां एक जाति विशेष और एक परिवार की बनकर रह गई हैं। सवाल है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी फिर से समूची पिछड़ा और अतिपिछड़ा बिरादरी को अपने झंडे तले ला पाएंगी? फिर, नीतीश कुमार ने जिस अतिपिछड़ा और महादलित जातियों की राजनीति को परवान चढ़ाया, उसमें भी भाजपा सेंध लगा चुकी है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि जाति जनगणना देश के स्तर पर कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगी या लोकसभा चुनाव में किसे इसका फायदा होगा। विपक्ष इस रणनीति को और धार दे पाएगा या भाजपा सोशल इंजीनियरिंग से उसकी काट ढूंढ लेगी?

कई बार मुद्दे हैरान करते हैं, जरूरी नहीं कि वे नए हों, लेकिन वे ऐसे छा जाते हैं कि अपने में सबको समाहित कर लेते हैं। बिहार के व्यापक जातिवार सर्वेक्षण ने लगता है ऐसी ही फिजा तैयार कर दी है, जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं ही नहीं, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी विचारों के केंद्र में आ गई हैं। बेशक, यह मुद्दा इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस समेत ज्यादातर केंद्रीय सत्ता की विपक्षी पार्टियों को उत्साहित कर रहा है जबकि सत्तासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियां कुछ हद तक दुविधा में दिख रही हैं। प्रधानमंत्री तो लगातार जनसभाओं में इस मुद्दे को समाज में बंटवारा पैदा करने वाला तक बता रहे हैं, लेकिन बिहार भाजपा के सुशील कुमार मोदी जैसे नेता कहते हैं, इसका फैसला तो हमारी गठबंधन सरकार के दौरान ही हुआ था और हमारी पार्टी के वित्तमंत्री ने इसके लिए धन मुहैया कराया था। इसी मामले में बिहार के मुख्यमंत्री तथा जदयू के नेता नीतीश कुमार विपक्ष के नए सूत्रधार की तरह उभरे हैं जिन्होंने पहली बार किसी मुद्दे से सत्तासीन गठजोड़ को बचाव की मुद्रा अपनाने पर मजबूर कर दिया है। वरना 2014 के बाद कम से कम दो लोकसभा चुनावों में यही दिखता रहा है कि भाजपा या नरेंद्र मोदी मुद्दे तय करते थे और विपक्ष प्रतिक्रिया देता रह जाता था। दरअसल, विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ ओबीसी जातियों के आरक्षण तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि इसका विस्तार आर्थिक नीतियों को घेरने में भी कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 9 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जाति जनगणना तो एक्सरे है। इसकी एमआरआई तो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो बताएगा कि किसके पास कितना धन, देश की संपत्ति का कितना हिस्सा है और अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ में कितना है। उसका बंटवारा करना होगा। यानी विपक्ष इसमें मौजूदा सत्ता के खिलाफ सारे मुद्दे समेटने की संभावना देख रहा है।

संभव है, भाजपा की दुविधा यही है। अगर महंगाई, बेरोजगारी, छोटे उद्योग-धंधों की बर्बादी जैसे मुद्दे इसमें समाहित हो जाते हैं, तो विपक्ष को शायद उम्मीद है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे भी गौण हो सकते हैं। शायद इसी वजह से भोपाल की एक सभा में प्रधानमंत्री ने दलील दी, अगर जितनी आबादी उतना हक की बात हो, तो अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के हिस्से क्या बचेगा, जिनका हक मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर पहला कह चुके हैं। (हालांकि कांग्रेस ने वीडियो जारी किया, जिसमें मनमोहन सिंह यह कहते दिखते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का है)। यहां इसका जिक्र भी मौजू है कि जब जी20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में अपनी सफलता और संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण जैसे कानून पारित करवाकर भाजपा और नरेंद्र मोदी अपनी भारी लोकप्रियता का दावा कर रहे थे, तभी जाति का यह मुद्दा उछल गया। नीतीश कुमार और उनके उप-मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जाति सर्वेक्षण के प्रारंभिक आंकड़े जारी कर फिजा में नए तेवर घोल दिए। इस सर्वेक्षण के सामाजिक-आर्थिक आंकड़े अक्टूबर के आखिर या नवंबर में विधानसभा सत्र में जारी किए जाएंगे। असल में बिहार के जाति सर्वेक्षण से वह जाहिर हुआ, जिसकी चर्चा कुछ समय से कयास की तरह जारी थी। अभी तक 1931 की जनगणना के अनुमान के मुताबिक ओबीसी या अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या 52 फीसदी मानी जाती रही है।

● **विपिन कंधारी**

भारत में जातिवार जनगणना के अहम पड़ाव

कांग्रेस की नीतियों में पहली दफा यह परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन बिहार के जाति सर्वेक्षण करने के ऐलान के साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी और इसके आंकड़े कभी भी जारी हो सकते हैं। इसी तरह कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार 2015 में कराए सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण के नतीजे जारी करने का संकल्प दोहरा चुकी हैं। इंडिया ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस और एकाध दूसरी पार्टियों को छोड़कर सभी जाति जनगणना के पक्ष में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह सभी इसके पक्ष में राय जाहिर कर चुकी हैं। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल में यह प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना सरकारों ने भी ऐसी सहमति जताई है। उप्र में समाजवादी पार्टी ने तो 2022 के विधानसभा चुनावों में ही अपने घोषणा-पत्र में जाति जनगणना का वादा किया था। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती इसके बदस्तूर पक्ष में हैं। बसपा नेता कांशीराम ने ही नारा दिया था, 'जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी।' अब कांग्रेस के राहुल गांधी इसे यूं कहते हैं, जितनी आबादी, उतना हक। आम आदमी पार्टी और अकाली दल की भी इस पर सहमति है। भाजपा में भी कई पिछड़े नेता जाति जनगणना के पक्ष में बोल चुके हैं।

बिना सबूत जेल में नेता

देश में तेजी से बढ़ रही आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में इस कदर फंस गई है कि एक-एक करके उसके कई नेता जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जांच के नाम पर जांच एजेंसियों ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर रखा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार एजेंसियों को फटकार लगा चुका है कि वे जल्द से जल्द इस मामले में सबूत इकट्ठा करें, ताकि मामले का निपटारा हो सके। उधर, आप का कहना है कि राजनीति के दबाव में उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है।

अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई, कुछ नहीं हुआ। नए नियम बनाकर कई हवाई अड्डे सौंप दिए गए। दबाव बनाकर कई तरह के लाभकारी ठेके दिलवाए गए। सरकारी संस्थानों को घाटे में दिखाकर बेच दिया गया, कोई जांच नहीं हुई। लेकिन किसी दूसरी पार्टी की सरकार ने नई शराब नीति बनाकर चंद ठेके दे दिए, तो जांच और गिरफ्तारियां होने लगीं। एक बड़ी पार्टी के यहां किसी भी तरह से पैसा आए, तो वह ठीक है। लेकिन दूसरी किसी पार्टी को कोई चंदा मिले, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग है। मुकदमा सिर्फ लेने वाले पर नहीं, देने वाले पर भी बनेगा। गवाह भी आरोपी को ही बना लिया जाएगा। गवाह के एक बयान पर किसी को भी उठा लिया जाएगा। लेकिन वहीं केंद्र की सत्ता में मंत्रियों पर रेप और पॉक्सो जैसे मामलों में भी कुछ नहीं होगा। पीड़ित भले ही प्रतिष्ठित ही क्यों न हो, पुलिस केस दर्ज नहीं करती। यह कोई आरोप या पक्षपात नहीं, बल्कि आजकल जो चल रहा है, उसी की बात हो रही है। साफ है कि भारत सरकार किसी को भी नया नियम बनाकर लाभ पहुंचा सकती है। लेकिन अन्य कोई सरकार ऐसा करेगी, तो उसके मंत्रियों और उसकी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि अब सरकार की सोच है कि हम ईमानदार हैं और सब बेईमान हैं।

विपक्षी सरकारों की सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है और हम वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर आते ही सारे दाग धुल जाते हैं। क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, और सब देशद्रोही। शायद इसी को ही राजनीति कहते हैं। अगर हम गिर रहे हैं, तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। मौजूदा दौर की राजनीतिक उठापटक यही कहती है। जिस तरह से पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है और सत्ताधारी पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर खामोशी है, उससे सवाल उठने लाजमी हैं। सरकार यह नहीं चाहती कि कोई उसके खिलाफ बोले। क्योंकि वह जो कर रही है, बिलकुल सही कर रही है और देश को ऐसी ही सरकार की दरकार है। उद्योगपतियों का सारा चुनावी चंदा भी सिर्फ उसी को मिले और वह अपने धुआंधार प्रचार के जरिए सरकार बनाती रहे और सत्ता की मलाई सिर्फ मौजूदा ताकतवरों की थाली में ही रहे। देश की जनता को उन्हें ही वोट देने की मजबूरी बना दी जाए, ऐसी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों के जरिए क्या देश निरंकुश शासन की ओर नहीं बढ़ रहा है? जिसमें लोकतंत्र की जगह एक तंत्र हावी हो रहा है।

फरवरी, 2023 में जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तभी प्रधानमंत्री को विपक्ष के आठ बड़े दलों के 9 नेताओं ने पत्र लिखकर ईडी की कार्रवाई पर चिंता जताई थी। लेकिन इस तरह की कार्रवाई रुकने के बजाय और तेजी से आगे बढ़ रही है। परिणाम यह निकला कि न्यूज क्लिक के तफ्तर पर छापे के बाद 4 अक्टूबर को पत्रकारों के 18 संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि पत्रकार देश के कानून से ऊपर नहीं हैं। किसी मामले में उनके लिए भी वही कायदे-कानून लागू होते हैं, जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं। लेकिन हम पत्रकारों की अपील है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देकर अकारण प्रताड़ित करने

एक हजार जगहों पर छापे... एक पाई नहीं मिली

ईडी और सीबीआई ने कम से कम 1,000 जगहों पर छापेमारी की है; लेकिन कहीं से एक रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। इस मामले में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही बताया। बता दें कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब इसी 5 अक्टूबर को सिसोदिया के जमानत मामले की सुनवाई हुई, तो अदालत ने ईडी पर तल्ख टिप्पणी की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी पुख्ता सबूत रखे, नहीं तो यह केस दो मिनट भी नहीं टिकेगा। कोर्ट ने पूछा कि अगर इस मामले में रुपयों के लेन-देन में सिसोदिया की भूमिका नहीं है, तो धन-शोधन के मामले में उन्हें आरोपी क्यों बनाया? कोर्ट ने कहा कि एजेंसी सबूत दे कि पैसा आरोपियों तक कैसे पहुंचा? कोर्ट ने कहा कि आपका केस आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द-गिर्द घूमता है और सबूत के नाम पर कुछ है नहीं आपके पास। कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब नीति से अगर सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टी को फायदा हुआ, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया? ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने पहली बार इस तरह से ईडी को फटकार लगाई हो।

वाली कार्रवाई से पत्रकारों को बचाए, जिससे हम अपना काम बिना डर के ठीक से कर सकें। साथ ही यह भी लिखा कि आप जल्दी कदम उठाएं, नहीं तो देरी हो जाएगी और हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। देखा जाए, तो पिछले 9 वर्षों से बेधड़क उन पत्रकारों, नेताओं सहित उद्योगपतियों के पीछे जांच एजेंसियों को छोड़ा जा रहा है, जो सरकार के पक्ष में नहीं हैं। जैसे ही कोई नेता या उद्योगपति सरकार के खेमे में शामिल होता है, वह पाक-साफ हो जाता है। इस बात की प्रतिपुष्टि एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए भी हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले आठ साल में ईडी के छापों में 27 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी होना कोई बड़ी बात नहीं है; लेकिन जिस तरह से छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उससे ईडी और सरकार सवालों के घेरे में है। 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार में ईडी ने 112 जगह दबिश दी और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। वहीं भाजपा सरकार के 9 वर्षों में ईडी ने 3,010 जगहों पर छापेमारी की और कुल एक लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की। इनमें यहां ध्यान देने वाली बात है कि संपत्ति सिर्फ अटैच की गई है। कितनी जब्त की गई ? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। डेटा के मुताबिक, 9 वर्षों में ईडी सिर्फ 9 मामलों में ही आरोपियों को ही दोषी सिद्ध कर पाई है। ये 9 मामले काफी छोटे प्रोफाइल थे। इससे साफ है कि ईडी के छापे महज लोगों को डराने-धमकाने और परेशान करने के लिए किए गए।

रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पहले के मुकाबले चार गुना ज्यादा मामले राजनीतिक दलों के ऊपर बढ़े हैं। इन 9 वर्षों में बड़े नेताओं पर 221 मामले ईडी के पास हैं। इनमें 115 मामले विपक्षी दलों के ऊपर हैं। यानी 95 फीसदी मामले विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए देश को एक अच्छा संदेश देने के बजाय नेताओं, पत्रकारों सहित उद्योगपतियों को भी डराने का काम कर ही है। दिल्ली में नई शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी तीन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। देखा जाए, तो जबसे इंडिया गठबंधन हुआ है, तबसे ईडी और ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। ईडी की नजर अभी और कई बड़े नेताओं पर है। अब तक ईडी की जांच के दायरे में कई मुख्यमंत्री और नेता शामिल हैं। जबसे भाजपा सत्ता में आई है, तबसे एक भी ऐसा नेता नहीं है, जिसके खिलाफ जांच के बाद ईडी उस पर आरोप सिद्ध करने में कामयाब हो पाई हो। आरोप इतने सारे; लेकिन सबूत एक भी नहीं, जिससे सिद्ध हो सके कि आरोप सही हैं। ईडी का चाल-चरित्र नेतागिरी के मॉडल पर आधारित है। यह सरकार के इशारों पर आरोप पत्र तैयार करने वाली महज एक एजेंसी बनकर रह गई है, जिसमें ट्रेजेडी है। ड्रामा है; और इमोशन भी है। वह जिसको चाहे, फर्जी केस में पकड़ सकती है।

दिल्ली की नई शराब नीति में गिरफ्तारी की जो पटकथा लिखी गई है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक का नाम शामिल है। कल तक जिस मामले में संजय सिंह का नाम तक नहीं था, आरोपी संजय अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाकर संजय सिंह का नाम उगलवाकर उनके घर पहुंचकर घंटों तलाशी और पूछताछ के बाद नाटकीय ढंग से ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अभी तक कथित नई शराब नीति घोटाले में ईडी 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित कुछ लोग जेल में हैं, बाकी सभी को जमानत मिल चुकी है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए इसे गैर-कानूनी बताया। संजय सिंह के आवास पर छापेमारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये छापे एक ऐसी पार्टी (भाजपा) की बदहवास कोशिश हैं, जो अगला चुनाव हारने जा रही है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि मुझे मरना मंजूर है; डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मुझे दी जाएं, मैं नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहूंगा। सिंह ने कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी को अडानी का नौकर बताया और कहा कि हम इनसे डरते नहीं हैं। ये जितना अत्याचार और जुर्म कर लें, हम सह लेंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बिना किसी सबूत और बिना किसी ठोस कारण के संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यह प्रधानमंत्री की निराशा, हार का डर और बौखलाहट है। यह एक ऐसा फर्जी शराब घोटाला है, जिसकी जांच पिछले 15 महीने से चल रही है।

● इन्द्र कुमार

मायापतियों पर ईडी-ग्रहण

मायानगरी मुंबई पर ईडी की पैनी नजर है। इसकी खास वजह मुंबई के कुछ व्यवसायियों और फिल्मी हस्तियों के पास अथाह पैसा है। तो क्या यह माना जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर लोगों को नोटिस भेजकर हरासमेंट के लिए बुलाने वाले ईडी को दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के बैंक एकाउंट फुल करने और मौका मिले, तो अपनी जेबें भी भरने की जुगत में लगा हुआ है? आरोप तो ऐसे ही लग रहे हैं आजकल ईडी अफसरों पर। कुछ समय पहले तानाजी मंडल नाम के ईडी के एक अधिकारी को महाराष्ट्र के भूषण पाटील और राजेश शेट्टी नाम के उसके दो सहयोगियों के साथ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कथित आरोप तो यहां तक है कि ईडी के अधिकारियों ने पैसे और नेमफेम वाले मुंबई के निवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है। कुछ समय से शिवसेना के संजय राउत के अलावा कुछ नामी-गिरामी व्यापारियों, नेताओं को इसी तरह ईडी डराती रही है। अब ईडी ने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोशन के लिए काम करने वाले करीब 34 फिल्मी और टीवी कलाकारों को भी रडार पर ले रखा है। ईडी ने मुंबई के कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर भी छापेमारी की है। ये प्रोडक्शन हाउस भी महादेव ऐप का प्रमोटर है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से हवाला की मोटी रकम मिली थी।

आदिवासी वोट करेंगे खेला

छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 34 परसेंट है। जाहिर है कि चुनाव में इतना बड़ा समूह सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में तो होगा ही। मगर, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, यहां की राजनीति भाजपा और कांग्रेस केंद्रित ही रही। आदिवासियों का वोट कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को जाता रहा है। आदिवासियों के नाम पर बनी कोई पार्टी मुख्य भूमिका में नहीं आ सकी। मगर, इस बार स्टेट में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। आदिवासियों की बनी एक पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा रखी है। चूंकि कांग्रेस पिछली बार आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में शत-प्रतिशत (2 सीट छोड़कर) सीट जीतने में सफल हुई थी, इसलिए ज्यादा चिंता कांग्रेस को ही है।

छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। इस हिसाब से सरकार बनाने के लिए 46 सीटें होनी चाहिए। कुल विधानसभा सीटों में 29 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। मतलब सीधा है कि आदिवासी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए। मगर, अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी समुदाय का मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अगर जीतती हैं, तो किसी आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना न के बराबर ही है। साल 2018 के चुनाव परिणाम की बात करें, तो कांग्रेस ने यहां 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। वहीं, 29 आदिवासी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं। बाद में उपचुनाव होने के चलते कांग्रेस ने एक और आदिवासी रिजर्व सीट जीत ली। सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस ने 30 सीटों पर 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर 2108 के आंकड़े सीधे-सीधे कांग्रेस के फेवर में दिख रहे हैं। इसलिए आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण किसी आदिवासी पार्टी के लिए होता है, तो सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है।

पिछले साल दिसंबर 2022 की ही बात है। प्रदेश के भानुप्रतापपुर में हुए उपचुनाव में मिले वोटों को अगर आधार मानें, तो कांग्रेस और भाजपा के लिए कई जगहों पर खतरा सर्व आदिवासी समाज की पार्टी हमर राज पार्टी से है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में ऐन मौके पर हमर राज पार्टी का कैंडिडेट ने पर्चा भरा और बिना किसी तैयारी के 23 हजार वोट पाने में सफल हुआ था। अब करीब 50 सीटों पर हमर राज पार्टी के प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने के लिए तैयार हैं। चूंकि कई सीट ऐसी हैं, जहां पर कांग्रेस के जीत का अंतर बहुत कम वोटों का रहा है, वहां तो पार्टी का नुकसान होना तय है। अगर 2018 विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों के वोटिंग ट्रेंड की तुलना करें, तो समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी से बहुत नुकसान हुआ था। 2018 विधानसभा चुनाव में बंपर वोटों से जीतने वाली कांग्रेस को ठीक अगले साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। भाजपा ने लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में 11 में से 8 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि राज्य में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। सबसे खास पहलू यह रहा कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित चार सीटों में से तीन पर भाजपा ने कब्जा जमाया लिया। कांग्रेस को केवल एक सीट पर संतोष करना पड़ा था।

साल 2018 के विधानसभा चुनावों में करीब 14 विधानसभा सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा। मतलब इन सीटों पर एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहे, जिन्हें भाजपा सरकार से नाराजगी थी। मगर, वे कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे। यही कारण है कि इन सीटों पर इस बार एकतरफा मुकाबला नहीं होगा। भाजपा से कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इन 14 विधानसभा सीटों पर नोटा को वोट देने वालों को अगर भाजपा मना लेती है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाजपा के लिए 2018 में आदिवासियों के लिए नाराजगी का सबसे बड़ा कारण रमन सिंह सरकार का सलवा जुडूम कार्यक्रम था। ऐसा कहा गया कि आदिवासियों के बीच इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी नाराजगी थी। हालांकि, बाद में कोर्ट ने भी इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। रमन सिंह के मुख्यमंत्री कैंडिडेट न होने के चलते यह संभव है कि सलवा जुडूम के नाम से नाराज आदिवासी वोटर फिर से भाजपा के पाले में आ जाएं। इस बीच केंद्र सरकार ने आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई काम किए हैं। भाजपा राज में देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी भारत को मिली हैं। हो सकता है कि भाजपा के लिए जो गुस्सा आदिवासियों में 2018 में था, वह कुछ कम हुआ होगा। कहने की जरूरत नहीं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो दल आदिवासियों को रिझाने में कामयाब रहेगा उसकी छत्तीसगढ़ में सरकार होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटरों के निर्णायक होने के पीछे कई तर्क हैं। पहला तर्क है कि इस बार एकतरफा मुकाबला नहीं होगा। भाजपा से कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिलेगी। दूसरा तर्क ये है कि बीते चुनाव में 14 विधानसभा सीटें ऐसी रही थीं जहां नोटा पर पड़े वोट तीसरे नंबर पर रहे थे। नोटा वोटों को एंटी इनकम्बेंसी के साथ-साथ विपक्ष से नाउम्मीदी वाला वोट भी माना जाता है। ये वोट अगर विपक्ष यानी भाजपा अपने साथ कर पाती है तो कांग्रेस को नाको चने चबाने पड़ेंगे। तीसरा तर्क लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर यह है कि भाजपा के वोटर छत्तीसगढ़ में उसके साथ बने हुए हैं। महज इस वजह से वे छिटक गए थे क्योंकि तत्कालीन रमन सिंह सरकार के प्रति उनकी गहरी नाराजगी थी।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

कांग्रेस-भाजपा में आदिवासियों के बीच तगड़ी टक्कर

कांग्रेस के लिए सुखद बात ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल आदिवासियों के बीच पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। शपथ लेने के बाद ही भूपेश बघेल ने आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन वापस कराने का फैसला लिया था। इस जमीन को प्रस्तावित स्टील परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था। धान के समर्थन में मूल्य में वृद्धि के फैसले से भी आदिवासी किसान खुश हैं। वनोपज के समर्थन में मूल्य में वृद्धि और उसकी खरीद की व्यवस्था किए जाने से भी आदिवासियों को राहत मिली है। इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। आदिवासियों के बीच लोकप्रिय नेताओं में भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव का नाम सबसे ऊपर आता है। इस परिवार की साख अब भी कायम है। मगर, बीते दिनों युद्धवीर सिंह जूदेव की असमय मृत्यु से भाजपा को गहरा धक्का लगा था। अब भी जूदेव परिवार की बदौलत भाजपा आदिवासियों के बीच सक्रिय है। भाजपा के लिए नंदकुमार साय भी महत्वपूर्ण नेता रहे थे जो भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं।

मराठा आरक्षण के पीछे की राजनीति

देश में आम चुनाव से पहले जातिगत जनगणना जितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भी उतना ही अहम है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आग सुलग गई है। 30 अक्टूबर को अचानक मराठा आंदोलन उग्र हो गया और राज्य में कई जगह मंत्रियों-विधायकों के घर पर हमला बोल दिया गया। वहीं आंदोलन के समर्थन में शिवसेना के दो सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा और 31 अक्टूबर को भी राज्य में जगह-जगह आगजनी की घटनाएं हुईं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि शिंदे सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेने से नहीं हिचक रही है। गत दिनों सबसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद मनोज जरांगे से फोन पर बातचीत की। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए और शिंदे कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इससे पहले सोलापुर में रेल रोको आंदोलन किया गया। हंगामे को देखते हुए ठाणे में मुख्यमंत्री शिंदे के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। आंदोलन को लेकर अभी तक 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली है।

गौरतलब है कि मनोज जरांगे के बयान के बाद 19 अक्टूबर को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता सुनील कावले का शव मुंबई के बांद्रा इलाके में एक फ्लाईओवर के किनारे लाइट के खंभे से लटका हुआ मिला। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग की गई थी। इन दोनों ही घटनाओं ने प्रदेश में मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने एक बयान में कहा, महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को कानून के दायरे में आरक्षण देने की पूरी कोशिश कर रही है। शिंदे ने मराठा समुदाय के युवाओं से आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाने का भी आग्रह किया है। शिंदे ने यहां भवानी चौक में नवरात्रि से संबंधित कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसे कदम उठाने से पहले अपने माता-पिता, परिवार, रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों के बारे में सोचें। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस आरक्षण की मांग की शुरुआत कब और कैसे हुई और ओबीसी नेता मराठा समुदाय के इस मांग का विरोध में क्यों कर रहे हैं?

सितंबर की शुरुआत में मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने समुदाय के लोगों को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र देकर ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग के साथ अनशन करना शुरू किया था। उनके इस अनशन ने एक महीने के भीतर आंदोलन का रूप ले लिया और सितंबर के आखिर तक आरक्षण की ये मांग राज्य के अन्य हिस्सों में भी पहुंच चुकी थी। इस बीच देश एक साल बाद होने वाले आम चुनाव और राजनीतिक दबाव बढ़ने से मुख्यमंत्री शिंदे ने जरांगे से मुलाकात की और उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। जरांगे ने 14 सितंबर को 17वें दिन अपना अनशन समाप्त कर दिया था। महाराष्ट्र में 1 सितंबर से चल रहे आंदोलन में मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। इस समुदाय का कहना है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी माना जाता था और कुनबी ओबीसी में आते थे। इसलिए एक बार फिर अब इन्हें कुनबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए।

मराठा समुदाय महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक हैं। महाराष्ट्र के अंदर इस समुदाय का प्रभाव कितना ज्यादा है यह इससे भी समझा जा सकता है कि साल 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक यानी साल 2023 तक, प्रदेश के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्री इसी समुदाय के हैं। राज्य के वर्तमान मंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा ही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी लगभग 33 प्रतिशत के आसपास है। ज्यादातर मराठा मराठी भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदायों को आरक्षण देने को लेकर ये पहला आंदोलन या प्रदर्शन नहीं है। आज से 32 साल पहले माथाडी लेबर यूनियन के नेता अन्नासाहेब पाटिल ने सबसे पहले मुंबई में इस आरक्षण की मांग की थी। इसके बाद साल 2023 में 1 सितंबर को यह मुद्दा तब गर्म हुआ, जब प्रदर्शन के दौरान मराठाओं पर जालना में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। जालना, ये वही जगह है जहां जरांगे-पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे थे। भले ही ये मांग दशकों पुरानी है लेकिन आज तक इस मसले पर कोई स्थायी हल नहीं निकल सका है। हालांकि साल 2014 में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार ने नारायण राणे आयोग की सिफारिशों पर मराठाओं को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक अध्यादेश पेश किया था। मराठाओं को ओबीसी में शामिल करने के उनकी इस मांग ने शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को मुश्किल में डाल दिया है।

● **बिन्दु माथुर**

मराठा आरक्षण को सुप्रीम झटका

साल 2018 में राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत रिजर्वेशन आरक्षण देने का निर्णय लिया। उस वक्त भी इस समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किए जा रहे थे। हालांकि बंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 16 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को घटाकर नौकरियों में 13 प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों में 12 फीसदी कर दिया। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को रद्द कर दिया। अब एक बार फिर मराठाओं का विरोध देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के मराठा अगर निजाम युग से कुनबी के रूप में रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र पेश कर दें तो वे ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। एक तरफ जहां मराठा समुदाय आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, वहीं उनकी इस मांग का ओबीसी के नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। इस विरोध में कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेता भी शामिल हैं। भाजपा नेता आशीष देशमुख ने सितंबर महीने में चल रहे आंदोलन के दौरान कहा था कि मराठाओं को ओबीसी कोटे से आधा फीसदी भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये आर्थिक तौर पर कमजोर नहीं हैं।

वसुंधरा राजे युग से आगे बढ़ी भाजपा

चुनाव बेहद दिलचस्प

मरुधरा में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचित करने वाला रहने वाला है, क्योंकि भाजपा बिना चेहरे और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी में वैसे तो चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं हैं, लेकिन पार्टी कहीं न कहीं इशारों में यह संकेत दे रही है कि चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस का एक वर्ग यह भी चाहता है कि सचिन पायलट के नाम को आगे बढ़ाया जाए। मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर लड़े जाने वाले इस चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा और उसके अगले एक सप्ताह में नई सरकार बन जाएगी। भाजपा यदि सत्ता में आई तो किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज होगा और कांग्रेस अगर सत्ता में बनी रही तो क्या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस बात की बहस इन दिनों राजस्थान में जोर-शोर से हो रही है।

राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी भी एक बड़ा फैक्टर हैं। पांच साल की कोशिशों के बाद भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनका कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन उनके कई समर्थकों का टिकट काटकर जो विरोध झेला, उसके बाद भाजपा आलाकमान को समझ आ गया कि चुनाव जीतना है तो अपने व्यर्थ के अहंकार को किनारे रखना पड़ेगा। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे के समानांतर दीया कुमारी को मैदान में उतार दिया गया है। खास बात ये है कि दीया कुमारी को टिकट भी वसुंधरा राजे समर्थक विधायक की सीट से दिया गया है। ऐसा संकेत समझा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ-साथ राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता और देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरों सिंह शेखावत का प्रभाव पूरी तरह खत्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सौ की एक बात। 2024 का आम चुनाव सिर पर है। विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुए कि आम चुनाव का माहौल बन जाएगा, ऐसे में कोई क्यों इतना बड़ा जोखिम लेगा? ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भले ही वसुंधरा राजे 2018 में विधानसभा चुनाव हार गईं, लेकिन 2019 में भी 2014 की ही तरह राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें एनडीए की झोली में ही रहीं। ये ठीक है कि क्रेडिट मोदी लहर को मिला, लेकिन क्या वसुंधरा राजे का कोई योगदान नहीं रहा?

वर्ष 2018 में राजस्थान में एक नारा जोर-शोर से चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं... तो पार्टी की यही कोशिश है कि किसी भी तरह वो यह संदेश भी दे कि वसुंधरा राजे को इस बार पार्टी नेतृत्व नहीं देने जा रही है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार राजस्थान आ रहे हैं व खुद की गारंटी दे रहे हैं और उन्हीं के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव भी लड़ा जा रहा है। फिर भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, जिनको भावी मुख्यमंत्री की दौड़ में माना जा रहा है, यानी साफ है कि राजस्थान में इस बार यदि भाजपा सत्ता में आती है तो एक नए चेहरे को नेतृत्व दिया जाएगा।

वसुंधरा राजे वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनकी फैन फॉलोइंग राजस्थान में जबरदस्त है। पूर्व राजघराने से आने वाली वसुंधरा के नेतृत्व में दो बार भाजपा सत्ता से कुछ दूर रह चुकी है। वर्ष 2008 और 2018, दोनों बार पार्टी वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारी थी। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी वसुंधरा की छाया से दूर जा चुकी है। जो 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी, उसमें वसुंधरा राजे के खास लोगों का भी टिकट काट दिया गया है। पहली लिस्ट के बाद कुछ जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पार्टी इसे भी एक सुखद संदेश के रूप में ले रही है, क्योंकि जितना विरोध होगा, उतना पार्टी के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ेगा। यह संदेश जाएगा कि पार्टी के प्रति रूझान बढ़ रहा है, इसलिए टिकटों के लिए मारामारी है। जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है तो दौड़ में जोधपुर सांसद व केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री व जोधपुर से ही आने वाले अश्विनी वैष्णव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। विद्याधर नगर से जब दीया कुमारी को टिकट दिया गया तो समर्थक उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चलाने लगे हैं।

अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया गया है और मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम भी चल रहा है। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं, जिससे उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चर्चाओं में हैं। वहीं, जैसा भाजपा में एक सरप्राइज देने का फैक्टर है तो अभी कोई भी इस बात को लेकर 100 प्रतिशत आश्वस्त नहीं है कि पार्टी सत्ता में लौटी तो सेहरा किसके सिर बंधेगा?

राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा का अपना महत्व है। गौरतलब है कि 2019 में वसुंधरा राजे को भाजपा नेतृत्व ने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। मतलब, भाजपा ने एक सर्कुलर निकालकर वसुंधरा राजे को दिल्ली अटैच कर दिया था, लेकिन वो ऐसे कागजों की परवाह कहां करने वाली। चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री आवास तो छूटना ही था, लेकिन धौलपुर पैलेस भला कौन ले सकता है। पुरखों की विरासत है। वो भी राजघराने की विरासत, उसके आगे दिल्ली के बंगले भी फेल। वाजपेयी सरकार में वसुंधरा राजे मंत्री रह चुकी थीं, लेकिन मोदी सरकार में ये सब उनको कतई मंजूर न था। पांच साल होने जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा टस से मस नहीं हुईं। जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होने को कतई राजी नहीं हुईं और अब एक बार जब राजस्थान में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं तो वसुंधरा राजे ठानकर बैठी हैं कि भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री तो वही बनेंगी। वसुंधरा राजे की ताकत ही अब उनकी मुसीबत बन गई है। असल में राजनीति में भी उन्होंने वसुंधरा घराना बना रखा है। भाजपा नेतृत्व उस घराने को फूटी आंख नहीं देखना चाहता। ऐसा भी नहीं कि वसुंधरा घराने की ही हर तरफ तूती बोलती हो, लेकिन कुछ क्षेत्रों में दबदबा तो है ही। वसुंधरा राजे उसी दबदबे की राजनीति कर रही हैं। जब तक मुख्यमंत्री रहीं, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राज्य में नया अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती थी। भाजपा नेतृत्व जिसे जिम्मेदारी देना चाहता था, वो चेहरा वसुंधरा को नहीं पसंद था। नियुक्ति नहीं हुई। राजस्थान भाजपा को नया अध्यक्ष तभी मिला जब चुनाव हार जाने के बाद वसुंधरा का असर थोड़ा कम हुआ।

● **जयपुर से आरके बिन्नानी**

दलित वोट पर सभी दलों का दांव

इस बार बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस (9 अक्टूबर) पर अकेले बसपा ने कार्यक्रम नहीं किए। कांग्रेस और सपा की ओर से भी धूमधाम से मान्यवर कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया।

कांग्रेस की ओर इसी दिन राज्यव्यापी दलित गौरव संवाद यात्रा की शुरुआत हुई है जो 26 नवंबर संविधान दिवस तक चलेगी। उप्र में दो विधायक और एक सांसद तक सिमट चुकी कांग्रेस को उम्मीद है कि कांशीराम की बसपा के उभार के साथ जो दलित वोटर उससे छिटक गए थे अब मान्यवर कांशीराम का नाम लेने से वापस आ जाएंगे।

असल में पिछले महीने उप्र के घोसी विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में बसपा नेत्री मायावती ने अपने मतदाताओं से अपील की थी कि दलित समाज के लोग या तो वोट न करें या फिर नोटा का बटन दबाकर अपना वोट डाल दें। बसपा मुखिया की यह अपील उनके ही अधिकांश समर्थकों ने ठुकरा दी। बहुजन समाज पार्टी के लिए तो यह खतरे की घंटी साबित हुई, लेकिन यहीं से सपा, कांग्रेस और भाजपा के लिए उम्मीदों का एक नया दरवाजा भी खुल गया है। यह दरवाजा है मायावती के दलित वोट बैंक में पैठ बनाने का। सब जानते हैं उप्र में जो जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। यही कारण है कि आगामी लोकसभा चुनाव में 80 सीटों के लिए दलित वोटरों को अपना बनाने के लिए सबने अपनी-अपनी न सिर्फ रणनीति तैयार कर ली है बल्कि बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है। मजेदार बात यह है कि सभी दलों ने दलित वोट हासिल करने के लिए घुमा-फिराकर उसी तरह की योजना तैयार की है जिसे दशकों पहले कांशीराम ने सबसे पहले आजमाया था।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर दलित समाज को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की अपील की है। लखनऊ में आयोजित पार्टी की अंबेडकर वाहिनी की बैठक को संबोधित करते हुए दलित समाज को जोड़ने का अभियान तेज करने का आव्हान किया। पिछले दो चुनावों में मिली हार से समाजवादी पार्टी लगभग किंकर्त्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में है। इस दरमियान येन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह-तरह के सुलह समझौते भी करती रही है। जिस कांग्रेस का विरोध कर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उनके रहते ही गद्दी पाने की लालसा में अखिलेश यादव ने उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां कर पार्टी की मिट्टी पलीत कर दी। हालांकि इस गठजोड़ का लाभ उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उप्र में अपनी सीटों का आंकड़ा कुछ बढ़ा लिया था, लेकिन सपा के हाथ निराशा ही आई थी। इसी तरह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद अखिलेश यादव ने बसपा के साथ भी चुनावी गठबंधन किया था। चुनाव में मशहूर बुआ-बबुआ की जोड़ी का भी कमोबेश वही हश्र हुआ, जैसा सपा-कांग्रेस का पिछले चुनाव में हुआ था।

बरसों बाद दलित वोटों की संजीवनी से समाजवादी पार्टी को घोसी उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत मिली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित मतदाताओं से वोट न करने अथवा नोटा का बटन दबाने की अपील की थी, लेकिन उनके आदेश को अनसुना कर दलितों ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा समाजवादी पार्टी या भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया। पार्टी के पक्ष में परिणाम आने के बाद से ही सपा प्रमुख पार्टी की अंबेडकर वाहिनी को सक्रिय करने में जुट गए। मिले मुलायम-कांशीराम के फॉर्मूले को नए सिरे से परिभाषित करते हुए दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। असल में दलित समाज के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली बसपा पिछले एक दशक से लगातार कमजोर हो रही है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में आज उसके पास केवल एक सीट है, जिसके कारण बहुजन आंदोलन भी कमजोर होता जा रहा है। प्रदेश के करीब 22 प्रतिशत दलित वोटों पर बसपा का कब्जा था लेकिन अब माना जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जमीनी राजनीति से सक्रियता खत्म होने के कारण दलित वोटों में भी बिखराव हो रहा है।

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.24 प्रतिशत वोट पाने वाली मायावती की पार्टी का वोट शेयर विधानसभा चुनाव 2022 में 12.81 प्रतिशत रह गया है। माना जा रहा है कि बसपा के पास दलितों में केवल हरिजन/जाटव वोट बचा है, गैर हरिजन/जाटव वोट का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ जुड़ गया है अथवा सपा के पास चला गया है। वर्तमान में कांग्रेस के पास विधानसभा की दो सीटें हैं जबकि संसद में केवल एक सीट है। अब बात करते हैं उप्र की सबसे ताकतवर पार्टी भाजपा की। भाजपा के सभी सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी और बाकी जिम्मेदार नेता दलित जोड़ो अभियान पर मंथन कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति के दो फॉर्मूले हैं, लोकसभा की 17 सुरक्षित सीटों के लिए अलग तैयारी और बाकी 63 सीटों के लिए दूसरी तरह की योजना है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दलित समाज को जोड़ने की योजना बनाई गई है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

दलितों को अपना बनाने की तैयारी

दलितों को अपना बनाने के लिए अगले लोकसभा चुनाव तक की पूरी योजना भाजपा ने तैयार कर ली है। तय हुआ है कि उप्र के कुछ शहरों में ऐसी रैली की जाए जिससे देशभर में संदेश जाए। प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में दलित महासम्मेलन किया जाएगा जिसमें पार्टी के बड़े नेता हिस्सा लेंगे। आगे चलकर जिलों में भी पार्टी दलित सम्मेलन और रैली करने की योजना तैयार की है। बस्ती संपर्क अभियान के तहत बस्तियों में लाभार्थियों से संपर्क सहित समाज के प्रबुद्ध वर्ग, सेवानिवृत अधिकारी, खिलाड़ी, लोक कलाकारों व अन्य प्रमुख लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने की भी पार्टी ने योजना तैयार की है। राजनीति में दलित दखल की बात करें तो भारतीय राजनीति में एक नारा बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया गया जो काफी चर्चित हुआ था। जगजीवन राम की आई आंधी, उड़ जाएगी इंदिरा गांधी... नारा लगा भी खूब और जनता पार्टी की सरकार भी बनी। लेकिन जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके। जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के तीन दावेदार थे, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो दलित समुदाय में काफी रोष आ गया, कहा जाता है कि उस समय देश में कई दलित घरों में खाना नहीं बना था। दलितों में पनपे इस रोष को आगे बढ़ाया कोशीराम ने। उन्होंने भी शुरूआत दलित चेतना के आंदोलन से की। उन्होंने दलित के साथ पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा। सरकारी दफ्तरों में इन वर्गों के संगठन बनाए। इसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। अंबेडकर की विचारधारा को जमीन पर उतरने का काम कांशीराम ने किया और उसे उप्र में आगे बढ़ने का काम मायावती ने।

घोटालों को दबाने का जतन

बिहार में जाति जनगणना के बाद तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों में जानबूझकर कुछ जातियों को कमतर दिखाने का आरोप तो लग ही रहा है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का पांसा अपने शासनकाल में हुए घोटालों को छिपाने के लिए फेंका है।

नीतीश शासन की बहती गंगा मानकर जिन घोटालों में हाथ धोए गए हैं, उनमें से सबसे चर्चित सृजन घोटाला था। हजार करोड़ के इस घोटाले का नाम सृजन घोटाला इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार के भागलपुर जिले में सृजन महिला सहयोग समिति नाम की एक संस्था इससे जुड़ी थी। मनोरमा देवी नाम की एक महिला ये एनजीओ चलाती थी। सरकार से जो फंड इन्हें काम करने के लिए मिलते थे, उसे बीच में ही गायब करके दूसरे बैंक खातों में डाल दिया जाता था। जो सूद मिलता उससे दिखाने के लिए छोटा-मोटा कुछ-कुछ काम जैसा आयोजन इत्यादि किया जाता और करोड़ों का मूलधन आराम से सूद कमाने के लिए रख लिया जाता। ये कार्यक्रम सात वर्षों तक 2007 से 2014 के बीच चलता रहा। इस दौरान मनोरमा देवी ने जो अन्य कारनामे किए उनमें 2003 में 24000 स्क्वायर फीट की जमीन 30 वर्षों के लिए लीज पर ली, जिसके लिए उन्होंने 2400 रुपए की भारी भरकम रकम अदा की थी! शुरूआती पुलिस प्राथमिकियों की मानें तो ये घोटाला 16 दिसंबर 2003 से 31 जुलाई 2017 तक चलता रहा, जिसमें सरकारी खजाने से अवैध निकासी होती रही।

एक सामाजिक कार्यकर्त्ता शिवेश भारती ने पटना उच्च न्यायलय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि 3608 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सीतामढ़ी में तटबंधों की हालत खस्ता है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच करने के आदेश दिए। इस मामले के सामने आने पर राजद के नेताओं ने (जो कि उस वक्त विपक्ष में थे) जमकर बवाल काटा। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले के सजायाफ्ता अपराधी लालू यादव तक कहने लगे कि बिहार में घोटालों की सेल लगी है- एक पर एक मुफ्त ले लो! अभी का हाल देखें तो चाचा-भतीजा यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार चला रहे हैं। घोटाले का क्या हुआ पता नहीं। वैसे इस मामले में सच्चाई बाहर आने की कितनी संभावना थी, इसका अनुमान आप इस बात से लगाइए कि जांच जल संसाधन विभाग के कर्मियों पर होनी थी और अदालत के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग के ही 72 कर्मचारी इस घोटाले की जांच कर रहे थे! उस दौर के राजद नेताओं के बयानों की मानें तो ये घोटाला भी 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर का था।

गंगा ब्रिज घोटाला

गंगा ब्रिज घोटाला तो बिहार का सबसे ताजा घोटाला है जो तेजस्वी यादव का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इस घोटाले पर रोशनी डालने के लिए मनीष कश्यप का नाम लिया जाता है। मनीष कश्यप पर फिलहाल तमिलनाडु की पुलिस ने एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया है और दूसरे कई पुराने मामले खोदकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई भी लगी हुई है। गंगा नदी पर भागलपुर जिले में आगुवानी-सुल्तानगंज के बीच सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण हो रहा था। इस 3 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 2017 में शुरू हो गया था। पहली बार ये पुल 30 अप्रैल 2022 को टूटा था। उसके बाद यही पुल 5 जून 2023 को टूट गया। जब दूसरी बार ये पुल टूटा तब इस पर कथित रूप से 8 मजदूर थे और एक गार्ड था जो कि लापता है। इस पुल को 2020 में ही बनकर पूरा हो जाना था और इसकी लागत थी 1710 करोड़ रुपए। नियत समय के तीन साल बाद भी ये पुल बनते-बनते ही टूट क्यों रहा है? कहा जाता है कि इससे पार्टी फंड में दस फीसदी यानि 171 करोड़ रुपए का कट जा रहा है। अब ब्रिज का क्या है? ब्रिज तो बनता और टूटता रहता है।

अब बात महादलित घोटाले की करते हैं। इस घोटाले का नाम महादलित घोटाला इसलिए पड़ा क्योंकि नीतीश बाबू की सुशासन सरकार ने दलितों में भी कुछ जातियों को चुनकर महादलित घोषित कर दिया था। महादलितों को अंग्रेजी बोलना और कम्प्यूटर चलाना सिखाने के नाम पर 2010 से 2016 के बीच घोटाला किया गया। इस मामले में राज्य की विजिलेंस ब्यूरो ने 23 अक्टूबर 2017 को एसएम राजू पर एफआईआर दर्ज की। बाद में एक दूसरी एफआईआर हुई जिसमें कई आरोपी थे।

ब्रिटिश लिंगुआ नाम की एक संस्था जो पटना में खासी प्रसिद्ध है, उसके निदेशक बीरबल झा, उस दौर के मिशन निदेशक और रिटायर हो चुके आईएएस अफसर राघवेंद्र झा और राजनारायण लाल, रामाशीष पासवान, मिशन के तब के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा (जो कि अब रिटायर हैं), मिशन के कोऑर्डिनेटर शशि भूषण सिंह, सहायक निदेशक हरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और बिरेंद्र चौधरी और तब के मिशन के स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर देबजानी कार को भी बाद में एफआईआर में आरोपी बनाया गया। विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक 2012-13 से लेकर 2015-16 के बीच ब्रिटिश लिंगुआ को 7.3 करोड़ रुपए दिए गए। उन्हें 40-40 छात्र-छात्राओं के बैच को पढ़ाना था लेकिन जांच में पता चला कि जिन छात्र-छात्राओं का नाम एक बैच में था, वही नाम दूसरे कई बैच में भी थे! इस तरह बिना पढ़ाए ही महादलितों के नाम पर पैसे लिए जाते रहे। इस मामले की जांच भी अभी तक चल रही है। टॉयलेट घोटाला कहीं दूर नहीं हुआ था। सुशासन बाबू की सरकार के ठीक नाक के नीचे, राजधानी पटना से इस घोटाले की बदबू उठने लगी। पंद्रह करोड़ का ये घोटाला करने में ज्यादा समय भी नहीं लगाया गया था। केवल 1 से 16 जून 2016 के बीच पंद्रह करोड़ रुपए जो केंद्र की स्वच्छ भारत मिशन योजना के थे, वो गायब हो गए। तब के पटना के डीएम संजय अग्रवाल ने पाया कि नियमों को ताक पर रखकर पैसे निकाले गए हैं तो उन्होंने जांच करवाई कि सचमुच शौचालय बने भी हैं या नहीं?

● **विनोद बक्सरी**

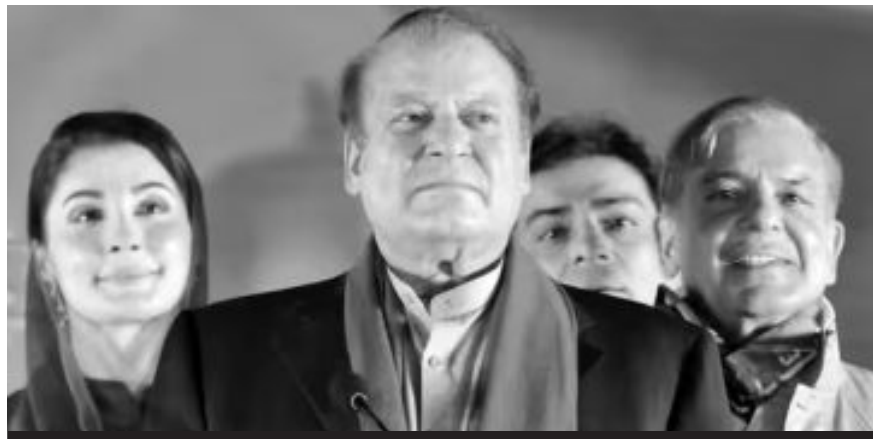

शरीफ के सामने दोहरी चुनौती

नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ गए हैं। उनकी यह वतन वापसी लगभग 4 वर्ष बाद हुई है। नवंबर 2019 में कोर्ट के आदेश पर वह इलाज कराने लंदन गए थे। उसके पहले वह एवन फील्ड और अल अजिजिया मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सात साल की सजा भुगतने के लिए जेल में थे। लंदन जाने से पहले वह लगभग एक साल जेल में रहे, जहां उनकी हालत खराब बताई गई और उसी के आधार पर उन्हें लंदन जाने दिया गया। अब सिर्फ एक सवाल लोगों के जेहन में है कि क्या उनकी वतन वापसी सत्ता में भी उनकी वापसी की गारंटी होगी या उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा?

जेल में इसलिए कि अभी उनकी पहचान एक फरार मुजरिम की है। समय पर कोर्ट में ना पेश होने के कारण अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर रखा है। पाकिस्तान में जो इस समय हालात हैं उसमें नहीं लगता कि उन्हें तत्काल जेल भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी वापसी ही तभी कराई गई है, जब उनकी पार्टी नेताओं को यह यकीन हो गया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई राहत मिल ही जाएगी। इसके लिए उनकी लीगल टीम तैयारी कर रही है। हालांकि नवाज की पार्टी को छोड़कर इन दिनों पाकिस्तान की हर पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री एक डील के तहत आ रहे हैं। यहां तक कि हाल तक सत्ता में साथ रही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं। डील पर यकीन करने के पर्याप्त कारण भी हैं। पहला यह कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के खिलाफ पाकिस्तान की फौज नहीं है। अलबत्ता वापसी के पहले आर्मी चीफ ने यह संदेश जरूर उनके भाई शहबाज शरीफ के जरिए ही लंदन भिजवा दिया था कि नवाज शरीफ को सिर्फ उसी सूरत में तकलीफ हो सकती है, जब वह अपनी तकरीरों और बयानों में आर्मी को निशाना बनाएंगे, चाहे वह पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ही क्यों ना हो।

पाकिस्तान की आर्मी की एक खास बात है कि वह कभी वर्तमान या पूव सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुन सकती। जिस किसी राजनीतिक नेता या पत्रकार ने आर्मी के खिलाफ आवाज उठाई या तो वह जान से गया या अपने परिवार से गया। पिछले दिनों कई पत्रकार और नेता इसका स्वाद चख चुके हैं। नवाज शरीफ को यकीन है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा तभी वह आते ही लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान में जलसे का आयोजन करा रहे हैं। मीनार-ए-पाकिस्तान लाहौर की वह जगह है, जहां 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम देश के लिए प्रस्ताव पास कराया था। उसे लाहौर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। बाद में 1960 से 68 के दौरान यहां एक 70 मीटर ऊंची मीनार खड़ी की गई और तब से इसका नाम मीनार-ए-पाकिस्तान पड़ गया। यहां बहुत बड़ा मैदान है जिसमें डेढ से दो लाख लोग जमा हो सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी राजनेता जब ऐतिहासिक रैली की बात करता है तो यहीं आता है। बेनजीर भुट्टो और इमरान खान भी यहां जलसा कर चुके हैं।

लेकिन नवाज शरीफ का यकीन अपनी जगह है, कानूनी पहलू अपनी जगह है। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ही 28 जुलाई 2017 को पनामा केस में कसूरवार मानते हुए आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया था। तब इस फैसले को सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ में जस्टिस उमर अता बांदियाल भी थे, जो पिछले 17 सितंबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए हैं। यह पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में बांदियाल अपने रिटायरमेंट से पहले चुनाव कराने का आदेश दे चुके थे, जिसे शहबाज शरीफ की सरकार बड़ी मुश्किल से टालने में सफल हुई थी। नवाज शरीफ की वतन वापसी में देरी और इसकी तिथि 21 अक्टूबर को करने के पीछे एक बड़ी वजह जस्टिस बांदियाल भी थे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके पद पर रहते नवाज को पाकिस्तान लाने का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थी। खैर जस्टिस बांदियाल जाते-जाते नैब के कानून में बदलाव के पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के प्रस्ताव को ही गैर कानूनी ठहरा गए, जिसके तहत सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खास लोगों पर नैब के अधीन मुकदमा दायर करने से छूट मिल सकती थी। नवाज शरीफ पर इस समय दो केसों में सजा और कम से कम चार मुकदमों का बोझ है। वह इनसे निकलेंगे और चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, इसको लेकर तमाम दावे हैं। नवाज शरीफ दुबई से चार्टर प्लेन के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। वहां से रैली निकालकर लाहौर पहुंचे।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

राहत मिलने की उम्मीद पूरी

बहरहाल नवाज शरीफ के लिए मामला बहुत आसान भी नहीं होगा। हालांकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के होने से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद पूरी है। फिर भी उन्हें दो मोर्चों पर अभी संघर्ष करना पड़ सकता है। पहला यह कि क्या उन्हें तत्काल जमानत मिल जाएगी और वह राजनीतिक अभियान शुरू कर सकेंगे और दूसरा कि क्या उन पर लगे आजीवन प्रतिबंध की मियाद खत्म मानी जाएगी? दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना है। संसद को सुप्रीम मानते हुए जस्टिस काजी अपने ही पूर्ववर्ती जज के फैसले को बदलकर यह राहत दे सकते हैं। जैसे नैब कानून में संशोधन और किसी राजनीतिज्ञ को अधिकतम पांच साल के प्रतिबंध के प्रस्तावों को नए चीफ जस्टिस सही ठहरा सकते हैं। वैसे जस्टिस काजी यह पहले टिप्पणी कर चुके हैं कि नेशनल असेंबली यदि कानून बनाने का अधिकार रखता है तो उसमें परिवर्तन का भी अधिकार उसके पास है। नवाज शरीफ अब 73 साल के हो चुके हैं। 35 साल से अधिक समय से वह राजनीति में हैं। उन्हें पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। इमरान खान तो सार्वजनिक सभाओं में भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जनरल जिया के जूते पॉलिश किया करता था। जो भी हो नवाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ-साथ पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह 1990, 1997 और 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के टेस्ट का श्रेय उन्हीं को जाता है। पर इस समय पाकिस्तान महंगाई और गरीबी के न्यूक्लियर बम पर बैठा हुआ है। ऐसे में वतन वापसी के साथ नवाज शरीफ के लिए दोहरी चुनौती होगी।

जमीन और मजहब की जंग

इजरायल का गठन होने के सालभर के भीतर उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद अस्तित्व में आ गई थी। मोसाद के जिम्मे सिर्फ एक काम था टू प्रिवेंट अनदर होलौकॉस्ट। यानी मोसाद को दुनियाभर के यहूदियों के लिए ऐसी नीति पर काम करना था कि भविष्य में कभी उनका कत्लेआम न हो। एक राष्ट्र के रूप में इजरायल के कंधे पर सिर्फ यहां रहने वाले यहूदियों को नहीं बचाना था बल्कि पूरी दुनिया के यहूदियों को संभावित खतरे से बचाना था। यह आसान काम नहीं था। वह भी तब एक इस्लाम नामक दीन ने उन्हें अपना घोषित दुश्मन बना रखा हो जिनकी जनसंख्या अब ईसाइयों के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन मोसाद ने लगभग इस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता ही पाई है सिवाय छुटपुट झड़पों के अलावा। लेकिन 2008 के मुंबई में आतंकी हमले और अब 7 अक्टूबर को हमास के मुजाहिदों द्वारा इजरायल के 22 बस्तियों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला करके लगभग 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।

हमास के मुजाहिदों ने जिन यहूदियों की हत्या की वो आम नागरिक थे। कोई अपने घर में था तो कोई उस रात यहूदी पर्व का जश्न मना रहा था। इन हत्याओं में उनकी युद्धनीति नहीं बल्कि यहूदियों से नफरत की आतंक नीति साफ-साफ दिखाई देती है। हमास के मुजाहिद उन्हें सिर्फ इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो यहूदी थे जिसके यहूदी होने भर से वो नफरत करते हैं और उन्हें पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहते थे। स्वाभाविक है यहां इजरायल के सुरक्षा प्रतिष्ठानों की असफलता के सिर्फ दो संभावित कारण हो सकते हैं। या तो उन्हें पहले कुछ पता नहीं चला या फिर वे अति आत्मविश्वास में आधुनिक तकनीक पर निर्भर होकर निश्चिंत हो गए थे, और हमास जानबूझकर उन्हें गफलत में रखता गया। कारण जो भी हो लेकिन 1967 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यहूदी नागरिक इजरायल की धरती पर आतंकी हमले में मारे गए जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और सुरक्षा बलों के लोग, सब शामिल हैं। इस हमले में न केवल इतनी बड़ी संख्या में यहूदी मारे गए, बल्कि 200 से अधिक लोग बंधक बनाकर गाजा ले जाए गए जिसमें इजरायल के अलावा अन्य देशों के नागरिक भी शामिल थे। अब तक हमास द्वारा 2 अमेरिकी और 2 इजरायली नागरिकों को स्वास्थ्य कारणों या फिर उम्र को देखते हुए रिहा किया गया है। इसमें जिन दो इजरायली नागरिकों को बुजुर्ग होने के कारण हमास द्वारा रिहा किया गया है उनमें से एक 85 वर्षीय योश्चेव लिफशिट्ज का कहना है कि वो एक नारकीय यातना से बाहर आई है।

स्वाभाविक है इजरायल पर हमले के दौरान हमास ने जिनको अगवा किया है उनको मानवीय सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। फिलिस्तीन पर काम करने वाले सुरक्षा विशेषज्ञ इसका एक और कारण गाजा में बनी सुरंगों को बताते हैं जहां वो युद्ध के दौरान खुद भी छिपते हैं और इन बंधकों को भी छिपा रखा है। इन सुरंगों के बारे में वहां के सुरक्षा जानकार बताते हैं कि मकड़ी के जाले की तरह बनी इन सुरंगों में कोई छिप तो सकता है और हवाई हमलों से भी बच सकता है लेकिन इन सुरंगों में जिंदा रहना ही एक बड़ी चुनौती है। इजरायल की रिचमैन यूनिवर्सिटी के असिटेंट प्रोफेसर रिचमंड बराक ने एक अमेरिकी मीडिया हाउस को बताया कि मैं इन सुरंगों में जा चुका हूं। एक बार जब आप सुरंगों में प्रविष्ट हो जाते हैं तो आपकी इंद्रीय चेतना खत्म हो जाती है। आप कहां हैं, और दिन है या रात इसका कुछ आभास नहीं रह जाता। इन सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि गाजा और मिस्र के बीच भी इसी तरह की सुरंग बनाई गई है, जहां से आतंकी अपने लिए हथियारों और अन्य साजो सामान की स्मगलिंग करते हैं। ये सुरंगे इजरायली सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती हैं, इसलिए अमेरिका भी इशारों में इजरायल को ग्राउंड अटैक करने से रोक रहा है।

इस बात की पूरी संभावना है कि इजरायल में जो बंधक बनाए गए हैं वो इन्हीं सुरंगों में रखे गए हों जिन तक पहुंचना इजरायली सुरक्षा बलों के लिए आसान काम नहीं होगा। हालांकि बमबारी करके और चेतावनी देकर इजरायल पहले ही गाजा सिटी के अधिकांश हिस्सों को खाली करा चुका है। फिर भी जमीनी हमला करके बंधकों को छुड़ाना नर्क से जिंदा बचकर निकलने जैसा होगा। इस बात का इशारा खुद उस इजरायली बुजुर्ग ने कर दिया है जिसे हमास ने रिलीज किया है। स्वाभाविक है हमास के मुजाहिद जिन तरीकों से इजरायल से लड़ रहे हैं और उसके नागरिकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वह सिर्फ जमीन का झगड़ा भर नहीं हो सकता। इसकी जड़ें उससे गहरी है जो मजहबी मान्यताओं में निहित हैं। येरुसलेम पर न केवल यहूदियों का दावा है बल्कि मुस्लिम भी लगभग 1400 साल से उस जगह पर दावा करके बैठे हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ येरुसलेम पर दावे तक रहती तो इस तरह की दुश्मनी पैदा नहीं होती कि दोनों एक-दूसरे के बच्चों तक की परवाह न करते।

● **कुमार विनोद**

मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संगठन से प्रेरित है हमास

बुनियादी फसाद इस्लामिक शिक्षाओं में है जो यहूदियों को अपना खुला दुश्मन बताती है। जब तक यासिर अराफात ने फिलिस्तीन का संघर्ष किया वह जमीन की जद्दोजहद थी इसलिए एक समय के बाद यासिर अराफात ने युद्ध की बजाय शांतिपूर्वक बातचीत का रास्ता चुन लिया। लेकिन अब जो हमास फिलिस्तीन के नाम पर इजरायल से लड़ रहा है उसकी जंग फिलिस्तीन की जमीन से अधिक यहूदियों से मजहबी दुश्मनी है। हमास जिस मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संगठन से प्रेरित है उसके मूल में इस्लामिक जिहाद है। हसन अल बन्ना ने इस इस्लामिक ब्रदरहुड की शुरुआत ही गैर मुस्लिमों से जिहाद के लिए की थी जिसमें सबसे ऊपर यहूदी थे। यहूदी इस बात को जानते भी हैं और समझते हैं कि वह जिस युद्ध में धकेले गए हैं वह सिर्फ जमीन पर दावे का झगड़ा भर नहीं है। यह उनके धरती से समूल सफाए का झगड़ा है। अगर उन्हें बचे रहना है तो उन्हें न केवल लड़ना पड़ेगा बल्कि आक्रामक होकर निपटना पड़ेगा। सिर्फ इजरायल की धरती पर ही नहीं बल्कि इजरायल के बाहर भी उन्हें यह जंग लड़नी होगी तभी वो बचे रह पाएंगे। इसीलिए मोसाद का गठन करते समय लक्ष्य एकदम स्पष्ट रखा गया कि अब भविष्य में हमें होलौकॉस्ट (विध्वंस) से बचना है।

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

कर्म-प्रेम का पाठ पढ़ाती है भगवद्गीता

श्रीमद्भगवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता का सार संपूर्ण जीवन दर्शन है... गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है।

गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्रीकृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता में श्रीकृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। आइए यहां जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश।

वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार- गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के तीन द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्म-विनाशकारी मानी जाती हैं।

मिट्टी में मिल जाएगा शरीर- श्रीकृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? श्रीकृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं...!!

किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता- अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य! तुम अपने आपको भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार, किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता, अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सबकुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं!

भविष्य का मजाक मत उड़ाओ- किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे-धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।

हमारा कर्म करता है भाग्य निर्धारित- गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं।

सफलता के लिए भगवत गीता सूत्र- हर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने ऐसी अनेक बातें बताई हैं जिन्हें हम जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए जानतें है क्या वे बहुमूल्य बातें।

महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बहुमूल्य बातें बताई थी। उनके द्वारा दिए गए यह उपदेश भगवत गीता में निहित हैं। गीता में उन सभी मार्गों की चर्चा की गई है जिन पर चलकर मोक्ष, बुद्धत्व, कैवल्य या समाधि प्राप्त की जा सकती है।

योजना बनाने का क्या है महत्व- अगर कोई व्यक्ति योजना के तहत काम करता है तो उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। इसलिए श्रीकृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले एक योजना जरूर बनाएं। इससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।

सोच-समझकर चुने संगति- अपने जीवन में हमेशा सोच-समझकर लोगों को चुनना चाहिए। क्योंकि संगति का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। भले ही आप अच्छे हों लेकिन आपके साथी अच्छे नहीं है तो आपको बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। महाभारत में ही इसका उदाहरण मौजूद है। दुर्योधन हमेशा अपने मामा के बताए रास्ते पर चला, जिसके कारण एक दिन उसका पूरा राजपाट चौपट हो गया।

अधूरा ज्ञान होता है खतरनाक- ज्ञान न होना हानिकारक है, लेकिन अधूरा ज्ञान होना उससे भी ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि कम ज्ञान वाले व्यक्ति बेवजह हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम की पूरी जानकारी के बाद ही उसे शुरू करें। वरना व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है।

इस बात का रखें ख्याल- आज के समय में किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना मूर्खता है। सोच-समझकर अपने दोस्तों का चुनाव करें। इस विषय पर भगवान श्रीकृष्ण भी कहते हैं कि हमेशा जांच परख कर ही अपना मित्र चुनना चाहिए। क्योंकि मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आपके सारे राज पता होते हैं।

खुश रहने का सूत्र- भगवान श्रीकृष्ण ने मन को मित्र और शत्रु दोनों ही बताया है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं रखता वह उसके लिए शत्रु का काम करता है। साथ ही भगवान ने यह भी कहा है कि इस दुनिया में खुश रहने का एक ही सूत्र है और वह है इच्छाओं का कम होना।

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने मैनेजमेंट के जो सूत्र बताएं हैं वो आज भी आपको सफलता दिला सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या फिर आपके अंडर में लोग काम करते हैं तो कृष्ण भगवान के सूत्र जरूर जान लीजिए... अपनी लाइफ में फॉलो करके बेस्ट मैनेजमेंट गुरू बन सकते हैं। कौरव और पांडव के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन को कौरवों के रूप में अपने ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसे में वह धनुष उठाने से मना कर देते हैं। तब श्रीकृष्ण युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को अपने उपदेशों से नैतिकता और अनैतिकता का पाठ पठाते हैं, और युद्ध के लिए कहते हैं। इसी तरह आज के मैनेजर को भी असंभव लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए जाते है। ऐसे में कृष्ण जैसे बॉस की जरूरत है जो टारगेट पूरा करने में हेल्प करे।

आपने काम पर अहंकार ना करें नुकसान होगा- गीता में कहा गया है कि अहंकार के कारण नुकसान होता है। ऐसे ही जिंदगी में जब सफलता मिलती है...तो हम अहंकार से भर जाते हैं...उसके बाद हमारा पतन शुरू हो जाता है...इसलिए गीता में श्रीकृष्ण का ज्ञान आज के मैनेजर पर भी लागू होता है।

खुद को नई तकनीक से अपडेट करते रहिए- श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, पर साथ में आगे बढ़ने के लिए अपने आपको अपडेट भी करते रहो। अपने ज्ञान को अपडेट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। समय को पहचानें और उसके मुताबिक चीजे सीखें। तभी आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में श्रीकृष्ण सबको साथ लेकर चलते थे। इसी तरह आप के प्रबंधन या मैनेजमेंट में जो भी आपके अंडर में काम करते हैं आपको उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। अहंकार ना करें और हमेशा सीखने का स्वभाव रखें। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को जीवन में हमेशा सफलता मिलती है।

● **ओम**

राशिफल

राम-राम पंडित जी। राम-राम एडिटर साहेब।

पंडित जी, आज मैंने आपको इसलिए फोन लगाया है क्योंकि आपने कल के अंक के लिए अभी तक राशिफल नहीं भेजा है।

एडिटर महोदय, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब होने के कारण मैं अपने गांव आ गया हूं। जल्दबाजी में अपना लैपटॉप लाना भूल गया। इसलिए मैं आपको ईमेल नहीं कर पाऊंगा। कृपया आप एक हफ्ते पहले के किसी भी दिन का राशिफल उठाकर कल के अंक में छाप दीजिएगा।

परंतु पंडित जी, ये तो गलत होगा न हमारे लाखों पाठकों के साथ...

देखिए एडिटर साहेब, धरती की आबादी छह अरब से भी ज्यादा हो गई है। राशि हैं कुल बारह। मतलब ये हुआ कि एक-एक राशि पचास करोड़ से ज्यादा लोगों को कव्हर करती है। सौ बात की एक बात कहूं, तो राशिफल किसी न किसी पर तो फिट बैठेगा ही न। और फिर मैं लैपटॉप लाया होता, तो खुद ही आपको कुछ भी कॉपी-पेस्ट करके भेज देता। पहले भी मैंने कई बार ऐसा किया है। अब आप ज्यादा मत सोचिए। जल्दी से कॉपी-पेस्ट कर डालिए। रखता हूं फोन। गुड नाईट।

संपादक महोदय सोच में पड़ गए, जब कॉपी-पेस्ट ही करनी है तो फिर इस पंडित की जरूरत ही क्या है?...

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

वादा

पूरे 15 दिनों के बाद स्नेहा अस्पताल से रिलीव होकर आई, आते ही किचन और घर संभालने में लग गई। पंखे के परों के साथ उसका अतीत भी घूमने लगा।

आईसीयू में 12 दिन उसको जमीन पर पांव ही नहीं रखने दिया गया। वॉर्ड में शिफ्ट होने के लिए उसने जमीन पर पांव रखा, पर यह क्या! लड़खड़ा गई वह! अब घर में कैसे चलेगी! कैसे काम करेगी! उसे चिंता लग गई।

चलना तो पड़ेगा ही!... उसने अपने आप से वादा किया।

उम्मीद का दामन थामे वह अस्पताल के दो कर्मचारियों की मदद से चलने का प्रयास करने लगी। प्रयास अभ्यास में बदल गया, अभ्यास विश्वास में और फिर विश्वास सफलता में।

खुद से किया गया वादा उसने पूरा कर लिया था।

- लीला तिवानी

दूसरी पारी

साठ का आंकड़ा, पार क्या किया
लगता है जैसे, नए पंख लग गए
नई-नई विधाओं, से हुआ सामना
खुशियों से रंग मंच, सज गए।
सोये हुए सब, अरमान जग गए।
अब कुछ समय की, कमी नहीं है
तमन्नाएं भी दिल में, भरी पड़ी हैं
कुछ तो लोगों ने, उत्साह बढ़ाया,
कुछ खुदबखुद, परवान चढ़ गए।
सोये हुए सब, अरमान जग गए।।

नए-नए लोगों से, हुआ सामना
भरा पड़ा था, अकूत खजाना
एक से बढ़कर, एक हिम्मतवाले
हम तो बस उनके, पीछे लग गए।
सोये हुए सब, अरमान जग गए।।

कोई संगीत में, महा निपुण है
तो कोई साहित्य, में पीटे डंका
नृत्य कला में, है कुछ की महारथ
चित्रकारी में, कुछ किस्से गढ़ गए।
सोये हुए सब, अरमान जग गए।।

यहां तो हर सख्श, ही निर्देशक है
भिन्न-भिन्न कलाओं, का पोषक है
हो बांसुरी वादन, या उत्कृष्ट गायन
सब अपने क्षेत्र में, कमाल कर गए
सोये हुए सब, अरमान जग गए।।

योग और ध्यान में, कुछ माहिर हैं
आयुर्वेद के गुण, जग जाहिर हैं
जन कल्याण ही, इनका मकसद
ज्ञान से अपने, ये अभिभूत कर गए
सोये हुए सब, अरमान जग गए।।

सब ही मिलने को, रहते बेकरार
सुनाते दिलों को, दिलों की झंकार
देखते ही देखते, समां बांध जाते
पता न चलता, कब नौ बज गए।
सोये हुए सब, अरमान जग गए।।

बस कहने भर को, है दूसरी पारी
सच पूछो तो अब, यह दुनिया सारी
प्रेम, स्नेह, मिलन, से यह जगमग
हम तो बस इसके, रंग में रंग गए।
सोये हुए सब, अरमान जग गए।।

- नवल अग्रवाल

पाकिस्तान पर हावी भारत

इस समय क्रिकेट विश्वकप का घमासान चल रहा है। भारत इस बार अपने पहले छह मैच जीत चुका है। अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला भारत-पाकिस्तान का रहा है। मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो फाइनल भी फीका पड़ जाता रहा है। लेकिन अब प्रतिद्वंद्विता वैसी नहीं दिखती। दर्शकों और प्रशंसकों में भी रोमांच पहले जैसा नहीं दिखता। विश्व कप 2023 में ही पाकिस्तान के साथ भारत की भिड़ंत नाम मात्र की रही। अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 117 गेंदें शेष रहते करारी शिकस्त दी।

व्यूअरशिप के लिहाज से भारत पाकिस्तान का मैच कल, आज और हमेशा ही सबसे बड़ा मैच रहेगा क्योंकि दोनों देशों में क्रिकेट में दर्शकों का आकर्षण भारी है और शायद यह खास तरह की भावनाओं को कुछ सहलाने का भी मौका बन जाता है। लेकिन, विश्लेषण करने पर पता लगता है कि मुकाबले अब एकतरफा होने लगे हैं। अब मैच के नतीजे के लिए 100 ओवरों तक नहीं, बल्कि 40 ओवरों तक ही इंतजार करना पड़ता है। निश्चित ही पाकिस्तान की टीम के खेल के स्तर में गिरावट आई है। आज पाकिस्तान टीम ऐसे खिलाड़ियों की तलाश में है, जो दिखावे की दुनिया से परे टीम को मैच जिताने का माद्दा रखते हों। साल 1992 से लेकर 2011 और कुछ हद तक 2015 विश्व कप तक भी...पाकिस्तान की टीम स्टार खिलाड़ियों से भरी रही है। जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सोहेल, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, मिस्बाह उल हक, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, यूसुफ योहाना अपने नाम के लिए नहीं बल्कि खेल और टेंपरामेंट के कारण जाने जाते थे। आज की पाकिस्तानी टीम कुछेक खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द घूमती है।

आज भारत की टीम को क्रिकेट के सभी प्रारूपों में विश्व की बेहतरीन टीमों में गिना जाता है तो इसका श्रेय भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के घरेलू क्रिकेट के बढ़िया ढांचे को जाता है। वीनू मांकड़ ट्रॉफी, कूचबिहार ट्रॉफी से लेकर रणजी, विजय हजारे और सैय्यद मुश्ताक अली टी20 प्रतियोगिता ने भारत को कई शानदार खिलाड़ी दिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग विश्व की सबसे बड़ी लीग है। कई विदेशी खिलाड़ी यह मानते हैं कि आईपीएल का दबाव किसी विश्व कप के जैसा ही होता है। पाकिस्तान में भी घरेलू प्रतियोगिताएं होती हैं लेकिन भ्रष्टाचार और धांधली चरम पर बताई जाती है। पैसों का अभाव भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथों को बांधकर रखता है। पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा संकट पैसों का अभाव है। पाकिस्तान की जीडीपी पस्त है। कुछ आतंकी और सियासी घटनाओं का असर यह भी हुआ कि भारत सहित अन्य देशों ने पाकिस्तान का दौरा करना बंद कर दिया। हालांकि, अब धीरे-धीरे टीमें वहां जाना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन, कम घरेलू मुकाबलों की वजह से कमाई हाथ नहीं लगती। बीसीसीआई आज सबसे अमीर बोर्ड है और इसका असर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और एशियन क्रिकेट परिषद (एसीसी) पर भी दिखता है। एशिया कप 2023 में मेजबान होने के बाद भी पाकिस्तान को भारत से मुकाबला खेलने के लिए श्रीलंका तक का सफर करना पड़ा। इसके पीछे भी बीसीसीआई की पावर छिपी है।

पाकिस्तान की टीम को अधिकतर जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ अधिक मुकाबले खेलने के लिए ट्रॉल किया जाता है। क्रिकेट के पंडित कहते हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जिम्बाब्वे या नेपाल जैसी टीमों के साथ तैयारी करते हैं, इसीलिए बड़े मुकाबलों में दबाव महसूस करते हैं। पाकिस्तान को हमेशा ही एक अप्रत्याशित टीम माना गया है, लेकिन इस टैग का नुकसान यही है कि टीम से हमेशा जीत की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अगर बेस्ट टीमों के खिलाफ जीतना है, तो बेस्ट के खिलाफ खेलना भी होगा। आप केवल रिकॉर्ड कायम करने के लिए कमजोर टीमों के साथ श्रृंखला नहीं खेल सकते।

● **आशीष नेमा**

अब तक के मुकाबले

1992 में सिडनी में खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर के 54 रन की मदद से 216 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 173 रन तक पहुंच सकी थी। 1996 में बेंगलूरू में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 रन बनाए। भारत की अच्छी गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान टीम नौ विकेट पर 248 रन बनाने में कामयाब रही। विश्व कप 1999 में मैनचेस्टर में हुआ। भारत ने छह विकेट पर 227 रन का छोटा स्कोर खड़ा किया। इस तरह पाकिस्तान की पारी 180 रन पर सिमट गई। 2003 में पाकिस्तान ने 273 रन का स्कोर बनाया लेकिन तेंदुलकर की 75 गेंद में 98 रन की पारी उस पर हावी रही। भारत की छह विकेट की जीत में युवराज सिंह ने भी नाबाद 50 रन बनाए। 2011 में भारत की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ी। इंडिया ने 260 रनों का स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तान भले 231 रन पर ऑल आउट हो गई। विश्व कप 2015 में एडिलेड में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 300 रनों का अच्छा स्कोर बनाया। जिससे पाकिस्तान 224 रन पर ढेर हो गया। 2019 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 336 रन बनाए, वहीं पाकिस्तान 40 ओवर में 212 रन बना सकी। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 191 रन बनाए। बुमराह, जडेजा, सिराज, हार्दिक और कुलदीप की गेंदबाजी के आगे कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका। भारत ने रोहित शर्मा की तूफानी पारी (86 रन, 63 गेंद) की बदौलत 30.3 ओवर में ही मैच जीत लिया।

जब काजोल ने हीरो का नाम सुनते ही छोड़ दी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई फ्लॉप

काजोल बॉलीवुड की वो टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत से अब तक ज्यादातर इंडस्ट्री को वो फिल्में दी हैं जिनकी कमाई से बॉक्स ऑफिस भी हिल गया था। लेकिन एक्ट्रेस ने करियर में कई ऐसी फिल्में भी रिजेक्ट की जो बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 2000 में भी उन्होंने एक हीरो का नाम सुनते ही फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।

साल 2000 में रिलीज हुई वो फिल्म कोई और बल्कि आमिर खान की फिल्म मेला है। इस फिल्म के लिए पहले काजोल को कास्ट किया गया था। इस बात का खुलासा खुद काजोल ने किया था कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि फिल्म के हीरो आमिर खान थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही जो आमिर खान का नाम सुनते ही उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी।

दरअसल, आमिर अपने हर

किरदार को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। अपने हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। इसी वजह से जब काजोल को ये फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने इसमें काम करने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वह जानती थी कि आमिर कई बार सीन के लिए रीटेक देते हैं और काजोल अपने सीन एक टेक में कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं।

साल 2000 में आई इस फिल्म को जब काजोल ने रिजेक्ट किया तो बाद में राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को ये रोल ऑफर किया गया था। फिल्म में आमिर के अपोजिट ट्विंकल खन्ना ने अपने किरदार से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन आमिर के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों ने पसंद नहीं की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी।

जब डायरेक्टर ने हेमा मालिनी से कर दी अजीब डिमांड, धर्मेंद्र ने सरेआम जड़ दिया था थप्पड़

हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी वह हिट फिल्म दे चुके हैं। लेकिन इंडस्ट्री में वह अपने शानदार काम के साथ-साथ अपने गुस्से को लेकर भी चर्चा में रहते आए हैं। साल 1981 में आई अपनी एक फिल्म के दौरान तो उन्होंने डायरेक्टर को ही थप्पड़ जड़ दिया था। बाद में किसी तरह सेट पर सभी ने बात संभाली थी। जानें कौन थे वो जाने माने डायरेक्टर।

बात साल 1981 में आई फिल्म क्रोधी की है जिसमें सुभाष घई ने पहले हेमा मालिनी को कास्ट किया था। उन्होंने एक सीन में हेमा को स्विमसूट पहनने को कहा लेकिन हेमा इस बात के लिए तैयार नहीं थीं। सुभाष घई ने कई बार उनको इस बात को लेकर रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वह नहीं मानीं। बाद में

उन्होंने सीन के लिए स्विमसूट पहन भी लिया। जैसे ही धर्मेंद्र को इस बात का पता लगा तो सेट पर पहुंचते ही उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया। उस वक्त सेट पर लोगों ने बाद में उनका गुस्सा शांत कराया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष घई एक्टर बनने ही आए थे। लेकिन जब दो फिल्में करने के बाद सफलता नहीं मिली तो उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया।

जब अमिताभ बच्चन की हीरोइन को सुनाई गई जेल की सजा, साउथ में भी मचाया धमाल

1970 से 1980 के दशक की हीरोइन ललिता रानी राव भारतीय सिनेमा का बड़ा नाम है और उन्हें लोग जया प्रदा के नाम से जानते हैं। 3 अप्रैल 1962 को जन्मी जया न सिर्फ एक अभिनेत्री बल्कि एक राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्हें 70 के दशक के अंत, 80 के दशक और 90 के दशक की शुरुआत में तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। लेकिन विवादों से अछूती वे भी नहीं और इसी साल के मिड में मामला इतना बढ़ गया था कि उन्हें 6 माह जेल की सजा भी सुनाई गई।

अगस्त 2023 में जया प्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने दोषी पाया है और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही अभिनेत्री पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। दरअसल, कोर्ट ने उनके

बिजनेस पार्टनर राम कुमार और राजा बाबू को भी दोषी पाया था, इसलिए उन्हें भी सजा सुनाई गई थी।

आपको बता दें कि जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर चलाती थीं, जिसे बाद में उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद उनके थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने जया के खिलाफ आवाज उठाई और उन पर वेतन और ईएसआई के पैसे का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया।

इस दशहरे पर भी नहीं मरा दशानन

सोटागुरु का खैनी बनाने का अंदाज ही जुदा है। उनकी अदा पर लाखों फिदा हैं। सोटागुरु के खैनी बनाने का अंदाज उस समय बेइंतहा हो जाता है जब सिर पर पगड़ी बधी हो और मूछे नागिन डांस करती हों। उनकी खैनीवाली अदा के लाखों दीवाने हैं। सोटागुरु कहते हैं अस्सी चुटकी नब्बे ताल, तब देखो खैनी की चाल। चौपाल पर सोटागुरु का खैनीडांस जब होता है तो कितने युवा मस्ती में खुद को खो बैठते हैं। वह जमीन पर होते हुए भी क्रूज की सैर कर आते हैं। सोटागुरु को देश-दुनिया की अच्छी जानकारी है। बस, उन्हें कोई छेड़ दे तो बात बन जाए।

खबरीलाल ने सोटागुरु को एक गंभीर खबर सुना कर आखिर छेड़ ही दिया। खबर सुनते ही सोटागुरु के चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगीं। वह धर्मसंकट में पड़ गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगते हुए इस खबर की अंतिम पुष्टि की इच्छा से पूछा। खबरीलाल क्या तुम सच कहत हौ। जी बिल्कुल! सोटागुरु, पक्की खबर है। अबकी दशहरे पर रावण ने हड़ताल कर दिया है। उसने प्रभु श्रीराम को व्हाट्सेप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेल के जरिए संदेश भेज दिया है कि अबकी दशहरे पर वह नहीं मरेगा। रावण ने लंका में इंटरनेशनल मीडिया की प्रेस बीफ भी बुलाकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। दुनिया भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। इस पर इहलोक और परलोक में डिबेट छिड़ गई है।

रामजी को भेजे संदेश में रावण ने साफ कहा है कि त्रेता से लेकर हम मरते-मरते कलयुग तक आ पहुंचे। पांच हजार साल से कलयुग में भी मरते आ रहे हैं। लेकिन हमने अब मुफ्त में मरने का इरादा छोड़ दिया है। रावण ने कहा है- कितनी बार मैं मरूंगा? युगों-युगों तक मरने का ठेका क्या हमी ने ले रखा है। पूरे देवलोक में इस खबर से खलबली मच गई है। जबकि इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि रामजी ने रावण की हड़ताल को जायज बताया है। उन्होंने कहा है कि रावण की हड़ताल बिल्कुल जायज और लोकतांत्रिक है। प्रभु की इस लोकतांत्रिक इच्छा से विष्णुलोक में खलबली मच गई है। जबकि रावण की लंका में इसे श्रीराम का समदर्शी न्याय बताते हुए मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है।

खबरीलाल ने सोटागुरु को बताया कि देवलोक की मीडिया इस खबर को युगांतकारी बताते हुए ब्रेकिंग चला रही है। सभी चैनल इस पर डिबेट कर रहे हैं। देव और दैत्यलोक के विश्लेषक अपने-अपने तरीके से इस पर डिबेट कर रहे है कि भविष्य में इसका क्या असर होगा। मीडिया में रामजी ने रावण के हड़ताल का समर्थन क्यों किया, इसकी वजह तलाशी जा रही है। देवलोक चाहता है कि प्रभु श्रीराम इसका स्पष्टीकरण दें। जबकि रावण की लंका में इस पर खूब जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन विभीषण परेशान हैं। आखिर यह सब हुआ कैसे।

सोटागुरु ने कहा- निशानेबाज तुमने यह खबर सुनाकर त्यौहार का मजा किरकिरा कर दिया। हमने सोचा था कि दशहरा करीब है और कोरोना चरसी नींद में है। अबकी सबकुछ अच्छे से मनेगा। लेकिन रावण ने तो होलियाना मूड में भांग पीकर फैसला सुना दिया। त्यौहारी और चुनावी मौसम में सोचा था कुछ खैरात का सरकारी गिफत मिल जाएगा। लेकिन भिया, रावण को क्या बोलें, वह तो रावण ठहरा। सोटागुरु, रावण कह रहा था कि डीजल, पेट्रोल और राई का तेल महंगा हो गया है। हमारे एक लाख पूत और सवालाख नाती बेकारी और बेगारी झेल रहे हैं। अनगिनत को मुए कोरोना ने लूट लिया। किसी तरह मुझे बख्श दिया है। फिर इस महंगाई के दौर में आखिर मुफत क्यों मरूं। जब सब कुछ बिक रहा है तो मेरी भी तो बोली लगनी चाहिए। आखिर दशहरा तो अपुन का टाइम है भाय। सरकार तो हर साल दशहरा और दिवाली पर अपने लोगों को बोनस और इंक्रीमेंट देती है। ऊपर से लोग काजू कतली का गिफ्ट भी पाते हैं। मुझे तो हर साल मुफत में मरने का भी बोनस नहीं मिलता।

सोटागुरु गंभीर चिंतन में चले गए। गहरी सांस लेते हुए कहा अब क्या होगा खबरीलाल। होगा क्या गुरु, अबकी ऊंट ने करवट बदल ली है। सूत्रों से खबर आई है कि देवलोक की अपातकाल मीटिंग में रामजी खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि रावण की बात जायज और लोकतांत्रिक है। उसने सच कहा है कि एक गुनाह की सजा उसे कितनी बार दी जाएगी। उसका कथन तर्कसंगत है कि प्रभु! हमने तो मां सीता का सिर्फ एकबार हरण किया था। जिसकी सजा में मुझे त्रेता से लेकर कलयुग तक मरना पड़ा। जबकि यहां तो हर रोज सीता का हरण होता है। रोज जलाई जाती हैं। चीरहरण आम बात है। मैं तो उस दौर में अकेला रावण था अब तो लाखों हैं जो मां सीता को रोज हरते हैं। हर गली, मोहल्ले, चौराहे और घर में हैं नाथ। फिर प्रभु, मेरे भी तो लोकतांत्रिक और मानवीय अधिकार हैं। अबकी दशहरे में मुझे माफ करो। प्रभु, पहले हर मन और घर में बैठे लाखों उस रावण को मारिए, फिर मुझ पर विचार करिए।

● **प्रभुनाथ शुक्ल**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है

कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की बृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है